R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-25

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 23 I अंक : 05
01 से 15 दिसम्बर 2024
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

विकास का सत्यानाश...

दिखाया पेरिस बनाने का ख्वाब
बूचड़खाने से भी बदतर भोपाल

राजधानी की सड़कें बदहाल, जनता परेशान, मंत्री-विधायक-अफसर अनजान

विकास में भेदभाव: टैक्स जनता से और माननीयों के क्षेत्र में सड़कें चकाचक

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

विकास

8 | निवेश के साथ रोजगार की...

मप्र में विदेश से निवेश लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 24 से 30 नवंबर तक ब्रिटेन और जर्मनी प्रवास पर रहे। मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. मोहन यादव की यह पहली विदेश यात्रा थी। यात्रा के बाद राजधानी...

डायरी

10-11 | सीएस ने दिलाई...

जैसे तैसे उप्र और मप्र की सरकारों की आपसी सहमति से केन-बेतवा लिंक को हरी झंडी मिल गई है, लेकिन इस परियोजना के तहत होने वाले निर्माण कार्यों की राह में रोड़ा ही रोड़ा है। सबसे बड़ा रोड़ा दोढन डैम का था। डैम के...

मप्र कांग्रेस

13 | अब संगठन की...

मप्र कांग्रेस की कार्यकारिणी के बाद अब पार्टी का फोकस संगठन की मजबूती और सक्रियता पर है। इसके लिए पार्टी ने फॉर्मूला बनाया है। जिसके तहत जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां फील्ड सर्वे के आधार पर की जाएंगी। नेताओं के बड़े...

समस्या

18 | ड्रग्स तस्करी का केंद्र बना मप्र

देश का हृदय प्रदेश मप्र ड्रग्स तस्करी का केंद्र बनता जा रहा है। पिछले कुछ सालों से मप्र को केंद्र बनाकर तस्कर यहां से ड्रग्स का काला कारोबार चला रहे हैं। पिछले दिनों मप्र में कई जांच एजेंसियों ने मिलकर भोपाल से 1800 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स का खुलासा किया था।

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

मप्र में डबल इंजन की सरकार विकास के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है। लेकिन जिन सड़कों को विकास का वाहक कहा जाता है वे सड़कें विकास का सत्यानाश कर रही हैं। प्रदेशभर की बात तो छोड़िए, राजधानी भोपाल की सड़कें इस कदर जर्जर, बदहाल हैं कि सड़कों पर गड्ढे नहीं, बल्कि गड्ढों में सड़कें समा गई हैं। जिसको देखकर लोग कहने को मजबूर हो रहे हैं कि भोपाल को पेरिस बनाने का सपना दिखाया गया, लेकिन यह तो बूचड़खाने से भी बदतर हो गया है।

राजनीति

30-31 | राहुल गांधी की कास्ट...

राहुल गांधी ने जातीय राजनीति की राह तो ठीक पकड़ी है, लेकिन जननायक की मंजिल अभी दूर है। ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के मामले में यूरेका मोमेंट पा लिया हो और कांग्रेस के वोटर से सीधे संवाद करने लगे हों। भाजपा के तीखे हमलों से बिलकुल बेअसर...

महाराष्ट्र

35 | मैनेजमेंट से जीत...

6 बड़ी पार्टियां और तकरीबन इतने ही छोटे दल। इनमें से महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित पवार) की तिकड़ी को चुना और विधानसभा चुनाव में महायुति को बहुमत दिया। तीनों पार्टियों ने 230 सीटों पर जीत हासिल की है। इस मैंडेट ने साफ कर दिया है...

बिहार

38 | जन सुराज ने सभी को डराया

चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर जिस जन सुराज के सूत्रधार हैं, वह चार सीटों के उपचुनाव से अपने चुनावी डेब्यू में जीरो पर रही। पार्टी के उम्मीदवार तीन सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे। एक सीट पर पार्टी चौथे स्थान पर रही। ऐसे प्रदर्शन के बावजूद...

6 -7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

पाक्षिक अक्स

वर्ष-23, अंक-05, पृष्ठ-48
1 से 15 दिसंबर, 2024

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com
W ebsite : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

प्रमुख संवाददाता

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल,
हर्ष सक्सेना-भोपाल,
दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,
विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,
ज्योत्सना यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,
टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहपुर,
अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,
इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता

पारस सरावगी (इंदौर)
09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर)
09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर)
098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन)
094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम)
089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा)
075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

अपनी बात

हत्या से 8 गुना अधिक मौत सड़क हादसों में

शा*यर मुसव्विर फिरोजपुरी का एक शेर है...*

जब हादसे ही हादसे अपना नसीब हैं
किस-किस पे रोए, आंख ये बरसे कहां-कहां

यह शेर देश में हो रहे सड़क हादसों पर सटीक बैठ रहा है। देश में सड़क हादसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वजह, ओवर स्पीड हो या रोड इंजीनियरिंग का फॉल्ट, सड़क हादसों में रोजाना औसतन 474 व्यक्ति मारे जा रहे हैं। सड़क हादसों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, जर्मनी और जापान सहित कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। भारत में हर रोज औसतन 1263 सड़क हादसे हो रहे हैं। प्रतिवर्ष होने वाले सड़क हादसों की बात करें तो यह संख्या चार लाख के पार चली जाती है। देश में साल 2023 में सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या को लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। राज्यों द्वारा केंद्र सरकार के साथ साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.73 लाख लोग मारे गए। इसका मतलब है कि हर दिन औसतन 474 लोगों की जान गई या लगभग हर तीन मिनट में एक मौत हुई। वहीं देश में रोजाना 78 हत्याओं के केस सामने आ रहे हैं। यानि हत्याओं से करीब 8 गुना अधिक मौतें सड़क हादसों में हो रही हैं। यह स्थिति तब है जब सरकार सड़क हादसों को रोकने के लिए तरह-तरह के इंतजाम कर रही है। कुछ साल पहले लागू हुए नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान राशि में कई गुना बढ़ोत्तरी की गई थी। मकसद था, सड़क हादसों में कमी लाना। लेकिन उसके बाद भी देश में प्रतिवर्ष 4 लाख से ज्यादा सड़क हादसे हो रहे हैं। सड़क हादसों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में भारत ने कई विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, जर्मनी और जापान सहित 19 देश शामिल हैं। सड़क हादसों को लेकर विकसित देशों में भारत के मुकाबले कानून कठोर हैं। साथ ही इन देशों में वाहन से लेकर रोड इंजीनियरिंग तक, इन सभी बातों पर गहराई से काम होता है। जबकि भारत में केवल कागजी योजनाएं और फॉर्मूला बनाए जाते हैं। देश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने अभी तक जितने भी प्रयास किए हैं, अगर उनका सही ढंग से क्रियान्वयन हो जाता तो हादसों में होने वाली मौतों की संख्या कम हो सकती थी। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण घायल होने वालों की संख्या किस तरह बढ़ रही है क्योंकि पिछले साल अधिकतम लगभग 4.63 लाख लोग घायल हुए थे, जो 2022 की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक था। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 1.68 लाख थी, जबकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 1.71 लाख थी। उप्र, महाराष्ट्र, मप्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम और तेलंगाना सहित कम से कम 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 2022 की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई, जबकि आंध्रप्रदेश, बिहार, दिल्ली, केरल और चंडीगढ़ जैसे राज्यों में मृत्यु दर में मामूली गिरावट आई। हैरानी की बात यह है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार ने जो कानून बनाया है, वह केवल चालान वसूली का केंद्र बना हुआ है। देखा यह जा रहा है कि पुलिस और यातायात विभाग के लोग सड़क पर खड़े होकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर केवल चालानी कार्यवाही करते हैं। लेकिन इसके लिए किसी को जागरूक नहीं किया जाता है। हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन वह केवल आयोजन तक ही सीमित रहता है। यही कारण है कि देश में सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं।

– राजेन्द्र आगाल

पत्र–संपादक के नाम

aksnews.com

जनता चुनेगी अध्यक्ष

मप्र में अब जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सीधे जनता से कराए जाएंगे। चुनावी प्रणाली और प्रक्रिया में जो बदलाव किया जाएगा उसमें दलीय आधार पर ही चुनाव होंगे। यह एक अच्छा कदम है। इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी। जो सरकार के लिए सही है।

● **उज्जवल राणा,** भोपाल (म.प्र.)

इंदौर की पहचान बढ़ेगी

कपड़ा मिलों की पहचान रहा इंदौर अब रेडीमेड गारमेंट का हब बनने जा रहा है। औद्योगिक विकास को साझा जिम्मेदारी मान रही मोहन सरकार प्रदेश में नए निवेश के लिए अवसर पैदा करने के साथ नई यूनिट्स के शिलान्यास पर फोकस कर रही है। इससे इंदौर की पहचान देशभर में और बढ़ेगी।

● **संजय साहू,** इंदौर (म.प्र.)

सौर ऊर्जा में मप्र अव्वल

प्रधानमंत्री मोदी की आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता का लक्ष्य 2047 तक भारत को ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र बनाना है। भारत वर्तमान में अपने तेल का 90 प्रतिशत और औद्योगिक कोयले का 80 प्रतिशत आयात करता है। आज मप्र सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में सिरमौर बन गया है।

● **शिल्पा दांगी,** बैतूल (म.प्र.)

पेयजल संकट से निजात

जल जीवन मिशन की योजना पहुंचने से वर्षों से बूंद-बूंद पानी को तड़पने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों की तकदीर बदल गई है। आज यहां हर घर में शुद्ध पेयजल का सपना पूरा हो रहा है। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की हर घर नल से जल योजना बुंदेलखंड क्षेत्र की नई कहानी बन गई है। जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना ने प्रदेश के बड़े क्षेत्र को पेयजल के बड़े संकट से निजात दिला दी है। हजारों गांवों में नल से घर-घर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू हो जाना इसका जीता जागता प्रमाण है। घर-घर नल से जल मिल रहा है। शुद्ध पानी मिलने से लोगों को बीमारियों से तो निजात मिली ही हैं, साथ ही पानी की उपलब्धता की समस्या भी दूर हो रही है।

● **प्रियांशु यादव,** सागर (म.प्र.)

मप्र में 2,82,700 करोड़ रुपए के निवेश

मप्र सरकार प्रदेश में निवेश के प्रयास कर रही है। मप्र में औद्योगिक विकास के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का जो फॉर्मूला शुरू किया है, उसका परिणाम भी दिखने लगा है। प्रदेश में जिस तेजी से निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं, उससे मप्र का औद्योगिक विकास मिसाल बनेगा। मप्र में पिछले 11 महीने में औद्योगिक विकास की नई लहर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में औद्योगिक विकास की जो पहल की है उसके परिणाम स्वरूप अब तक 2,82,700 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

● **जीवन सिंह,** जबलपुर (म.प्र.)

एलीफेंट कॉरिडोर फायदेमंद

उमरिया में 10 हाथियों की मौत के बाद मोहन सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने हाथियों के लिए एलीफेंट कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही बफर और कोर एरिया जोन भी बनाया जाएगा। इसके अलावा एलीफेंट टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी। मप्र में आने वाले समय में ऐसे वन क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिसमें हाथियों की बसाहट के साथ सहअस्तित्व की भावना मजबूत हो सके। इससे हाथियों की सुरक्षा में इजाफा होगा।

● **महक राजपूत,** ग्वालियर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

मंत्रिमंडल का विस्तार और दायित्वों की आस

उत्तराखंड की धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के लगभग ढाई बरस पूरे कर चुकी है, लेकिन राज्य के धाकड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी तक न तो अपने मंत्रिमंडल में खाली पड़े चार मंत्री पद भर पाए हैं और न ही विभिन्न निगमों, सरकारी प्रतिष्ठानों और समितियों में भाजपा नेताओं को दर्जाधारी पद देने के वे खास इच्छुक नजर आते हैं। देहरादून के सत्ता गलियारों में चर्चा गर्म है कि भाजपा के भीतर पद के दावेदारों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। कहा-सुना तो यह भी जा रहा है कि अब तक जितने भी दर्जाधारी पद धाकड़ धामी ने बांटे हैं, उनमें से अधिकतर पर नियुक्ति पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के करीबियों की ही हुई है। इसके चलते मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हैं कि वे अपने राजनीतिक गुरू कोश्यारी के दबाव में रहते हैं और उनके पसंद के भाजपा नेताओं को ही सरकारी तंत्र का हिस्सा बना रहे हैं। जानकारों का दावा है कि अब राज्य में निकाय चुनावों से पहले मुख्यमंत्री धामी न केवल मंत्री परिषद में बदलाव करने और उसका विस्तार करने का मन बना चुके हैं बल्कि बड़े स्तर पर भाजपा नेताओं को दर्जा पद भी देने जा रहे हैं। इस खबर के चलते मंत्रियों, विधायकों और भाजपा के नेताओं के मध्य भारी बेचैनी का माहौल गर्माने लगा है।

फिर कोपभवन में वसुंधरा

राजस्थान भाजपा में अंतर्कलह अपने चरम पर जा पहुंची है। भारी बहुमत के साथ राज्य की सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा तमाम प्रयास करने के बावजूद इस अंतर्कलह को न तो थाम पा रही है और न ही मीडिया में इसे चर्चा का विषय बनने देने से रोक पा रही है। हालांकि राजस्थान भाजपा के प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ऐसी किसी भी आंतरिक कलह को सिरे से खारिज करने का जी-तोड़ प्रयास जरूर कर रहे हैं लेकिन सात विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव से वसुंधरा राजे सिंधिया का दूरी बनाना इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री एक बार फिर से कोपभवन में जा बैठी हैं। गौरतलब है कि भाजपा ने वसुंधरा राजे को इन चुनावों में स्टार प्रचारक बनाया था, लेकिन वे कहीं भी प्रचार करने के लिए नहीं गईं। सूत्रों की मानें तो सिंधिया सही समय की प्रतीक्षा कर रही हैं। यदि संघ के दबाव को दरकिनार कर मोदी-शाह उन्हें नड्डा के स्थान पर भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाते हैं तो महारानी जल्द ही कोई बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकती हैं।

बैकफुट पर आप

बीते 10 वर्षों से दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी गहरे संकट में बताई जा रही है। दिल्ली के सत्ता गलियारों में नाना प्रकार की अफवाहें तैर रही हैं। कहा-सुना जा रहा है कि आतिशी सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत का मंत्री पद से त्याग पत्र और आम आदमी पार्टी से गुडबॉय तो मात्र ट्रेलर है, अभी कुछ और झटके लगने बाकी हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे गहलोत दरअसल आतिशी का मुख्यमंत्री बनना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। विधानसभा चुनाव से मात्र दो माह पूर्व उन्होंने सरकार और पार्टी से त्याग पत्र देकर न केवल केजरीवाल की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि नाना प्रकार के आरोपों से घिरी पार्टी भीतर चरम पर जा पहुंची अंतर्कलह को भी सार्वजनिक कर डाला है। खबर गर्म है कि आने वाले दिनों में पार्टी के कुछ विधायक और राज्यसभा के एक या दो सांसद भी त्याग पत्र देकर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी की पंजाब इकाई में भी भाजपा सेंधमारी करने जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने का दावा कर रही पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है।

बागी होते बिरेन सिंह

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह को हटाए जाने अथवा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की चर्चाओं का दौर दिल्ली के सत्ता गलियारों से बाहर निकल अब प्रदेश की राजधानी इम्फाल तक जा पहुंचा है। भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व लंबे अर्से से एन बिरेन सिंह की मजबूत पकड़ चलते कड़ा फैसला लेने से हिचकिचा रहा है। गत सप्ताह बिरेन सिंह ने यकायक ही विधायकों की बैठक बुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक तरह से चुनौती देने का काम कर दिखाया। 18 नवंबर को हुई इस बैठक में सत्तारूढ़ एनडीए के 45 विधायकों में से 27 विधयक मौजूद थे। इतना ही नहीं उनकी सरकार से समर्थन वापस ले चुकी एनपीपी पार्टी के 7 विधायकों में से 2 विधायक भी बैठक में शामिल हुए। 18 एनडीए विधायक जरूर इस बैठक में शामिल नहीं हुए। ये वही विधायक हैं जिन्होंने भाजपा आलाकमान को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को हटाने की मांग की है। सूत्रों की मानें तो बिरेन सिंह के तेवर खासे तल्ख थे।

पवार परिवार से त्रस्त भाजपा

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने कुछ बातें ऐसी कह डाली हैं जिनके चलते सवाल उठ रहे हैं कि कहीं भीतरखाने चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के मध्य कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही? इस आशंका को दो बातों ने बल देने का काम किया है। पहली बात उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे का अजित द्वारा खुला विरोध किया जाना है। जूनियर पवार ने इस नारे को सिरे से खारिज कर महायुति गठबंधन के भीतर बेचैनी पैदा करने का काम किया। अभी यह बेचैनी शांत भी नहीं हुई थी कि अजित दादा ने एक ऐसा रहस्योद्घाटन कर डाला जिसने भाजपा नेतृत्व को खासा असहज और शर्मिंदा करने का काम कर दिया है। बकौल अजित 2019 में जब चुनाव बाद सरकार गठन में गतिविरोध आया था तब उन्होंने एनसीपी के विधायकों को चाचा शरद पवार के कहने पर ही विद्रोह के लिए तैयार किया था और उनकी रजामंदी से ही भाजपा संग हाथ मिलाया था।

डांट के डर से बैक बेंचर बने...

अभी तक आपने बैक बेंचर शब्द स्कूल-कॉलेजों के संदर्भ में सुना होगा, लेकिन इन दिनों प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में दो अफसरों को बैक बेंचर कहा जा रहा है। ये दोनों अफसर आईएएस हैं। बताया जाता है कि ये दोनों तेजतर्रार अफसरों में गिने जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इन्हें फिसड्डी माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि ये दोनों अफसर प्रशासनिक मुखिया की डांट के डर से उनकी मीटिंग में सबसे पीछे बैठते हैं। जब इस मामले की पड़ताल की गई तो पता चला कि प्रदेश में जबसे नए प्रशासनिक मुखिया ने कमान संभाली है, मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों का चैन खो गया है। इसकी वजह यह है कि आए दिन बड़े साहब किसी न किसी अफसर की गलती पकड़कर उनको फटकार लगा देते हैं। सूत्र बताते हैं कि बड़े साहब की मीटिंग में जो दोनों आईएएस अधिकारी पीछे बैठ रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। बताया जाता है कि इनमें एक सचिव और दूसरे प्रमुख सचिव हैं। दोनों तेजतर्रार अफसरों में गिने जाते हैं, लेकिन बड़े साहब के सामने इनकी खामियां उजागर हो चुकी हैं। बताया जाता है कि लगभग हर मीटिंग में इनके पीछे बैठने की वजह को जानने के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने जब उनसे पूछ लिया कि आखिर क्या वजह है कि आप लोग पीछे ही बैठ रहे हो? इस पर इन दोनों अफसरों ने कहा कि आप तो एसीएस बन गए हो, डांट तो हमें पड़ती है। ऐसे में यही रास्ता सूझा है।

जिसे काम बिगाड़ना हो, मेरे पास आए

शीर्षक पढ़कर आप भी आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, लेकिन इन दिनों इसकी चर्चा प्रदेश की राजनीतिक वीथिका में खूब हो रही है। दरअसल, प्रदेश सरकार के एक बड़े विभाग के मंत्री और बड़ी राजनीतिक हैसियत रखने वाले एक माननीय ने गत दिनों ये बातें अपने क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान कही हैं। सूत्रों का कहना है कि माननीय के पास भले ही बड़ा विभाग है, लेकिन उनकी तनिक भी नहीं चल रही है। इससे माननीय इस कदर आहत हैं कि किसी न किसी बहाने कैबिनेट की बैठक से भी दूर रह रहे हैं। हालांकि उनके नजदीकियों का कहना है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कारण माननीय कैबिनेट की बैठकों में शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन लगातार पांच कैबिनेट बैठकों से दूर होना इस बात का संकेत है कि माननीय नाराज चल रहे हैं। यही नहीं सूत्र बताते हैं कि अपने क्षेत्र के सबसे कद्दावर नेता ये माननीय इस बात से भी आहत हैं कि उनके क्षेत्र में प्रदेश के एक अन्य बड़े नेता अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। इसको देखते हुए माननीय अपनी धाक और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। वहीं उन्होंने सबको सचेत कर दिया है कि कोई भी उनके पास काम कराने के लिए न आए। अगर वह ऐसा करता है तो उसका काम होने की बजाय बिगड़ जाएगा। इसके पीछे शायद माननीय का मंतव्य यह है कि सरकार में उनकी तनिक भी नहीं चल रही है।

पुलिस देर से ही आती है...

पुलिस के बारे में यह ख्यात है कि वह कहीं भी देर से आती है। इस तथ्य पर गत दिनों उस समय मुहर लग गई, जब प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री निर्धारित कार्यक्रम में पहुंच गए, लेकिन उनके विभाग में पदस्थ बड़े साहब जो पुलिस विभाग के हैं, देर से पहुंचे। दरअसल, गत दिनों युवाओं से संबंधित विभाग द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उस कॉन्फ्रेंस को विभागीय मंत्री के साथ ही विभाग के बड़े साहब को भी संबोधित करना था। आयोजन स्थल पर सब लोग समय से पहुंच गए। विभाग के अन्य अधिकारी आयोजन स्थल पर सारी तैयारियां कर मंत्री और बड़े साहब का इंतजार कर रहे थे। प्रोटोकॉल के अनुसार अधिकारी को समय पर और मंत्री से पहले पहुंचना था, लेकिन हुआ इसके विपरीत। सूत्र बताते हैं कि मंत्रीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने नियत समय पर पहुंच गए, लेकिन साहब का कोई अता-पता ही नहीं था। मंत्रीजी के पहुंचते ही विभाग के अफसर भी साहब की खोज-खबर में जुट गए, लेकिन साहब ठहरे अपनी मर्जी के मालिक। इसलिए वे मंत्रीजी के पहुंचने के थोड़ी देर बाद कार्यक्रम में पहुंचे। साहब जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे, वहां उपस्थित लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई कि देखा, पुलिस देर से ही आती है। इस परंपरा को एडीजी स्तर के इस अधिकारी ने भी कायम रखा है।

इस ओर कब होगी नजर?

आने वाले दिनों में आईएएस अधिकारियों की मीट होने वाली है। इस मीट में प्रदेशभर के आईएएस अधिकारी और उनके परिजन खेलकूद सहित अन्य गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। यानि मनोरंजन करेंगे। लेकिन इस आयोजन के पीछे की कहानी हैरान करने वाली है। सूत्रों का कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था के सबसे बड़े ओहदे वालों की इस मीट का खर्चा व्यापारियों और कारोबारियों से वसूला जाता है। यानि यह संस्था इतनी गरीब है कि इसके आयोजन के लिए प्रदेशभर के व्यापारियों और कारोबारियों पर दबाव बनाकर बैनर-पोस्टर की आड़ में मोटा चंदा लिया जाता है। इस चंदा वसूली के लिए एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा जिलों में पदस्थ कलेक्टर, निगम आयुक्तों और अन्य आईएएस अफसरों को टारगेट दिया जाता है। टारगेट मिलते ही अफसर वसूली अभियान में जुट जाते हैं। बताया जाता है कि यह वसूली कायदे-कानून का डर दिखाकर की जाती है। अब सवाल है कि प्रशासनिक व्यवस्था की खामियों को दूर करने में लगे बड़े साहब की नजर इस ओर कब पड़ेगी?

बंदरबाट... पूर्व मंत्री परेशान

पिछली सरकार में खनिज संपदा के रक्षक के रूप में मालदार विभाग की कमान संभालने वाले एक पूर्व मंत्री इस कदर परेशान हैं कि वे अजब-गजब हरकतें करने लगे हैं। इस संदर्भ में जानकारों का कहना है कि साहब जब मंत्री थे तो वे और उनके ओएसडी, दोनों मिलकर चारों हाथों से जमकर माल कूट रहे थे। विभाग की लक्ष्मी उगाही का पूरा दारोमदार ओएसडी पर ही था। यही नहीं, माल लाने से लेकर उसके बंटवारे तक की जिम्मेदारी ओएसडी को ही थी। लेकिन प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद भी अभी तक लाखों रुपए की एक बड़ी पेमेंट जो पार्टी फंड में जानी थी, वह नहीं पहुंच पाई है। वर्तमान सरकार में उक्त पूर्व मंत्री को जगह नहीं मिली है, लेकिन उन पर उस राशि के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसको देखते हुए गत दिनों मंत्रीजी और उनके बेटे ने ओएसडी के घर पर धावा बोल दिया। लेकिन ओएसडी ने कहा कि जिस व्यापारी के यहां से पैसा आना था, वह फोन नहीं उठा रहा है। पूर्व मंत्री ने भी उक्त व्यापारी को फोन लगाया तो उसने फोन नहीं उठाया। हालांकि उक्त पूर्व मंत्री का मानना है कि व्यापारी नहीं बल्कि ओएसडी ही पैसा खा गया है।

निवेश के साथ रोजगार की बहार

मप्र में विदेश से निवेश लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 24 से 30 नवंबर तक ब्रिटेन और जर्मनी प्रवास पर रहे। मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. मोहन यादव की यह पहली विदेश यात्रा थी। यात्रा के बाद राजधानी भोपाल में उन्होंने जिस उत्साह और जिस अंदाज से यात्रा की सफलता के संस्मरण सुनाए उससे यह साफ झलक रहा था कि प्रदेश में निवेश के साथ ही रोजगार की बहार आने वाली है। मुख्यमंत्री ने एक आम आदमी की तरह अपनी 6 दिनी यात्रा का संस्मरण सुनाया और इस दौरान वे कई बार भाव-विभोर भी हो गए। उद्योग वर्ष 2025 में प्रदेश में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने 6 दिवसीय विदेश यात्रा के दौरान दोनों देशों के उद्योगपतियों और निवेशकों को मप्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि, लंदन और जर्मनी की यात्रा के दौरान संतोषजनक निवेश आया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने जानकारी देते हुए बताया कि, जर्मनी से 18 हजार करोड़ के निवास के प्रस्ताव मिले हैं और यूके से 60 हजार करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि, संभागों के अंदर रीजनल इन्वेस्टर समिट हो रही है। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि, हमें दुग्ध उत्पादन से लेकर आईटी सेक्टर को आगे बढ़ाना है। विदेश में हमने हर क्षेत्र के निवेश के लिए काम किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 30 नवंबर को अपनी 6 दिवसीय लंदन और जर्मनी की यात्रा से भोपाल लौटे। विदेश यात्रा से लौटने पर मुख्यमंत्री निवास में पत्रकारवार्ता में उन्होंने कहा कि अभी की मेरी यूके और जर्मनी की यात्रा को मैं 2014 से जोड़ रहा हूं। 2014 से पहले आर्थिक व्यवस्था में भारत का नंबर 11वां था, लेकिन 2014 में मोदीजी ने इंग्लैंड को पीछे कर दिया। इसके बाद हम 5वें नंबर पर आ गए और इंग्लैंड 6वें नंबर पर आ गया। लेकिन हमें यही नहीं रुकना है, हमें कोशिश करते रहनी है और अब तीसरे स्थान पर पहुंचना है। डॉ. मोहन यादव ने कहा, केवल संभाग ही नहीं एक-एक जिले की प्रगति का हमने संकल्प लिया है और हमारी सरकार इसी हिसाब से काम कर रही है, जब सब तरक्की करेंगे तभी प्रदेश तरक्की करेगा, उन्होंने बताया कि इस दौरे में हमने एक-एक मिनट का उपयोग प्रदेश की बेहतरी के लिए किया है। उन्होंने कहा कि मप्र की प्रगति के लिए जो प्लान हमने बनाया था हमको उसका रिस्पॉन्स भी वहां से वैसा ही मिला, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि मप्र में योग्यता, क्षमता, प्राकृतिक संसाधन किसी की कोई कमी नहीं है, और इस भरोसे पर दुनिया में रोजगार के जहां भी अवसर मिलेंगे वहां मप्र सबसे पहले खड़ा दिखाई देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से संपन्न बनकर ही हम मप्र का भला कर सकते हैं, हम अपने युवाओं की इच्छाओं को पंख देकर उन्हें उड़ान भरने का अवसर दे सकते हैं। उन्होंने कहा- हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से संभाग स्तर पर रोजगार के अवसर जुटाए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लंदन में खासतौर पर माइनिंग सेक्टर, हेल्थ, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे सेक्टर में प्रस्ताव मिले हैं। जर्मनी ने हेल्थ और फार्मास्यूटिकल में दिलचस्पी दिखाई है। सिर्फ एक जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी से ही 3000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है। वहां से ही जमीन आवंटन की मंजूरी उन्हें दे दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि भोपाल के अचारपुरा में जर्मनी की कंपनी 100 करोड़ रुपए निवेश करेगी। जब हम लोग अयस्क की बात कर रहे थे, तब मिस्टर औद्योगिक घराने ने कहा कि हम बड़े स्तर पर निवेश करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने बताया कि दोनों देशों की यात्रा के नतीजे बेहद सकारात्मक रहे। यात्रा उपलब्धियों से भरी रही। अगले साल भोपाल में होने वाले ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के लिए ये दौरा काफी अहम रहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि यूके में उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों ने मप्र प्रवासियों के साथ जुड़ने पर अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने राज्य के शिक्षित और कुशल युवाओं को क्वालिटी एजुकेशन और जॉब देने की पेशकश की। साथ ही आर्थिक समृद्धि में योगदान करने के लिए राज्य के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से विकसित मप्र के लिए यूके और जर्मनी का निवेश संबंधी मेरा प्रवास सफल रहा। दोनों देश के उद्यमी पूंजी निवेश के साथ तकनीक के क्षेत्र में भी मप्र में आने को लेकर उत्साहित हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मप्र में क्षमता, योग्यता, प्राकृतिक संसाधन और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं।

● **कुमार राजेंद्र**

इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने बताया कि मप्र को एक ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटर के रूप में स्थापित करने के लिए की गई यूके की यात्रा से राज्य के लिए बहुक्षेत्रीय निवेश के अवसर खुले हैं, जिनसे रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यूके के किंग्स क्रॉस अर्बन रीजुवनेशन प्रोजेक्ट का भ्रमण कर शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं को समझने और मप्र में इसी तरह की परियोजनाओं पर काम करने के लिए उपयोगी जानकारी मिली। साथ ही वार्विक मैन्युफेक्चरिंग ग्रुप का भ्रमण कर ऑटोमोबाइल क्षेत्र के एक्स्पर्ट्स से प्रदेश की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए धार जिले के पीथमपुर में निर्मित ऑटो टेस्टिंग ट्रैक में डब्ल्यूएमजी के साथ मिलकर कार्य करने की योजना पर भी चर्चा हुई। बीईएम लिमिटेड ने मॉड्यूलर हॉउसिंग प्रोजेक्ट में 1,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए प्रस्ताव दिया है। बुनियादी ढांचे के विकास, आधुनिक परिवहन प्रणाली, ऑटोमोबाइल सेक्टर हेतु एवं अन्य परियोजनाओं जैसे स्मार्ट सिटी और आवासीय सुविधाओं पर भी विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि यूके और जर्मनी की यात्रा टेक्नो-फ्रेंडली युवाओं के लिए रोजगार सृजन के बेहतर अवसर लेकर आई है। यूके और जर्मनी द्वारा प्रदेश में निवेश करने से तकनीकी संस्थानों में उन्नत टेक्नोलॉजी आएगी। इससे एक ओर जहां हमारे युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के संस्थानों को वैश्विक स्वरूप मिलेगा। यूके की वार्विक यूनिवर्सिटी का भ्रमण कर चर्चा की गई कि शिक्षा और कौशल क्षेत्र में इनोवेटिव स्किल डेवलपमेंट को मप्र के युवाओं के लिए कैसे उपयोगी बनाया जाए।

सुशासन पर जोर

कानून व्यवस्था स्थिति रहे सुदृढ़

मुख्यमंत्री ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर अवैध मादक पदार्थ जब्त किए जाएं। अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए। विशेष अभियान संचालित कर नशे का व्यापार करने वाले अपराधियों की धरपकड़ की जाए। युवाओं को नशामुक्ति अभियान से जोड़कर जागरूक बनाया जाए। शिक्षण संस्थाएं भी ऐसे प्रयास करें। नशे की वस्तुओं की सप्लाई चेन पर नियंत्रण हो। अन्य राज्यों से भी संपर्क और संवाद कर नशे की वस्तुओं पर अंकुश लगाया जाए। खांसी के विभिन्न सीरप जो नशे के विकल्प के तौर पर उपयोग में लाए जा रहे हैं उन पर भी नियंत्रण किया जाए। पुलिस की निगाह ऐसी गतिविधियों पर होनी चाहिए, विशेष कर औद्योगिक क्षेत्रों में इसे रोकने की विशेष आवश्यकता है। दवा की दुकानों की भी रैंडम रूप से चेकिंग कर इस पर नियंत्रण किया जाए। गौ-तस्करों पर तत्काल एक्शन हो। आदतन अपराधियों के विरूद्ध और साइबर क्राइम पर भी नियंत्रण स्थापित किया जाए। पुलिस की कार्रवाई से अपराधिक तत्व बचना नहीं चाहिए। त्यौहारों के अवसर पर विशेष सतर्कता बरती जाए। वीसी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने बताया कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में होम-स्टे लोकप्रिय हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे शीघ्र ही अलीराजपुर, धार या अन्य किसी जनजातीय बहुल जिले में संचालित होम-स्टे में रात्रि विश्राम करेंगे। मप्र के होम-स्टे में ख्यात व्यक्तियों और सिने जगत की हस्तियों को भी आमंत्रित कर प्रदेश की पहचान को देश में स्थापित किया जाएगा।

मप्र में सुशासन के मंत्र को आत्मसात कर सरकार चला रहे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की शिक्षा, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण प्राथमिकताएं हैं, जिस पर लगातार काम हो रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार विभागवार समीक्षा भी करते रहते हैं। वे इस बात पर गहराई से ध्यान देते हैं कि योजनाओं और घोषणाओं से परे आमजन की छोटी-छोटी समस्याओं के निराकरण समयावधि में हों। जो नियम सरकार ने बनाए हैं, उनका लाभ आमजन को समय पर मिले। इसके लिए वे नियमों के पालन करवाने के लिए जिम्मेदार तंत्र को लगातार सजग करते रहते हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्र के कभी भी कहीं भी इस्तेमाल पर रोक लगाने संबंधी आदेश तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीते वर्षों में दिए जा चुके थे, लेकिन इनका पालन करवाने की इच्छाशक्ति नहीं होने की वजह से जनता अब तक ध्वनि प्रदूषण की पीड़ा भोग रही थी। मोहन सरकार ने इच्छाशक्ति दिखाई वैसे ही जनता को राहत मिलना शुरू हो गई। जन की ऐसी कई आकांक्षाएं-समस्याएं हैं, जो अगले वर्षों में वे मोहन सरकार के माध्यम से हल होते या पूरा होते देखेंगे। सरकारी सुविधाएं धीरे-धीरे अंतिम व्यक्ति तक पहुंच भी रही हैं, लेकिन इसकी गति सही रहे और विस्तार सही तरीके से हो इसकी निगरानी मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं।

इसका ताजा उदाहरण यह है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कानून-व्यवस्था और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर 22 नवंबर को कलेक्टर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति आदर्श होनी चाहिए, इसके लिए कलेक्टर और एसपी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। अगर किसी जिले से गड़बड़ी या अनियमितता की शिकायतें मिलती हैं, तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे उच्चाधिकारी ही क्यों न हों। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 22,000 थानों की सीमाओं में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं। जनकल्याण की दृष्टि से जिलों के पुनर्गठन के लिए राज्य शासन ने आयोग का गठन किया है। इसमें कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों को आवश्यक सुझाव देने के लिए कहा गया है। आगामी समय में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण और आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने जैसे निर्णय लागू किए जाएंगे। इस दृष्टि से प्रशासनिक कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए हम पूरी तरह कटिबद्ध हैं। कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर और कमिश्नर को पुलिस और प्रशासन में कसावट लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में कलेक्टर और एसपी विकास और कानून व्यवस्था के कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। नियम विरूद्ध कार्यों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करें। इसके लिए उच्च स्तर से निर्देश की प्रतीक्षा न करें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खाद और बीज वितरण, धान व सोयाबीन खरीदी, नरवाई और पराली प्रबंधन, मिलावटखोरी रोकथाम समेत अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बताया कि 10 दिसंबर तक हम होंगे कामयाब अभियान चलाया जा रहा है, इसमें जेंडर आधारित हिंसा को रोकने के लिए जागरूकता गतिविधियां होंगी। अभियान पुरुषों पर आधारित कर पुरुषों के दायित्व को माताओं और बहनों को सुरक्षा का भाव दिलवाने के लिए निर्धारित किया गया है। पुरुष वर्ग अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाकर महिलाओं के विरूद्ध हिंसा रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वाहनों में पैनिक बटन के उपयोग से भी महिलाओं के सम्मान को प्रभावित करने के मामलों पर नियंत्रण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर और एसपी विशेष ध्यान दें। परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में चाहे विकास का प्रश्न हो, शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन या कानून-व्यवस्था की बात हो, आदर्श स्थिति बनाए रखने का दायित्व कलेक्टर-एसपी का है। अपने जिले में सभी व्यवस्थाओं के लिए कलेक्टर्स और एसपी जिम्मेदार होंगे। जिन जिलों से अनियमितताओं की शिकायतें आएंगी, वहां बड़े अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में जन-कल्याण की दृष्टि से जिलों के पुनर्गठन के लिए राज्य शासन ने आयोग गठित किया है। इसमें कलेक्टर और जन-प्रतिनिधि भी जरूरी सुझाव देकर सहयोग करें। आने वाले समय में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण, आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने जैसे निर्णय क्रियान्वित होंगे। इस दृष्टि से अनेक प्रशासनिक कार्यों का सह संबंध रहेगा। जिलास्तर पर भी जन-कल्याण के साथ प्रशासनिक सुधार प्राथमिक कार्य है।

● **कुमार विनोद**

सीएस ने दिलाई लंबी परियोजना की अनुमति...

जैसे तैसे उप्र और मप्र की सरकारों की आपसी सहमति से केन-बेतवा लिंक को हरी झंडी मिल गई है, लेकिन इस परियोजना के तहत होने वाले निर्माण कार्यों की राह में रोड़ा ही रोड़ा है। सबसे बड़ा रोड़ा दोढन डैम का था। डैम के निर्माण का टेंडर पिछले 6 माह से जलशक्ति मंत्रालय में फंसा हुआ था। मंत्रालय इसे दबाकर बैठा था। ऐसे में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस प्रोजेक्ट को अनुमति दिलाने का बीड़ा उठाया। इसके लिए उन्होंने जलशक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखी, फिर 21 नवंबर को दिल्ली में आयोजित बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार में रहते अपने अनुभवों और संबंधों के आधार पर लाइनअप कर दोढन बांध निर्माण की अनुमति ले ली। मुख्य सचिव ने इस परियोजना को अनुमति दिलाकर यह दर्शा दिया है कि प्रदेश में अब कोई भी योजना केंद्र में नहीं अटकेगी।

मुख्य सचिव का प्रस्ताव पतने-ब्यावरामा दमोह-पन्ना की नदी का 2.5 लाख हेक्टेयर का प्रस्ताव दिया है, जबकि पहले यह प्रस्ताव 90 हजार हेक्टेयर का था। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत पतने-ब्यावरामा 2.5 लाख हेक्टेयर का लंबे दिनों से प्रयास किया जा रहा था। जिसकी स्वीकृति की दिशा में यह पहला कदम है। दरअसल, सूत्रों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए एक ठेकेदार ने 22 फीसदी नीचे का टेंडर डाला था। ऐसे में इंतजार किया जा रहा था कि कोई दूसरा ठेकेदार भी आए, लेकिन कोई नहीं आ पाया। ऐसे में उसी को टेंडर आवंटित कर दिया गया। गौरतलब है कि मुख्य सचिव अनुराग जैन की दिल्ली सरकार और पीएमओ में अच्छी पैठ है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अपनी पसंद का होने के कारण उन्हें मप्र का मुख्य सचिव बनाया है। ऐसे में प्रदेश में विकास योजनाओं में शायद ही कोई बाधा उत्पन्न हो, क्योंकि मुख्य सचिव दोनों सरकारों के बीच समन्वय बनाने में सफल रहेंगे। इसका प्रमाण दोढन बांध के निर्माण की अनुमति से मिल गया है। गौरतलब है कि केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर मप्र और उप्र के बीच वर्ष 2005 में अनुबंध हुआ था। उसके बाद प्रक्रिया धीमी पड़ गई थी। तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों राज्यों के बीच वर्ष 2021 में समझौता हुआ। परियोजना पूरी होने के बाद मप्र और उप्र में साढ़े आठ लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई क्षमता का विकास होगा तो लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी। केन-बेसिन से उप्र के 2.27 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, केन-बेसिन से मप्र में 4.51 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होगी, जबकि बेतवा बेसिन से मप्र में सिंचाई का क्षेत्रफल 2.06 लाख हेक्टेयर होगा और बिजली मप्र के हिस्से में आएगी। सूत्र बताते हैं कि मुख्य सचिव ने जलशक्ति मंत्रालय के अफसरों के सामने इस परियोजना की ऐसी तस्वीर रखी जिससे कोई भी कुछ बोल नहीं पाया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना से मप्र में 6 हजार हेक्टेयर जमीन डूब क्षेत्र में आएगी। वहीं विस्थापन की भी जिम्मेदारी हमारी है। ऐसे में केंद्र सरकार पर मात्र 10 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मुख्य सचिव द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के बाद केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने दोढन बांध निर्माण की अनुमति दे दी है।

मप्र में 1 जनवरी से ई-ऑफिस

प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाने के लिए 1 जनवरी 2025 से ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है। इसकी शुरूआत मंत्रालय से होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को इसके लिए तैयार रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि सरकार ने 7 साल पहले भी मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की थी, कुछ दिन ही ई-ऑफिस पर नस्तियां चलीं। तब से लेकर पुराने ढर्रे पर ही काम हो रहा है। उसी समय उप्र, तेलंगाना, केरल, दिल्ली समेत अन्य राज्यों ने भी ई-ऑफिस प्रणाली को लागू किया था। इन राज्यों में पूरा सरकारी कामकाज इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ गया। जबकि मप्र प्रशासनिक इच्छाशक्ति के अभाव में ई-ऑफिस प्रणाली में 7 साल पिछड़ गया है। अब नए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने एक महीने के भीतर ही ई-ऑफिस प्रणाली को सख्ती से लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। नए मुख्य सचिव जैन के पदभार ग्रहण करने के बाद संभावना जगी है कि अब पहले मंत्रालय के विभागों में इसके बाद प्रदेशभर में ई-ऑफिस प्रणाली पर काम शुरू हो जाएगा। जीएडी ने अभी 7 नवंबर 2024 को सभी विभाग के एसीएस, पीएस व सचिवों को पत्र भेजकर 2018 से लेकर 2023 तक के पत्रों का हवाला देकर इस बार काम शुरू कराने को कहा है। प्रथम चरण में एक जनवरी 2025 से ई-ऑफिस प्रणाली लागू किया जाना है। एक जनवरी से नस्तियां इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही भेजी जाएंगी।

अब सालभर ट्रांसफर नहीं

मप्र में अधिकारी-कर्मचारी ट्रांसफर की आस लगाए हैं, लेकिन आजकल-आजकल करते हुए लगभग एक साल से तबादलों पर से बैन नहीं हट पाया है। अब प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य सचिव अनुराग जैन के हाथों में है। ईमानदार और कड़क छवि वाले मुख्य सचिव ने आते ही ट्रांसफर की व्यवस्था में बदलाव करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव का मानना है कि प्रदेश में साल में एक ही बार ट्रांसफर हो। इसलिए उन्होंने अघोषित तौर पर तबादलों पर रोक लगा रखी है। उधर, तबादलों पर रोक लगने के कारण मंत्री और विधायक परेशान हैं। जानकारों का कहना है कि तबादले को मंत्री और विधायक अपना अधिकार समझते हैं। वे विभागीय और क्षेत्रीय स्तर पर तबादले करवाकर अपनी राजनीतिक हैसियत मजबूत करते हैं। लेकिन पिछले 11 महीने के दौरान मंत्रियों और विधायकों की तबादलों में एक नहीं चली है। प्रदेश में जो भी तबादले हो रहे हैं, वह मुख्यमंत्री स्तर पर हो रहे हैं। ऐसे में मंत्रियों और विधायकों की पूछ-परख कम हो रही है।

प्रमोशन तबादले साथ-साथ

प्रदेश में तबादलों पर बैन की एक वजह यह भी है कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के प्रकाशन के मद्देनजर मैदानी अफसरों के तबादले पर रोक लगा रखी है। ऐसे में माना जा रहा है कि जनवरी में तबादलों पर से बैन हटाया जा सकता है। उसी दौरान पुलिस विभाग में आईपीएस अफसरों का प्रमोशन भी होना है। ऐसे में प्रमोशन के साथ ही उनके तबादले किए जाएंगे।

शर्तों पर मकवाना बने डीजीपी...

1988 बैच के आईपीएस अधिकारी कैलाश मकवाना प्रदेश के 32वें डीजीपी होंगे। 1 दिसंबर को वह यह पद ग्रहण करेंगे। वहीं वर्तमान डीजीपी सुधीर सक्सेना 30 नवंबर को रिटायर हो गए। सुधीर सक्सेना ने मार्च 2020 में डीजीपी के रूप में पदभार संभाला था। कैलाश मकवाना के पास कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रही हैं, जिनमें मप्र पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन के चेयरमैन का पद भी शामिल है। सूत्रों का कहना है कि मकवाना को शर्तों पर डीजीपी बनाया गया है। यानि जब केंद्र से डीजीपी के लिए 3 नामों की सूची आई तो उसमें कैलाश मकवाना को प्राथमिकता देने का भी निर्देश था। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच तकरीबन 6 घंटे बैठक हुई। उसके बाद जब मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पर जा रहे थे तो एयरपोर्ट पर उन्होंने कैलाश मकवाना के साथ आधे घंटे तक चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर उनके साथ बात की। मुख्यमंत्री ने यह संदेश भी दिया कि समन्वय बनाकर काम करने की जरूरत है। दरअसल, मकवाना की साफगोई और स्पष्टवादिता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।

बैचमेट ने की सिफारिश

बताया जाता है कि जब 9 आईपीएस अधिकारियों के नाम का पैनल मप्र से यूपीएससी को भेजा गया तो उसमें से वरिष्ठ 3 आईपीएस अफसरों का पैनल तय हुआ। इसी दौरान आईबी में पदस्थ एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने मोर्चा संभाला और कैलाश मकवाना को मप्र का डीजीपी बनाने की सिफारिश की। उक्त अधिकारी असम कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और उनकी पीएमओ में अच्छी छवि है। उनकी विश्वसनीयता को देखते हुए पीएमओ ने कैलाश मकवाना को डीजीपी बनाने की अनुमति दी। बताया जाता है कि उक्त आईपीएस अधिकारी कैलाश मकवाना के बैचमेट तो हैं ही साथ ही रूम पार्टनर भी थे। ऐसे में दोनों अधिकारियों के बीच अच्छी छनती है। गौरतलब है कि कैलाश मकवाना का अकादमिक बैकग्राउंड भी मजबूत है। उज्जैन के रहने वाले कैलाश मकवाना ने मैनिट भोपाल से बीई किया है और आईआईटी दिल्ली से एमटेक की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने कई प्रमुख पोस्टों पर कार्य किया है, जिनमें अति संवेदनशील क्षेत्रों में काम करने का अनुभव शामिल है। उन्होंने दुर्ग, मुरैना, जबलपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, मंदसौर और सागर जैसे विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अलावा, वह इंटेलीजेंस विभाग में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे हैं। कैलाश मकवाना को तेज-तर्रार और मेहनती अफसर माना जाता है। उन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। शिवराज सरकार के कार्यकाल में वह लोकायुक्त के डीजी के रूप में नियुक्त हुए थे, लेकिन महज छह महीने बाद उनका तबादला कर दिया गया। उनके कार्यकाल में लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कई ठंडे बस्ते में पड़ी फाइलें खोलीं और महत्वपूर्ण जांचों को आगे बढ़ाया। उन्होंने पद संभालते ही आईएएस, आईपीएस के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। ठंडे बस्ते में पड़ीं पुराने मामलों की फाइल खोलकर कई आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की। उन्होंने महाकाल लोक कॉरिडोर की जांच भी शुरू कर दी थी। अधिकारियों के साथ ही सरकार भी थर्रा उठी और कैलाश मकवाना को वहां से जल्द ही हटा दिया गया। इतना ही नहीं, आईपीएस कैलाश मकवाना की एसीआर (गोपनीय चरित्रावली) भी खराब कर दी गई। उन्होंने अपने एसीआर (गोपनीय चरित्रावली) सुधरवाने के लिए मप्र शासन से 9 महीने पहले अपील की थी। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजते हुए सरकार से कहा था कि लोकायुक्त संगठन में डीजी रहने के 6 महीने के दौरान उनकी एसीआर खराब कर दी गई। दुर्भावनापूर्वक खराब की गई एसीआर पर शासन को उचित निर्णय लेना चाहिए। डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने के कुछ महीने पहले ही वरिष्ठ सचिवों की कमेटी ने इसे दुरुस्त कर दिया था। मुख्यमंत्री ने उन्हें 10 में से 10 नंबर दिया। मकवाना को हर स्तर पर काम करने का अनुभव है। यही नहीं उनकी कार्यप्रणाली हमेशा एक ईमानदार अफसर की रही है।

● **राजेंद्र आगाल**

एक और होटल पीपीपी मोड पर

प्रदेश में एक-एक कर कई सरकारी होटलों को निजी हाथों में सौंप दिया गया है। इसी कड़ी में भोपाल का प्रतिष्ठित होटल लेक व्यू अशोका अब पर्यटन विभाग की ओर से नए शर्तों पर लीज पर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार के लोग निकम्मे हैं। अगर सरकारी अधिकारी-कर्मचारी निकम्मे हैं तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। हैरानी की बात यह है कि विसंगतियों को दूर करने की बजाय सरकार पर्यटन विभाग के होटलों को एक-एक करके पीपीपी मोड पर देते जा रही है। अब इसी कड़ी में होटल लेक व्यू अशोका को पीपीपी मोड पर देने की तैयारी हो रही है। यह होटल केवल उन फर्मों, एजेंसियों या कंपनियों को लीज पर दिया जाएगा जो होटल संचालन से जुड़ी हों और हर साल विभाग को कम से कम 4 करोड़ रुपए की फिक्स राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हों। इसके अलावा, जो कंपनी मुनाफे में अधिक हिस्सेदारी दे सकेगी उसे ही प्राथमिकता दी जाएगी। लीज की शर्तों में मुनाफे की हिस्सेदारी का भी प्रावधान किया गया है। पर्यटन विभाग के अनुसार, मुनाफे की हिस्सेदारी का प्रतिशत 3 से 5 प्रतिशत तक रखा जाएगा। यह टेंडर की शर्तों का हिस्सा होगा। इसका अर्थ यह है कि जो भी कंपनी होटल के संचालन के लिए फिक्स राशि के अलावा अधिक मुनाफे की पेशकश करेगी, उसे होटल का संचालन सौंपा जाएगा। होटल लेक व्यू अशोका को बेचने या लीज पर देने की प्रक्रिया कुछ साल पहले शुरू हुई थी, जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) आमंत्रित किया गया था। तब राजस्थान, मप्र सहित अन्य राज्यों के 10 बड़े होटल समूहों ने रूचि दिखाई थी। हालांकि, तब प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी थी। अब फिर से यह प्रक्रिया शुरु की जा रही है, लेकिन इसके लिए वित्त विभाग की मंजूरी आवश्यक होगी। मंजूरी मिलने के बाद ही यह प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

रोजगार की बहार

मप्र में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए मोहन सरकार ने जहां एक ओर औद्योगिकीकरण पर फोकस किया है, वहीं अब सरकारी नौकरियों का पिटारा भी खोलने जा रही है। मप्र में सरकारी भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा पर वित्त विभाग ने अमल किया है। आने वाले 5 सालों के भीतर सरकार ढाई लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों को भर्ती की प्रक्रिया के लिए अनुमति दी है।

पिछले दिनों मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकारियों से खाली पदों की जानकारी मांगी थी। साल 2028-29 तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी। राज्य प्रशासनिक सेवा के साथ एम्पलाई सिलेक्शन बोर्ड को भी निर्देश दिए गए हैं। समय पर परीक्षा कराने के लिए वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। भर्ती के नियमों का पालन करने के साथ आरक्षण को भी लागू करने के निर्देश दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया के साथ विभागवार खाली पदों को भरने के लिए वित्त विभाग ने फॉर्मूला बनाया है। पहले साल 8 और उसके बाद दो सालों के भीतर 66 प्रतिशत खाली पदों पर भर्ती होगी।

प्रदेश सरकार ने रिक्त सरकारी पदों को भरने के लिए नियम और फॉर्मूला तैयार कर लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका पूरा ब्यौरा तैयार कर सभी विभागों को भेजा है। इसके तहत अगले पांच साल में ढाई लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए हर साल परीक्षा कैलेंडर जारी होगा। विभागों को तय फॉर्मूले के अनुसार ही रिक्त पदों को भरना होगा। प्रदेश के सरकारी विभागों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी और वाहन चालकों के पदों की पूर्ति आउटसोर्स के जरिए होगी। अति आवश्यक होने पर इन पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से मंजूरी लेना होगी। सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल, मप्र लोक सेवा आयोग और अन्य संस्थानों ने अगर रिक्त पदों पर 30 अक्टूबर तक परीक्षा करा ली है और नियुक्ति की जाना है, तो उसे निरस्त नहीं माना जाएगा। वहीं, 13 अगस्त, 2021 में मुख्य रूप से संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर 5 फीसदी पदों की सीधी भर्ती से पदपूर्ति करने हेतु प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया था, उसे अब 2028-29 तक के लिए स्थगित कर दिया है। प्रदेश में सरकारी पदों पर भर्ती के लिए सरकार ने जो फॉर्मूला बनाया है उसके अनुसार सबसे पहले प्रत्येक संवर्ग में 1 अप्रैल, 2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जाएगी। ऐसे पद जो कर्मचारी चयन मंडल, एमपीपीएससी या अन्य संस्थानों द्वारा भरे जा रहे हैं, रिक्त पदों की गणना में सम्मिलित नहीं होंगे। ऐसे 13 फीसदी पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के उपरांत रोके गए हैं, इनको भी रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जाएगा।

प्रदेश के विभागों में खाली पड़े पदों के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया है उसके अनुसार 33 फीसदी से कम पद रिक्त हैं, तो एक बार में सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। 33 फीसदी अथवा अधिक और 66 फीसदी से कम पद रिक्त होने पर वर्ष 2024-25 में 8 फीसदी, 2025-26 में 46 प्रतिशत और तीसरे साल 2026-27 में 46 फीसदी पदों पर भर्ती होगी। 66 फीसदी अथवा अधिक पद रिक्त होने पर प्रथम वर्ष 2024-25 में 8 फीसदी, साल 2025-26 में 31 फीसदी, साल 2026-27 में 31 फीसदी और चौथे साल 2027-28 में 30 फीसदी पद भरे जाएंगे। 25 प्रतिशत अथवा अधिक और 50 फीसदी से कम पद होने पर 2024-25 में 8 फीसदी, साल 2025-26 में 46 फीसदी और साल 2026-27 में 46 प्रतिशत पद भरे जाएंगे। 50 प्रतिशत अथवा अधिक और 75 प्रतिशत से कम पद होने पर साल 2024-25 में 8 फीसदी, 2025-26 में 31 फीसदी, 2026-27 में 31 और 2027-28 में 30 फीसदी पद भरे जाएंगे। 75 फीसदी अथवा अधिक पद खाली होने पर 2024-25 में 8, साल 2025-26 में 23 फीसदी, साल 2026-27 में 23 फीसदी और 2027-28 में 23 फीसदी पद भरे जाएंगे। प्रदेश में 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक इंक्रीमेट (वार्षिक वेतन वृद्धि) का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके आधार पर ही उनकी पेंशन का निर्धारण भी होगा। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई को और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 1 जनवरी की स्थिति में उनकी पात्रता के अनुसार एक इंक्रीमेट व पेंशन का निर्धारण होगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल, सभी संभागायुक्तों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को आदेश जारी किए है। गत 12 नवंबर को कैबिनेट ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सरकार के इस फैसले से 48 हजार 661 पेंशनरों-परिवार पेंशनरों को लाभ होगा। एरियर्स की राशि के भुगतान पर सरकारी खजाने पर 48.51 करोड़ का भार आएगा।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

पदोन्नति में आरक्षण का विवाद सुलझाने फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

मप्र में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नतियां वर्ष 2016 से रुकी हुई हैं। मप्र लोक सेवा पदोन्नति नियम-2002 को मप्र हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद से पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। प्रतिवर्ष हजारों अधिकारी-कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। पदोन्नति में आरक्षण का विवाद सुलझाने के लिए अब मोहन सरकार पहल करेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के शीघ्र निराकरण के लिए आवेदन दिया जाएगा। नया नियम तैयार करने तत्कालीन गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट का परीक्षण भी करवाया जाएगा। डॉ. मिश्रा ने सभी प्रभावित पक्षों से चर्चा करने के बाद रिपोर्ट तैयार की थी। प्रदेश में आरक्षित और अनारक्षित वर्ग को दी जाने वाली पदोन्नति को लेकर अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद पदोन्नति नियम को निरस्त कर दिया। प्रदेश सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए। तब से ही पदोन्नति पर रोक लगी है। कोर्ट के आदेश पर ही मई, 2016 के पहले हुई विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर पदोन्नतियां दी गई हैं। पदोन्नति न मिलने से नाराज कर्मचारियों को साधने के लिए सरकार ने उच्च पद का प्रभार देने का रास्ता निकाला पर यह भी सभी विभागों में लागू नहीं हो पाया।

अब संगठन की मजबूती पर फोकस

मप्र कांग्रेस की कार्यकारिणी के बाद अब पार्टी का फोकस संगठन की मजबूती और सक्रियता पर है। इसके लिए पार्टी ने फॉर्मूला बनाया है। जिसके तहत जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां फील्ड सर्वे के आधार पर की जाएंगी। नेताओं के बड़े नाम या जान-पहचान के आधार पर किसी को पद नहीं मिलेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जिला और ब्लॉक स्तर पर जाकर सक्रिय कार्यकर्ता तलाशे जाएंगे। युवाओं और महिलाओं को अधिक महत्व दिया जाएगा। पदाधिकारियों की नियुक्ति में नेताओं की सक्रियता और पूर्व के चुनावों में उनके योगदान को ध्यान दिया जाएगा। कई जिलों की कार्यकारिणी में लंबे समय से बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में फील्ड में जाकर स्थिति देखने के बाद रिपोर्ट बनाई जाएगी, फिर उसकी समीक्षा के बाद नियुक्ति दी जाएगी। मप्र में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की करारी हार के बाद कांग्रेस प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूत करने अब गांव स्तर तक पहुंचेगी। कांग्रेस प्रदेश में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करेगी। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में राजनीतिक मामलों के लिए गठित समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि अब कांग्रेस ग्राम पंचायत स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कदम उठाएगी। इसके लिए प्रदेश की सभी 23 हजार ग्राम पंचायतों में कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में अभी वार्ड स्तर पर तो कांग्रेस की कमेटी है, लेकिन अब पार्टी 50 घरों पर एक अलग से कमेटी बनाएगी।

सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस आगामी दो वर्ष केवल संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी। इसके लिए नया फॉर्मूला लागू किया जाएगा। जिला और ब्लॉक इकाइयों के अध्यक्ष प्रत्येक तीन वर्ष में बदले जाएंगे। दोबारा काम करने का अवसर सिर्फ उन्हें ही मिलेगा, जिनका प्रदर्शन बेहतर होगा। जिला प्रभारी एक माह के भीतर आवंटित जिलों का दौरा करके अपनी रिपोर्ट संगठन को देंगे, जिसके आधार पर नए वर्ष में लगभग 50 प्रतिशत जिला और ब्लॉक इकाइयों में परिवर्तन किया जाएगा। अधिकतर नए पदाधिकारी 50 वर्ष से कम आयु के बनाए जाएंगे। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार का बड़ा कारण संगठन की कमजोरी को माना गया। जिला और ब्लॉक इकाइयों के अधिकतर पदाधिकारी निष्क्रिय रहे। उन्होंने संगठनात्मक कामों में रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण कार्यकर्ता भी हतोत्साहित हुए। इस स्थिति को बदलने के लिए अब संगठन के पुनर्गठन पर फोकस किया जा रहा है। राजनीतिक मामलों की समिति ने जिला और ब्लॉक इकाइयों को सक्रिय करने के लिए आम सहमति से दो सुझाव दिए थे, जिसे प्रदेश कांग्रेस ने स्वीकार किया है। इसमें पहला पार्टी के कार्यक्रम भोपाल में करने के स्थान पर ब्लॉक या जिला स्तर पर किए जाएं और दूसरा जिला व ब्लॉक पदाधिकारी तीन वर्ष से अधिक पदस्थ नहीं रहना चाहिए। युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रदेश कार्यसमिति के माध्यम से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। अब जिला और ब्लॉक इकाइयों में परिवर्तन किया जाएगा। जिन पदाधिकारियों को पदस्थ रहते तीन वर्ष से अधिक समय हो चुका है, उन्हें बदला जाएगा। इसके लिए प्रदेश महासचिवों से कहा गया है कि वे प्रभार के जिले में बैठक करके संगठन की गतिविधियों को लेकर प्रतिवेदन तैयार करें। इसमें यह भी बताएं कि जिला और ब्लॉक इकाइयों में पदाधिकारी कब से पदस्थ हैं। वहां नगरीय निकाय, जिला और जनपद पंचायत के साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणाम कैसे रहे हैं। पार्टी की गतिविधियों को किस तरह से संचालित किया जा रहा है। कौन-कौन से अभियान चलाए गए हैं और पार्टी से नए लोगों को जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इन सब आधार पर जिला और ब्लॉक इकाइयों में परिवर्तन का निर्णय लिया जाएगा। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले वरिष्ठ नेता कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा गया था, तब उन्होंने अपने हिसाब से जिलाध्यक्ष बनाए थे। इसके बाद कुछ जिला और ब्लॉक अध्यक्ष ही बदले गए। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि लगभग 50 प्रतिशत अध्यक्षों को चार वर्ष से अधिक हो चुके हैं। कुछ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष तो 15-15 वर्षों से हैं। ऐसे सभी पदाधिकारी बदले जाएंगे।

● **अरविंद नारद**

खराब प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों की छुट्टी

प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति के गठन के बाद कांग्रेस का फोकस संगठन की मजबूती पर है। इसके लिए कांग्रेस अपने हर पदाधिकारी की परफॉर्मेंस का आंकलन कराएगी। जिस पदाधिकारी का प्रदर्शन खराब होगा उसकी छुट्टी कर दी जाएगी। कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने तय किया है कि इन सबके कामों का त्रैमासिक मूल्यांकन किया जाएगा। सभी पदाधिकारियों को प्रतिमाह अपने कामकाज का ब्यौरा प्रदेश कांग्रेस को देना होगा। इसमें दौरे, बैठकों और कार्यक्रमों की जानकारी रहेगी। वहीं, जिला और ब्लॉक इकाइयों से भी प्रदेश पदाधिकारियों की गतिविधियों का फीडबैक लिया जाएगा। इसके आधार पर मूल्यांकन होगा। जो भी कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, उसकी छुट्टी करने का इरादा है। पार्टी ने यह भी तय किया है कि संगठन को हर स्तर पर सक्रिय किया जाएगा। जिलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसमें बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। प्रशिक्षण विभाग द्वारा पार्टी की रीति-नीति और कार्यक्रम बताए जाएंगे। इसके साथ ही भाजपा सरकार की वादाखिलाफी को मुद्दा बनाकर प्रदर्शन भी किए जाएंगे। इन्हें निर्देश दिए गए हैं कि सबको माह में कम से कम एक बार प्रभार के जिले का दौरा करना होगा। जिला और ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक करके संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करनी होगी। कांग्रेस द्वारा दिए जाने वाले कार्यक्रमों का नेतृत्व करने के साथ उसकी रिपोर्ट भी प्रदेश मुख्यालय को देनी होगी।

विदेशों से हो रही है साइबर ठगी

देश में साइबर अपराध या धोखेबाजी का खेल कितने तरीके से खेला जा रहा है? प्रवर्तन निदेशालय की जांच में इसकी बानगी देखने को मिली है। नकली सीबीआई और फर्जी कस्टम अधिकारी बन जाते हैं, बैंक भी नकली और साइबर अपराध व डिजिटल अरेस्ट के जरिए जो कमाई की, उसे शेल कंपनियां बनाकर निवेश करने का प्रयास किया गया। साइबर धोखेबाजों ने फर्जी आईपीओ आवंटन और धोखाधड़ी वाले ऐप्स के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश से जुड़ी योजनाओं का लालच देकर व उच्च रिटर्न का वादा कर निर्दोष व्यक्तियों को अपने जाल में फंसाया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से साइबर धोखेबाजी का खेल खेला गया। हांगकांग और थाईलैंड में रहने वाले साइबर अपराधियों ने लोगों को निशाना बनाने के लिए भारत में एक गैंग तैयार किया। साइबर धोखेबाजों ने 159.70 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की।

प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले माह विशेष न्यायालय (पीएमएलए), बंगलूरू के समक्ष आठ आरोपी व्यक्तियों (सभी ईडी द्वारा गिरफ्तार) चरण राज सी, किरण एस के, शाही कुमार एम, सचिन एम, तमिलारासन, प्रकाश आर, अजित आर और अरविंदन के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। इसमें 24 कंपनियां और उनकी 159 करोड़ रुपए की साइबर अपराध से जुड़ी आय भी शामिल है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। विशेष न्यायालय, बंगलूरू ने 29 अक्टूबर को पीसी का संज्ञान लिया है। ईडी ने पूरे भारत में कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर उक्त मामले की जांच शुरू की थी। इन प्राथमिकियों में आरोप लगाया गया है कि कुछ अज्ञात साइबर धोखेबाजों ने फर्जी आईपीओ आवंटन और धोखाधड़ी वाले ऐप्स के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश से जुड़ी योजनाओं का लालच देकर, उच्च रिटर्न का वादा करके निर्दोष व्यक्तियों को अपने जाल में फंसाया है। इसके अलावा, कुछ पीड़ितों को सीमा शुल्क और सीबीआई द्वारा फर्जी गिरफ्तारी की आड़ में बरगलाया गया है।

ईडी के मुताबिक, डिजिटल अरेस्ट एवं साइबर अपराध से जुड़ी दूसरी तकनीकों के जरिए लोगों से फर्जी फंड नियमितीकरण प्रक्रिया के तहत विभिन्न शेल कंपनियों में भारी धनराशि हस्तांतरित की गई। आरोपियों ने फर्जी शेयर बाजार, निवेश और डिजिटल गिरफ्तारी, आदि का इस्तेमाल किया है। ये मुख्य रूप से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। इनके तरीके को सूअर-कसाई घोटाले के रूप में भी जाना जाता है। नकली शेयर बाजार और निवेश घोटाले से ये आरोपी, पीड़ितों को उच्च रिटर्न का वादा करते थे। नकली वेबसाइटों और भ्रामक वॉट्सएप समूहों का उपयोग किया गया। कुछ समूह ऐसे भी बनाए गए, जो प्रतिष्ठित वित्तीय फर्मों से जुड़े हुए प्रतीत होते थे। इससे लोगों को इन घोटालेबाजों पर भरोसा हुआ। आरोपियों ने नकली विज्ञापनों और मनगढ़ंत सफलता की कहानियों के माध्यम से लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता स्थापित की।

इसके बाद साइबर धोखेबाजों ने पीड़ितों को एक बड़ी मात्रा में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। धोखेबाजों ने डिजिटल गिरफ्तारी का सहारा भी लिया। गैंग के ही कुछ सदस्य, खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत करते थे। वे पीड़ितों को अपनी बचत स्थानांतरित करने के लिए ऐसे परिदृश्य बनाकर डराते थे, जिससे सामने वाला व्यक्ति डरकर अपनी कमाई में उन्हें हिस्सा देने के लिए राजी हो जाता था। ईडी की जांच से पता चला कि आरोपियों ने पीड़ितों को धोखा देने और अवैध आय को सफेद करने के लिए भी एक जटिल योजना तैयार की थी। जालसाजों ने सैकड़ों सिम कार्ड जुटाए थे। इनका इस्तेमाल शेल कंपनियों के बैंक खातों का संचालन और वॉट्सएप खाते बनाने के लिए किया गया। इन सिम कार्ड के द्वारा आरोपियों को अपनी असल पहचान छिपाने का मौका मिल जाता है। साथ ही आरोपियों के लिए पीड़ितों को धोखा देने के चांस पुख्ता हो जाते हैं। ईडी की जांच से पता चला कि घोटालेबाजों ने साइबर अपराधों से प्राप्त आय के अधिग्रहण और शोधन की सुविधा के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक आदि जैसे विभिन्न राज्यों में 24 फर्जी कंपनियां बनाई हैं।

● **लोकेश शर्मा**

हांगकांग-थाईलैंड में सक्रिय गिरोह

भारत से बाहर हांगकांग और थाईलैंड में रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने कई पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए भारत में स्थित अपने सहयोगियों की सक्रिय सहायता से एक परिष्कृत साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। इन विदेशी घोटालेबाजों ने वॉट्सएप के माध्यम से भेजे गए नकली दस्तावेजों का उपयोग कर डिजिटल हस्ताक्षर बनाने, फर्जी कंपनियों की स्थापना करने और बैंक खाते खोलने के लिए डमी निदेशकों के रूप में काम करने के लिए भारत में व्यक्तियों के साथ समन्वय किया था। आरोपी व्यक्तियों में से एक, चरण राज सी ने निदेशक पद के लिए व्यक्तियों की भर्ती और बैंक खाता खोलने के प्रबंधन में इस योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शशि कुमार एम (आरोपी) ने कई शेल कंपनियों को शामिल करने में सहायता की है जो अपराध की आय को इकट्ठा करने और उसे बैंकिंग प्रणाली में एकीकृत करने में सहायक बनीं। जांच के दौरान, जब चरण राज सी के आवास की तलाशी ली गई तो कई दस्तावेज और सामान जब्त किए गए। इनमें शेल कंपनी की मुहर वाली एक डायरी, बैंक खाता खोलने का विवरण देने वाले हस्तलिखित नोट, चेक और बैंकिंग दस्तावेज व डमी निदेशकों के पहचान वाले दस्तावेज शामिल हैं। कंपनी से संबंधित ऐसे दस्तावेज भी बरामद किए गए, जो निवेश साइबर-धोखाधड़ी में शामिल शेल कंपनियों के एक नेटवर्क का खुलासा करते हैं। आरोपी किरण एसके, सचिन एम और तमिलारासन से जुड़ी विभिन्न कंपनियों की ईडी जांच में धोखाधड़ी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग में व्यापक संलिप्तता का पता चला है।

मनरेगा में करोड़ों का खेल!

100 दिनों का रोजगार दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा

मप्र में मनरेगा में फर्जीवाड़ा की सारी हदें पार की जा रही हैं। मनरेगा में मजदूरों को साल में 100 दिन का रोजगार दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। शिवपुरी जिले की बदरवास जनपद की ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों ने तो फर्जीवाड़े की सारी हदें पार कर दीं। सरकारी अस्पतालों में जिस दिन महिलाओं के प्रसव हुए, उसी तारीखों में इन महिलाओं से पंचायतों में मनरेगा के तहत अमृत सरोवर के गड्ढे खुदवाना बता दिए। इतना ही नहीं, सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की मिलीभगत से इन दिनों की मजदूरी भी निकाल ली गई। गौरतलब है कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत जॉब कार्डधारी परिवारों की महिलाओं को प्रसव होने पर प्रसूति सहायता का प्रावधान है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा श्रम कार्ड के आधार पर 45 दिन की मजदूरी का भुगतान स्वास्थ्य विभाग के जरिए कराया जाता है।

जिस मनरेगा योजना से हिन्दुस्तान की तस्वीर बदलने का दावा किया गया, उसकी जमीनी हकीकत आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। ग्रामीण मजदूरों को गरीबी से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाने वाली मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के मप्र में हाल बेहाल हैं। मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार दिलाने के नाम पर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। वहीं मजदूरों को पिछले कई महीने से मजदूरी का पैसा नहीं मिला है। अपने मेहनताने यानी मेहनत की मजदूरी के लिए मजदूर दर-दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मनरेगा की योजनाओं में करोड़ों रुपए का खेल हुआ है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मप्र मनरेगा की योजनाओं के क्रियान्वयन में हमेशा अन्य राज्यों से आगे रहा है। लेकिन इस दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा भी किया गया है। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि मप्र सरकार लगातार गांव में लोगों को रोजगार देने के लिए तरह-तरह के प्रयास करती है, जिनमें से एक सबसे बड़ी योजना मनरेगा है। जहां मनरेगा के तहत लोगों को गांव में ही रोजगार देने का शासन का प्रावधान है, लेकिन मनरेगा योजना में सबसे अधिक धांधली होती है, जिसकी वजह से यहां लोगों को रोजगार नसीब नहीं होता है। प्रदेश की सरकार ने पलायन पर प्रतिबंध लगाने के लिए गांवों में मनरेगा के तहत काम तो खोला और लोगों को काम देने का वादा भी किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकारी तंत्र द्वारा मजदूरों से काम न कराकर मशीनों से काम कराया जाता है और मजदूर फिर से बेरोजगार होकर पलायन कर बाहर जाने को मजबूर हो जाते हैं।

मनरेगा में फर्जीवाड़े का आलम यह है कि कागजों पर जिन लोगों को मजदूरी करते दिखाया गया है उसमें वे महिलाएं भी शामिल हैं जिनका उसी दिन प्रसव हुआ है। यानी जब प्रसूता उठ-बैठ नहीं सकती, उन दिनों में मजदूरी करना बताया गया है। शिवपुरी जिले के बारई गांव की फूला बाई पत्नी नवलसिंह कुशवाह ने 22 मार्च 2023 की दोपहर 1:50 बजे बदरवास अस्पताल में बेटे को जन्म दिया था। ग्राम पंचायत बारई में मनरेगा के तहत चरनोई की जमीन पर मिनी पर्कोलेशन टैंक निर्माण कार्य में 21 मार्च से 27 मार्च तक मजदूरी दर्ज कर दी। फूला बाई के संग उसके पति को भी छह-छह दिन की मजदूरी का भुगतान ग्राम पंचायत ने अपने रिकार्ड में किया है। वहीं मांगरोल पंचायत के ईश्वरी गांव की निवासी पूनम यादव पत्नी रूपेश यादव ने बदरवास अस्पताल में 16 अप्रैल 2023 की दोपहर 1:50 बजे बच्चे को जन्म दिया। ग्राम पंचायत मांगरोल ने अमृत सरोवर नवीन तालाब निर्माण भजुआ नाला बरखेड़ाखुर्द में 14 अप्रैल 2023 से 20 अप्रैल 2023 के बीच पूनम को मजदूरी करना भी दर्ज कर दिया। 19 अप्रैल की अनुपस्थिति छोड़कर 6 दिन का भुगतान 1326 रुपए किया। प्रसव की वजह से जिस दिन पूनम की हालत बैठने की भी नहीं थी, उस दिन भी मजदूरी करना बता दिया। वहीं बरखेड़ाखुर्द सचिव नरेश सोनी का कहना है कि आरईएस का काम है, पंचायत का कुछ नहीं है।

बडोखरा पंचायत की निकिता धाकड़ पत्नी दीपक धाकड़ ने 13 अप्रैल 2023 को बदरवास अस्पताल में सुबह 7:30 बजे बेटे को जन्म दिया। ग्राम पंचायत बडोखरा ने मनरेगा के तहत गीदखेड़ा गांव पहाड़ी के पास डग पॉइंट निर्माण कार्य में मजदूरी करना दर्ज कर दिया। प्रसूता निकिता धाकड़ को 9 अप्रैल 2023 से 15 अप्रैल 2023 तक 6 दिन की मजदूरी दर्शाई है। निकिता को 15 अप्रैल की गैर हाजिरी काटकर प्रतिदिन 221 रुपए के हिसाब से 6 दिन की कुल 1326 रुपए भुगतान हुआ है। कलेक्टर शिवपुरी रवींद्र कुमार चौधरी का कहना है कि जिला पंचायत सीईओ से मामले की जांच कराएंगे। जिन ग्राम पंचायतों में प्रसूताओं को भी मजदूर बनाया है, ऐसे मामलों का पता लगाएंगे। जिला पंचायत सीईओ से बोलकर जांच करवाता हूं। जांच के आधार पर संबंधितों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। सीईओ जनपद पंचायत बदरवास शिवपुरी अरविंद शर्मा का कहना है कि यदि मामले हमारे बदरवास ब्लॉक के हैं तो जांच कराएंगे जिस दिन प्रसव हुआ, उसी दिन प्रसूता से मजदूरी कराना संभव ही नहीं। यदि मामले हमारे बदरवास ब्लॉक के हैं तो जांच कराएंगे। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

कांग्रेस ने मनरेगा में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि गरीबों के रोजगार के लिए आवंटित धन को अधिकारी और सत्ताधारी दल से जुड़े लोग मिलकर हड़प रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने सरकार से मामले की जांच कराने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार ने आरोप लगाया है कि मप्र में मनरेगा में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए जो पैसा आवंटित है उसे अधिकारी और भाजपा से जुड़े लोग चट कर जा रहे हैं। शिवपुरी में कुछ मामले सामने आए हैं जिनमें महिलाओं ने जिस दिन अस्पताल में बच्चों को जन्म दिया उस दिन वो कागजों में मजदूरी कर रही थी और उनके नाम से पैसा निकाल दिया गया। शिवपुरी अकेला जिला नहीं है, पूरे प्रदेश में इस तरह के फर्जीवाड़े हो रहे हैं।

● **प्रवीण सक्सेना**

मप्र में दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मुकाबला 50-50 का रहा। एक सीट बुधनी पर जहां भाजपा की जीत हुई, तो वहीं दूसरी सीट विजयपुर पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन अंततः मुकाबला बराबरी पर रहा। दोनों सीटों पर विजयी प्रत्याशी भले ही बदले, लेकिन परिणाम 2023 वाले ही रहे।

मप्र में बराबरी का मुकाबला

मप्र में दो सीटों पर हुए उपचुनाव में एक को भाजपा ने और दूसरी को कांग्रेस ने जीता है। बुधनी विधानसभा सीट पर भाजपा का तो विजयपुर में कांग्रेस का कब्जा बरकरार है। दरअसल बुधनी सीट जीतने की सबसे मुख्य वजह शिवराज सिंह चौहान है। बुधनी विधानसभा शिवराज सिंह चौहान की सीट रही है, ऐसे में पहले से ही संभावना जताई जा रही थी कि यह सीट भाजपा की ही कब्जे में जाएगी और हुआ भी वैसा ही। हालांकि इस सीट पर जीत को लेकर कॉन्फिडेंट होने के बाद भी भाजपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव के दौरान बुधनी में डेरा डाले रखा तो वहीं पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी रोड शो कर भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी रैली करके बुधनी में जोर आजमाइश की। यही वजह रही कि सारे बड़े नेताओं ने यहां भरपूर ताकत झोंक दी। बुधनी फिर से भाजपा के कब्जे में वापस आ गई। हालांकि सीट पर कांग्रेस ने भी कोई कमजोर आजमाइश नहीं कि कांग्रेस के सारे बड़े नेता बुधनी उपचुनाव पर ताकत झोंकते नजर आए।

13 नवंबर को बुधनी सीट पर उपचुनाव की वोटिंग हुई थी। बुधनी सीट पर पिछले चुनाव के मुकाबले वोट प्रतिशत में इस बार कमी आई थी। उपचुनाव में 77.32 प्रतिशत वोटिंग हुई, जो 2023 विधानसभा चुनाव में लगभग 84.86 प्रतिशत थी हालांकि, चुनाव के दौरान दोनों की प्रमुख पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने यहां चुनाव प्रचार किया था। शिवराज और उनके बेटे कार्तिकेय भी सक्रिय भूमिका में थे उसके बावजूद जीत का अंतर कम हो गया। जिससे जाहिर होता है कि शिवराज सिंह चौहान के प्रति जो जनता का प्रेम 2023 के विधानसभा चुनाव में दिखा था वह बाय इलेक्शन में उतना नजर नहीं आया। वहीं, कांग्रेस से जीतू पटवारी सहित अन्य नेताओं ने भी कमान संभाल रखी थी।

लोकसभा चुनाव में पाला बदलकर भाजपा में शामिल हुए वन मंत्री रामनिवास रावत को बड़ा झटका लगा है। विजयपुर में रामनिवास रावत की कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा से करारी हार हुई है। शुरुआती रुझान में पीछे होने के बाद रामनिवास रावत ने बाद में बढ़त जरूर बनाई, लेकिन ये बढ़त ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रह पाई और आखिर में रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा ने उन्हें करीब 6 हजार से अधिक वोटों से हराया है। कांग्रेस को श्योपुर-मुरैना लोकसभा सीट पर मिली हार का बदला कांग्रेसियों ने मिलकर ले लिया। 6 बार विधायक रहे रामनिवास रावत की गिनती मप्र के बड़े नेताओं में होती है। वो 6 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस से उनकी नाराजगी सामने आई थी। मुरैना-श्योपुर लोकसभा सीट से सत्यपाल सिंह सिकरवार को टिकट मिलने की वजह से वो नाराज थे और यही वजह है कि कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। रामनिवास 8 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन इस बार जनता को उनकी दबंगई पसंद नहीं आई, जबकि कहा जाता है कि रामनिवास रावत ने अपने पसंदीदा अफसरों की तैनाती करवाई, रावत ने जीत के कई हथकंडे अपनाए, बावजूद इसके वो कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से चुनाव हार गए। विजयपुर उपचुनाव में मिली कांग्रेस की जीत को लेकर ही कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपना माहौल बनाने में कामयाब रही। कांग्रेस ने उपचुनाव के पहले विजयपुर में नए अफसर के ट्रांसफर का मुद्दा जोर-शोर से उठाया और कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में सफल रही। दूसरा मुद्दा मतदान वाले दिन क्षेत्र में हुई दबंगई की घटनाओं को भी कांग्रेस ने जोर-शोर से उठाया और उसे भी भुनाने में कांग्रेस सफल रही। भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत ने मंत्री बनने के बाद सौगातों का पिटारा खोला लेकिन जनता को यह भी रास नहीं आया। भाजपा ने मंत्री का दर्जा देकर सीताराम

भाजपा के पास नहीं था विकल्प

दरअसल, विजयपुर सीट पर भाजपा के पास प्रत्याशी को लेकर कोई विकल्प ही नहीं था। रामनिवास रावत को विधायक न रहते हुए भी मंत्री बनाया गया। उनके हिसाब से प्रशासनिक जमावट की गई और विकास कार्यों के लिए खजाने का मुंह भी खोल दिया। सीताराम आदिवासी की नाराजगी को कम करने और आदिवासियों को संदेश देने के लिए उन्हें सहरिया विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाकर मंत्री दर्जा दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मुरैना से सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जमकर प्रचार किया। इन इलाकों में रात्रि विश्राम कर समीकरण साधने का प्रयास किया। हर वो काम भाजपा ने विजयपुर में किया, जिससे रामनिवास की जीत सुनिश्चित हो सके पर वे कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतने में असफल रहे। विधायक न बन पाने के कारण उन्होंने वन मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया। उधर, विधानसभा व लोकसभा चुनाव और फिर अमरवाड़ा सीट के उपचुनाव में हार मिलने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निराशा थी। बुधनी और विजयपुर सीट के उपचुनाव पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं में जान फूंकने और फिर मुकाबले में आने का माध्यम भी थे। बुधनी में जीत की संभावना कम ही थी फिर भी अनुभवी नेता राजकुमार पटेल पर दांव लगाकर कांग्रेस ने मुकाबला कांटे का बना दिया। पार्टी का जोर विजयपुर पर अधिक था क्योंकि कांग्रेस यहां रामनिवास रावत को सबक सिखाने के लिए भी मैदान में थी।

आदिवासी की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया, लेकिन भाजपा की यह रणनीति भी काम नहीं आई।

उपचुनाव में विजयपुर हॉट सीट थी। दरअसल, यहां से कोई सामान्य प्रत्याशी नहीं बल्कि वन मंत्री रामनिवास रावत मैदान में थे। वे इसी सीट पर कांग्रेस से छह बार विधायक रहे और भाजपा उन्हें तोड़कर लाई थी इसलिए माना जा रहा था कि उनका अपना भी काफी प्रभाव होगा, हालांकि वह उपचुनाव में दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा यहां भाजपा को स्वयं की कई कमजोरियां भारी पड़ गईं। मतदान तक भी पार्टी कार्यकर्ता रामनिवास रावत को भाजपा का नहीं मान पाए। भाजपा के स्थानीय बड़े आदिवासी नेता व पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी, बाबूलाल मेवरा सहित अन्य ने भी खुलकर साथ नहीं दिया। रामनिवास रावत ने भी भाजपा के बजाय अपनी ही टीम पर ज्यादा भरोसा किया। वहीं, कांग्रेस को प्रत्याशी चयन में आम सहमति, जातीय समीकरण को साधने और एकजुट होकर चुनाव लड़ने का लाभ मिला। विजयपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव के प्रमुख रणनीतिकार के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र सिंह तोमर थे। मुख्यमंत्री ने आदिवासियों को साधने के लिए सीताराम आदिवासी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। विजयपुर के विकास के लिए सरकार का खजाना खोल दिया। क्षेत्र के आदिवासियों सहित सभी वर्गों को साधने के लिए रात्रि विश्राम सहित लगातार प्रवास कर सभाएं कीं, लेकिन आदिवासियों को रिझाने में नाकाम रहे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने व्यक्तिगत नाराजगी के कारण उपचुनाव से दूरी बनाकर रखी थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने समूचे संगठन को चुनाव में लगा दिया था। वहीं विजयपुर की जीत से कांग्रेस और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भी बल मिला है। स्थानीय कार्यकर्ताओं की पसंद पर वर्ष 2023 में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया गया। मुरैना से चुनाव लड़ने वाले सत्यपाल सिंह सिकरवार और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने मैदानी मोर्चा संभाला। आदिवासियों के बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहुंचे तो पटवारी ने कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने का काम किया। इस जीत से पटवारी की टीम के गठन को लेकर जो विरोध के स्वर उभर रहे थे, वे भी मंद पड़ेंगे।

उधर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जीत में मप्र भाजपा संगठन और नेताओं की अहम भूमिका रही है। मप्र के नेताओं की चुनावी मैनेजमेंट से वहां कमल खिला है। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की ऐतिहासिक जीत पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने महाराष्ट्र विधानसभा व देश के अन्य राज्यों में हुए उपचुनावों में भाजपा को मिली विजय पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित विजय उत्सव में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर, आतिशबाजी कर उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता लगातार आशीर्वाद दे रही है। मप्र में भी भाजपा का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव कई मायनों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना व शरद पवार की एनसीपी के लिए सबक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन की सरकार द्वारा कराए गए जनहितैषी विकास कार्यों एवं गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए जनता ने फिर आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस देश में अप्रासंगिक और अलोकप्रिय हो चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर एक बार अपना आशीर्वाद दिया है। शिवाजी की धरती महाराष्ट्र में सत्य और सुशासन की जीत हुई है। जनता ने झूठ और नफरत की राजनीति करने वाली कांग्रेस व इंडी गठबंधन के परिवारवाद, वंशवाद को पूरी तरह नकार दिया है। कांग्रेस को आत्मचिंतन व आत्म अवलोकन करना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मराठा समुदाय से आते हैं और उनका महाराष्ट्र में प्रभाव माना जाता है। ऐसे में भाजपा ने उन्हें महाराष्ट्र में स्टार प्रचारक बनाया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में लगातार भाजपा के पक्ष में प्रचार किया। खास बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मराठी बोलते हैं, ऐसे में उन्होंने मराठवाड़ा इलाके में मराठी में ही प्रचार किया, जबकि उन्होंने भाजपा के साथ-साथ एनसीपी और शिवसेना के प्रत्याशियों के पक्ष में भी प्रचार किया। वहीं विश्वास सारंग ने 1 महीने से भी ज्यादा समय तक महाराष्ट्र में लगातार कैंपेनिंग की थी। उन्होंने प्रत्याशियों के साथ-साथ अलग सीटों पर चुनावी रणनीति बनाई, जिसका असर महाराष्ट्र के चुनावों में दिखा है। इसी तरह उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ-साथ कई विधायक और सांसदों ने लगातार प्रचार किया था।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

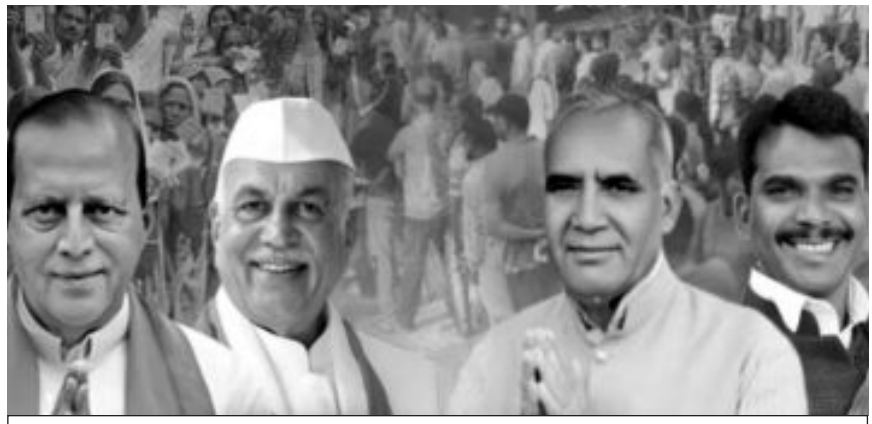

मप्र में लगातार बढ़ रहा भाजपा का ग्राफ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मप्र में भी भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हमने 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटें जीतीं। कांग्रेस और कमलनाथ का गढ़ कही जाने वाली छिंदवाड़ा सीट भी हमने जीती और उपचुनाव में अमरवाड़ा की विधानसभा सीट भी हम जीते। उपचुनाव में बुधनी विधानसभा सीट भी हम जीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि विजयपुर में हमारे प्रत्याशी रामनिवास रावत को भले ही पराजय का सामना करना पड़ा हो, लेकिन वहां हमारे वोट बढ़े हैं। मप्र में भाजपा की डबल इंजन की सरकार प्रदेश के विकास की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी और आने वाले चुनाव में हम विजयपुर में भी बड़ी जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत जो दुनिया का सबसे युवा देश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और यही लोकतंत्र की असली ताकत है, देश के मतदाताओं की ताकत है। मप्र के नेताओं ने वहां की जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महाराष्ट्र में जमकर पसीना बहाया। उनके प्रचार वाली ज्यादातर सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। सभाएं करके प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया, जबकि अलग-अलग लोगों और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक करके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। कैलाश विजयवर्गीय को भाजपा में चुनावी मैनेजमेंट में माहिर माना जाता है। ऐसे में पार्टी ने उन्हें नागपुर की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने नागपुर में डेरा जमाकर लगातार भाजपा और महायुति के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। मप्र में भाजपा के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव से पहले ही भाजपा ने उन्हें वहां एक्टिव कर दिया था। नरोत्तम मिश्रा ने महाराष्ट्र के विदर्भ में लगातार प्रचार किया। उन्होंने भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया।

ड्रग्स तस्करी का केंद्र बना मप्र

देश का हृदय प्रदेश मप्र ड्रग्स तस्करी का केंद्र बनता जा रहा है। पिछले कुछ सालों से मप्र को केंद्र बनाकर तस्कर यहां से ड्रग्स का काला कारोबार चला रहे हैं। पिछले दिनों मप्र में कई जांच एजेंसियों ने मिलकर भोपाल से 1800 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स का खुलासा किया था। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यह स्थिति तब है जब प्रदेश में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस का सख्त एक्शन जारी है। जनवरी 2023 से अक्टूबर 2024 तक यानी 22 महीनों में 7886 आरोपियों को ड्रग्स तस्करी और खरीद-फरोख्त के मामले में गिरफ्तार किया गया है जबकि 29 अपराधियों के खिलाफ 115 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की गई है।

हाल ही में राजधानी भोपाल से 1814 करोड़ की ड्रग्स और उसे बनाने वाले पदार्थ को जब्त किए जाने के साथ ही नशे के खिलाफ मप्र पुलिस का अभियान लगातार जारी है। मप्र पुलिस ने आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि जनवरी 2023 से अक्टूबर 2024 तक पूरे प्रदेश में 6161 प्रकरणों में अवैध मादक पदार्थ के व्यापार में शामिल 7886 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इसके अंतर्गत ऐसी गतिविधियों में शामिल अपराधियों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को जब्त-फ्रीज किए जाने के लिए एनडीपीएस एक्ट 1985, धारा 68-ए के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 29 अपराधियों के खिलाफ 115 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक इस प्रावधान के तहत सबसे ज्यादा कार्रवाई अफीम की मंडी कहे जाने वाले मंदसौर और नीमच में की गई हैं, जहां से 23 कुख्यात अपराधियों की संपत्ति फ्रीज की गई है। इन अपराधियों में नाहरगढ़ के धनराज उर्फ धन्ना (पिता-ओमप्रकाश पाटीदार) की 14 करोड़ से अधिक की संपत्ति, नारायणगढ़ के श्याम (पिता-भंवर सिंह) की 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति, मनसा के पीयूष (पिता-पीरू बंजारा) की 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति, सीतामाउ के अशोक (पिता-मांगीलाल पाटीदार) की 8 करोड़ से अधिक की संपत्ति और अफजलपुर के ताहिर (पिता-शफी मोहम्मद) की 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति शामिल है।

बता दें कि एनडीपीएस एक्ट नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है। इस एक्ट के लगने के बाद आरोपी अपराधी को छह महीने तक जमानत नहीं मिल पाती है। इस अधिनियम के तहत पिछले दो सालों में की गई कार्रवाई पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसके अंतर्गत 1 जनवरी 2023 से अभी तक कुल 74 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें इंदौर के 43 अपराधी, मंदसौर और उज्जैन के 5-5, नीमच और रतलाम के 4-4 अपराधी शामिल हैं।

भोपाल से 1800 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ने के मामले का खुलासा होने के बाद इनके तार मंदसौर से भी जुड़े हुए मिले हैं। जिसके कारण मंदसौर जिला चर्चाओं में आ गया है। भोपाल एमडी ड्रग्स केस में मुख्य आरोपी यहीं के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस घटना ने मंदसौर जेल पर भी लोगों का ध्यान खींचा है। वर्तमान स्थिति में वहां बंद ड्रग तस्करों की संख्या के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। बता दें, कि मंदसौर जेल में बंद 640 से ज्यादा बंधकों में से 60 प्रतिशत से ज्यादा यानी 398 कैदी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानि एनडीपीएस एक्ट के तहत बंद हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि प्रदेश को खोखला करने के प्रयास में हर साल ड्रग तस्करों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन इतनी बड़ी मात्रा में आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है।

मंदसौर जिला जेल में कैदियों की क्षमता से ज्यादा बंधक बंद हैं। यहां एक बार में लगभग 370 अपराधियों को रखा जा सकता है। पर फिलहाल इस जेल में 640 से ज्यादा कैदी बंद किए गए हैं। इनमें से 395 से ज्यादा अपराधी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। जो दर्शाता है कि जेल में बंद कैदियों में ड्रग तस्करों का कितना बड़ा हिस्सा है। बाकी कैदी कत्ल, डकैती, डोमेस्टिक वायलेंस और धोखाधड़ी जैसे मामलों के दोषी हैं। जेल के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि यहां इस जेल में 630 पुरुष और 12 महिलाएं हैं। मौजूदा जेल सिर्फ 1.06 हेक्टेयर में है। इसे लेकर भूखी गांव की जमीन पर 39 एकड़ में नई जेल बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। मंदसौर जेल में दूसरी उप-जेल से भी ड्रग तस्करी के आरोपियों को लाया जा रहा है। इसके कारण भी कैदियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

● **जितेंद्र तिवारी**

इंदौर-टू-राजस्थान बना ड्रग्स कॉरिडोर

मप्र की आर्थिक राजधानी इंदौर ड्रग्स का बड़ा सेंटर बन चुका है। यहां हाल ही में करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इन सिंडिकेट क्रिमिनल्स के तार राजस्थान से लेकर पूरे देश में फैले हुए हैं। हाल ही में सर्राफा पुलिस ने 95 लाख रुपए की ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को इस आरोपी के पास 989 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली। उसकी पूछताछ में पता चला कि आरोपी राजस्थान के प्रतापगढ़ का है। वह राजस्थान से ड्रग्स इंदौर और आसपास के इलाकों में सप्लाई करता था। इतना ही नहीं, पुलिस को आरोपी के पास से एक ही नाम के दो आधार कार्ड भी मिले। दरअसल कुछ दिन पहले सर्राफा थाना पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ रिंकू और पारस नाम के दो युवकों को पकड़ा था। पुलिस को उनके पास से 506 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली थी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि वो ये ड्रग्स राजस्थान के तस्कर फारुख से लेकर आए थे। आरोपियों की निशानदेही पर ही पुलिस ने फारुख खान नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि फारुख इंदौर होते हुए उप्र की तरफ ड्रग सप्लाई करने जा रहा है। इस सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पुलिस को फारुख के पास से 95 लाख रुपए की नशीली सामग्री मिली। आरोपी के पास से मप्र और राजस्थान के दो आधार कार्ड भी मिले। पुलिस इनकी जांच कर रही है। डीसीपी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि एमपी में ड्रग सप्लाई करने वालों में फारुख बड़ा नाम है। ये मप्र में इसलिए नहीं पकड़ा जा सका, क्योंकि उसके खिलाफ मामले राजस्थान में दर्ज होते थे।

नक्सलियों ने बनाया नया ठिकाना

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर हो रहे ताबड़तोड़ प्रहार के बाद अब नक्सली मप्र का रुख कर रहे हैं। नक्सलियों की सक्रियता को देखकर बालाघाट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे नक्सलियों ने संजय टाइगर रिजर्व को अपना नया ठिकाना बना लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कुछ नए चेहरे देखने को मिले हैं। ये लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, हमें नहीं पता। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अफसर की रिपोर्ट के अंश हैं जो पिछले दिनों केंद्र सरकार को दी गई है। अफसर ने ये भी लिखा कि आशंका इस बात की है कि ये नक्सली हैं, जो छत्तीसगढ़ से भागकर मप्र की सीमा में दाखिल हुए हैं। दरअसल, इसी रिपोर्ट के आधार पर मप्र सरकार ने पिछले दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में सीआरपीएफ की दो बटालियन की मांग की है। सीधी-सिंगरौली के जंगल से सटा माड़ा का जंगल नक्सलियों का नया ठिकाना है। इससे पहले वे कान्हा के रास्ते बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में दाखिल होते रहे हैं। आखिर नक्सलियों ने माड़ा के जंगल को सेफ जोन क्यों बनाया है, सुरक्षा बल इससे निपटने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं?

4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर-दंतेवाड़ा में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए थे। इसके बाद छत्तीसगढ़ से सटे मप्र और महाराष्ट्र में हाईअलर्ट जारी किया गया। दरअसल, जब भी नक्सलियों के साथ सुरक्षाबलों की मुठभेड़ होती है वे अपने लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश करते हैं। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक मप्र के बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जिलों को नक्सली अपने सुरक्षित ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बालाघाट जोन के आईजी संजय कुमार कहते हैं कि नक्सलियों ने साल 2015-16 में महाराष्ट्र, मप्र और छत्तीसगढ़ (एमएमसी) क्षेत्र बनाया था। ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा से लेकर मनेंद्रगढ़ और कोरिया जिले तक फैला है। संजय कुमार के मुताबिक महाराष्ट्र का गोंदिया, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव और मप्र का बालाघाट (जीआरबी) नक्सलियों के एमसीसी क्षेत्र का एक हिस्सा है। इसके अलावा नक्सलियों ने मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ के भोरमदेव अभयारण्य जिसे केबी कहा जाता है, इसे डेवलप किया है।

महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इंटेलिजेंस से जुड़े दो बड़े अधिकारियों के मुताबिक 20 से 25 नक्सलियों का मूवमेंट सीधी-सिंगरौली से लगे माड़ा जंगल और मंडला के कान्हा नेशनल पार्क के कोर एरिया में देखा जा रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के एक अधिकारी ने खुद इन क्षेत्रों का भ्रमण कर इसकी पुष्टि की है। आईबी ने केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक कान्हा के जंगल के आसपास नए लोगों को देखे जाने की पुष्टि स्थानीय गांव वालों ने की है। ये पहले से सक्रिय नक्सलियों से अलग लोग हैं। इससे साफ है कि बस्तर में बढ़ते दबाव के बाद नक्सली इस क्षेत्र में शरण लेने आ रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के बाद माओवादियों की कमर टूट गई और उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। कई नक्सलियों के मारे जाने के बाद अब बड़ी संख्या में वे मप्र को अपने छिपने का ठिकाना बना रहे हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिलने के बाद मप्र सरकार सतर्क हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में नक्सलियों के नए कैडर तैयार हो रहे हैं। नक्सली दलम-2 के नाम से इसे विस्तार दे रहे हैं। यही वजह है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र से 2 बटालियन सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व बल) की मांग की हैं। दोनों बटालियन बालाघाट, मंडला और डिंडौरी के घोर नक्सल एरिया में तैनात होंगी। सीआरपीएफ बटालियन के साथ इन तीनों जिलों में 220 नए सड़क निर्माण की मांग भी की है। तीनों जिलों के नक्सली मूवमेंट एरिया में रिजिड कांक्रीट पेवमेंट से 220 नई सड़क बनेंगी। कान्हा टाइगर रिजर्व में नक्सलियों ने अपने नेटवर्क का विस्तार सुनियोजित तरीके से किया। 1 अक्टूबर 2018 को चिल्फी थाना क्षेत्र के शंभूपीपर गांव में दहशत फैलाने नक्सली पर्चे फेंके गए थे। उस पर्चे में जीआरबी डिवीजन कमेटी का जिक्र था। 30 जनवरी 2019 को चिल्फी थाना क्षेत्र में ही एनएच-30 पर नक्सलियों ने पेड़ गिराकर रास्ता रोक दिया था। इस दौरान नक्सलियों के फेंके पर्चे में एमएमसी (महाराष्ट्र-मप्र-छत्तीसगढ़) स्पेशल जोनल कमेटी का जिक्र था। 2 जून 2019 को मंडला के मोतीनाला के नेवसा तेंदूपत्ता फड़ को नक्सलियों ने जलाने के बाद, पेड़ पर पर्चा चस्पा कर केबी डिविजन बोड़ला एरिया कमेटी का जिक्र किया था।

पिछले दिनों गृहमंत्री अमित शाह ने आंकड़े पेश करते हुए बताया था कि देश में 2004 से 2014 तक नक्सली हमले में 6617 सुरक्षाकर्मी और आम लोग मारे गए थे। केंद्र में मोदी सरकार के 10 सालों में इसमें 70 प्रतिशत की कमी आई है। मोदी सरकार ये आंकड़ा 2004 तक सीमित करने में सफल रही है। गृहमंत्री शाह का दावा है कि मप्र सहित बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एक जिला छोड़कर महाराष्ट्र भी नक्सल समस्या से मुक्त हो चुके हैं।

● **रजनीकांत पारे**

पांच से सिमटकर एक जिले तक सीमित हुए नक्सली

मप्र में 2004 से 2014 तक नक्सलियों ने मंडला, डिंडौरी और बालाघाट के साथ सीधी, सिंगरौली जिले में अपनी गतिविधियां बढ़ाई थीं। 2008 में सिंगरौली में एक फैक्ट्री को निशाना बनाया था। सीधी, सिंगरौली के दो थानों में 2011 से लेकर 2014 के बीच नक्सली मूवमेंट को लेकर कुल 32 केस दर्ज किए गए थे। तब छत्तीसगढ़ तक फैला माड़ा का जंगल नक्सलियों का ठिकाना हुआ करता था। इस क्षेत्र में नक्सलियों को विस्तार दलम का नाम भी दिया जा रहा था। बाद में हुई पड़ताल के बाद नक्सलियों के मूवमेंट पर तो मुहर लगी, लेकिन विस्तार दलम की मीटिंग होने की बात प्रकाश में नहीं आई। इसके बाद सीधी, सिंगरौली से हॉक फोर्स के जवानों को ट्रांसफर कर बालाघाट भेज दिया गया था। इसी तरह मंडला, डिंडौरी में भी नक्सलियों का मूवमेंट वर्तमान में सीमित हो चुका है। कभी कभार मंडला के कान्हा नेशनल पार्क और डिंडौरी से अमरकंटक में नक्सलियों के होने की पुष्टि होती रही है।

मप्र देश के अन्य राज्यों की तरह युवाओं का प्रदेश है, लेकिन विडंबना यह है कि यहां की प्रशासनिक व्यवस्था उम्रदराज अधिकारियों-कर्मचारियों के हाथ में है। इसकी वजह यह है कि पिछले दो दशक से मप्र में सरकारी नौकरियों की रफ्तार कम हुई है। यानि प्रदेश में साल-दर-साल अधिकारी-कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उस अनुपात से भर्तियां नहीं हो रही हैं। इसका असर यह हो रहा है कि विभागों में जो उम्रदराज अधिकारी हैं, उन पर काम का बोझ भी बढ़ रहा है।

उम्रदराजों के हाथ में कामकाज...

मप्र में एक तरफ सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन पर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ स्थिति यह है कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों का टोटा है। पिछले दो दशक के दौरान प्रदेश में बड़ी कम संख्या में सरकारी भर्तियां हुई हैं। इस कारण राज्य मंत्रालय से लेकर जिलों के सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों, कर्मचारियों की संख्या कम हो गई है। भर्तियां न होने से शासकीय कार्यों का बोझ उम्रदराज अधिकारियों और कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस समस्या का समाधान करने के लिए अगले 5 साल में ढाई लाख सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया शुरू करवा दी है। जिससे माना जा रहा है कि विभागों को पर्याप्त संख्या में अधिकारी-कर्मचारी मिल जाएंगे।

वर्तमान समय में अगर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों का आंकलन करें तो मप्र के 73 फीसदी क्लास-वन अधिकारी और 53 फीसदी क्लास-टू अफसरों की उम्र 45 साल से ज्यादा है। इसके अनुपात में क्लास-वन युवा अफसरों की संख्या 27 प्रतिशत तो क्लास-टू कैटेगरी के अधिकारी 47 प्रतिशत हैं। आने वाले 5 साल में सभी कैटेगरी के एक लाख से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं। इस स्थिति ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। पिछली कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। ब्यौरा मिलने के बाद मुख्यमंत्री मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ बैठक करेंगे।

जानकारों की मानें तो ऐसी स्थिति इसलिए बनी क्योंकि भर्ती प्रक्रिया के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। इसका असर आने वाले समय में सरकार के कामकाज पर पड़ना तय है। जानकार ये भी मानते हैं कि युवाओं की भर्ती नहीं होने से आने वाले समय में नवाचार और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में कमी आएगी। मप्र के स्वास्थ्य विभाग में सिर्फ डॉक्टर्स की रिटायरमेंट उम्र 65 साल है। बाकी विभागों में 62 साल में कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। प्रदेश सरकार की 31 मार्च 2023 को जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में नियमित सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की संख्या कुल 5 लाख 90 हजार 550 है। मौजूदा साल में ये आंकड़ा और घट गया है, जिसकी रिपोर्ट इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने के बाद जारी की जाएगी। मप्र में 45 साल से कम उम्र वाले कुल अधिकारी-कर्मचारियों की संख्या 3 लाख 7 हजार 315 है, जो कुल कर्मचारियों का 52 फीसदी है। 46 से 61 साल की उम्र के कर्मचारियों की संख्या 2 लाख 83 हजार 235 हैं, जो कुल कर्मचारियों का 48 फीसदी है। युवा और उम्रदराज कर्मचारियों के बीच केवल 4 फीसदी का अंतर है। जानकारों के मुताबिक, ये रेश्यो 60:40 का होना चाहिए यानी 60 फीसदी युवा और 40 फीसदी उम्रदराज कर्मचारी-अधिकारी होने चाहिए।

क्लास-वन अधिकारियों की बात की जाए तो इनकी कुल संख्या 8 हजार 49 हैं। इनमें से 2135 यानी 27 फीसदी अधिकारी 45 साल से कम उम्र के हैं। 46 से 61 साल से ज्यादा उम्र वाले अधिकारियों की संख्या 5 हजार 914 है, जो कुल अधिकारियों की संख्या का 73 फीसदी है। क्लास-वन अधिकारी राजपत्रित अधिकारी होते हैं। प्रशासनिक मशीनरी को चलाने में इनका अहम रोल होता है। मप्र में क्लास-टू अधिकारियों की कुल संख्या 38 हजार 432 है।

5 साल में रिटायर होंगे एक लाख अधिकारी-कर्मचारी

मप्र के 73 फीसदी क्लास-वन अधिकारी और 53 फीसदी क्लास-टू अफसरों की उम्र 45 साल से ज्यादा है। इसके अनुपात में क्लास-वन युवा अफसरों की संख्या 27 प्रतिशत तो क्लास-टू कैटेगरी के अधिकारी 47 प्रतिशत हैं। आने वाले 5 साल में सभी कैटेगरी के एक लाख से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं। इस स्थिति ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। पिछली कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। ब्यौरा मिलने के बाद मुख्यमंत्री मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ बैठक करेंगे। जानकारों की मानें तो ऐसी स्थिति इसलिए बनी क्योंकि भर्ती प्रक्रिया के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। इसका असर आने वाले समय में सरकार के कामकाज पर पड़ना तय है। जानकार ये भी मानते हैं कि युवाओं की भर्ती नहीं होने से आने वाले समय में नवाचार और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में कमी आएगी।

क्लास-वन अधिकारियों से इनकी संख्या करीब साढ़े चार गुना ज्यादा है। ये भी राजपत्रित अधिकारी होते हैं। क्लास-वन अधिकारियों के बाद क्लास-टू अधिकारी प्रशासनिक मशीनरी को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनका काम सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का है। इनमें से 17 हजार 871 यानी 47 फीसदी कर्मचारियों की उम्र 45 से कम है जबकि 46 से 61 से ज्यादा उम्र वाले अधिकारियों की संख्या 20 हजार 561 है, जो कुल अधिकारियों का 53 फीसदी है।

मप्र में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 4 लाख 84 हजार 928 हैं। कर्मचारियों की ये सबसे ज्यादा संख्या है। सरकारी दफ्तरों के बाबू तृतीय श्रेणी कर्मचारी कहलाते हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में ये अहम भूमिका निभाते हैं। इस संवर्ग में युवा कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। 4 लाख कर्मचारियों में 45 साल से कम उम्र के कर्मचारियों की संख्या 2 लाख 60 हजार 927 है, जो कुल कर्मचारियों का 54 फीसदी है। जबकि 46 से 61 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों की संख्या 2 लाख 24 हजार 1 है, जो कुल कर्मचारियों का 46 फीसदी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की फौज भी उम्रदराज है। इस कैटेगरी में प्यून, ऑफिस बॉय, चौकीदार, सफाईकर्मी शामिल हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कुल संख्या 59 हजार 141 हैं। इनमें से 45 साल से कम उम्र वाले कर्मचारियों की संख्या 26 हजार 382 है, जो कुल कर्मचारियों का 45 फीसदी है। वहीं, 46 से 61 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों की संख्या 32 हजार 759 हैं, जो कुल कर्मचारियों का 55 फीसदी है। इनमें भी 51 से 55 साल के कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा 10 हजार 660 हैं।

मप्र में साल-दर-साल सरकारी अधिकारी-कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह नई भर्तियां करने की बजाय आउटसोर्स कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों को तैनात किया जा रहा है। इस तरह मंत्रालय से लेकर कलेक्टोरेट तक सरकारी सिस्टम ठेका कर्मियों के भरोसे हो गया है। जानकारों का कहना है कि सरकार में ठेका प्रणाली की यह घुसपैठ कभी भी प्रशासनिक ढांचे को बैठा सकती है। प्रदेश के सरकारी विभागों, उपक्रमों, निगम, मंडल, बिजली

कंपनियों, दुग्ध सहित अन्य विभागों में 4.25 लाख से अधिक ठेका श्रमिक और आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। मंत्रालय में ही कर्मचारियों की संख्या जिस गति से हर महीने घट रही है, उस गति से बढ़ नहीं रही है। मंत्रालय में 2539 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 1345 कर्मचारी ही रह गए हैं। जिनमें सबसे ज्यादा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के हैं। यही स्थिति सरकार के अन्य लगभग सभी कार्यालयों की है। जहां नियमित कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कुल स्वीकृत पदों से आधी से भी कम बची है। प्रदेश में पिछले एक-डेढ़ दशक में सरकारों ने रिक्त पदों को भरने की बजाय ठेका प्रणाली से प्रशासनिक तंत्र को चलाने की जुगाड़ बैठाई थी। अब ज्यादातर विभागों में सीधी भर्ती वाले कर्मचारी उतने भी नहीं बचे कि आगे प्रशासनिक तंत्र को खींचा जाए। यही स्थिति रही तो प्रशासनिक तंत्र कभी भी बैठ सकता है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों में खाली पदों की गणना शुरू कर दी है। जिसके आधार पर सरकार अगले 5 साल के भीतर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करेगी। कर्मचारी नेताओं के अनुसार मौजूदा स्थिति में राज्य में करीब 2.50 लाख नियमित कर्मचारी बचे हैं। 2026 तक यह संख्या घटकर 1.50 लाख तक रह जाएगी। इसके अनुपात में संविदा कर्मचारियों की संख्या 3 लाख से ज्यादा है। जबकि आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या का कोई प्रमाणित आंकड़ा किसी विभाग के पास नहीं है, फिर भी पंचायत, वार्ड कार्यालयों से लेकर मंत्रालय तक करीब 1.25 लाख कर्मचारी ठेकादारों के माध्यम से सरकार में काम कर रहे हैं।

प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की कमी का आंकलन इसी से किया जा सकता है कि मंत्रालय में प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक 2539 पद स्वीकृत हैं। जिनके विरूद्ध 1345 पद ही भरे हैं। खास बात यह है कि प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त सचिव के 3 पद, उप सचिव के 14 पद पूरी तरह से खाली हैं। अवर सचिव के 57 पदों के विरूद्ध सिर्फ 18 अधिकारी बचे हैं, जबकि 39 पद खाली हैं। सरकार ने तंत्र को चलाने के लिए मंत्रालय सेवा के अधिकारियों की जगह मैदानी अधिकारी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को पदस्थ कर रखा है। कर्मचारी नेता सुभाष वर्मा का कहना है कि अटैचमेंट और आउटसोर्स के जरिए ज्यादा वक्त तक प्रशासनिक तंत्र को नहीं चलाया जा सकता है। सरकार को चाहिए कि पदोन्नति का रास्ता निकाले और नियमित भर्तियां शुरू करे। कार्यालयों में अनुभवी कर्मचारियों का टोटा है। बाहरी लोग कुछ भी कर रहे हैं। तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।

● **सुनील सिंह**

मप्र में अधिकांश पद खाली

मप्र में अधिकारियों-कर्मचारियों की स्थिति यह है कि अधिकांश पद खाली पड़े हैं। 19 नवंबर की स्थिति में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के 3 पद स्वीकृत हैं जो खाली पड़े हैं। वहीं उप सचिव के भी सभी 14 पद खाली हैं। अवर सचिव के 57 पदों में से 17 भरे हैं और 40 खाली हैं। स्टाफ ऑफिसर के 18 पदों में 10 भरे हैं 8 खाली हैं। अनुभाग अधिकारी के 143 पदों में से 114 खाली, निज सचिव के 60 पदों में से 25 खाली, सहा. अनुभाग अधि. के 338 पदों में से 237 खाली, सहा. ग्रेड-2 के 335 पदों में से 118 खाली, सहा. ग्रेड-3 के 602 पदों में से 131 खाली, निज सहायक के 128 पदों में से 62 खाली, शीघ्र लेखक के 53 पदों में से 21 खाली, स्टेनो टायपिस्ट के 84 पदों में से 43 खाली, तकनीकी श्रेणी के 69 पदों में से 59 खाली और चतुर्थ श्रेणी के 635 पदों में से 319 खाली हैं।

शिकारियों को सजा दिलाने कानूनी पक्ष होगा मजबूत

मप्र में सरकार की सख्ती के बावजूद वन्य जीवों के शिकार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आलम यह है कि किसी मामले में जब भी शिकारी पकड़े जाते हैं, वे कमजोर कानूनों का फायदा उठाकर बच निकलते हैं। इसे लेकर मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक वीएन अंबाडे ने मैदानी अधिकारियों के लिए सभी वन इकाइयों को एडवाइजरी जारी की है। जिसके अनुसार वन्यजीवों के शिकार में अब आरोपित को जमानत न मिल पाए इसके लिए वन विभाग आरोपित का प्रकरण मजबूती के साथ न्यायालय में रखेगा।

गौरतलब है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की मौत के बाद वन विभाग ने ऑपरेशन वाइल्ड ट्रेप अभियान शुरू किया है। इस अभियान के जरिए जंगली जानवरों को फंदा, लेग होल्ड ट्रेप और करंट लगाकर शिकार करने वाले शिकारियों की धरपकड़ की जाएगी। यह अभियान 1 दिसंबर से शुरू होगा और 31 जनवरी तक चलेगा। इस अभियान में वन विभाग अमले के साथ स्थानीय पुलिस के अलावा बिजली विभाग की मदद भी ली जाएगी। अभियान की मॉनिटरिंग वन मुख्यालय स्तर पर होगी। वहीं वन्यजीवों के शिकार में अब आरोपित को जमानत न मिल पाए इसके लिए वन विभाग आरोपित का प्रकरण मजबूती के साथ न्यायालय में रखेगा। दरअसल, हाईकोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत जमानत देने के मापदंड, भारतीय दंड संहिता (भारतीय न्याय संहिता) के तहत अन्य अपराधों की तुलना में अधिक कठोर हैं। यह नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के प्रविधानों के समानांतर है, जो जमानत के लिए सख्त शर्तें भी लगाता है। एडवाइजरी में हाईकोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि वन्यजीव अपराधों में जमानत याचिकाओं को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए और न्यायालय के समक्ष एकत्रित साक्ष्य को सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत कर जमानत का विरोध अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अंबाडे ने एडवाइजरी में यह भी कहा है कि हाल ही में प्रदेश में दर्ज कुछ वन्यजीव अपराध प्रकरण की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को, भविष्य में समान प्रकृति के वन अपराधों में शासन हित में जमानत याचिकाओं के निरस्तीकरण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

सिवनी कटंगी रोड पर संदिग्ध व्यक्ति सुनील खंडाते को पकड़ा गया था और उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से बाघ की 49 हड्डियां, 14 नाखून और 31 मूंछ के बाल थे, जिन्हें साक्ष्य के तौर पर विधिवत जब्त किया गया। आरोपी सुनील खंडाते द्वारा चौथी बार हाईकोर्ट में यह जमानत याचिका दायर की गई थी जिस पर आदेश पारित करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि जिस वन्यप्राणी का शिकार किया गया है, वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2022 के अनुसूची एक का वन्य प्राणी है। न्यायालय ने कहा कि बाघ जैसे वन्य प्राणी के शिकार की घटना को सामान्य अपराधों के समान नहीं माना जा सकता क्योंकि ऐसा अपराध प्रकृति और वन के लिए खतरा है। सुनील खंडाते एवं अन्य के विरुद्ध इस प्रकरण में हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2024 को आरोपित की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई थी।

मप्र को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। लेकिन बाघों की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में सबसे अधिक बाघों की मौत यहीं पर हुई है। पिछले 12 साल में सबसे अधिक बाघों ने मप्र में ही दम तोड़ा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के आंकड़ों में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल फिर प्रदेश में सबसे अधिक 38 बाघ मप्र की धरती पर दम तोड़ चुके हैं। बाघों की मौत के मामले में महाराष्ट्र दूसरे जबकि कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के आंकड़े बता रहे हैं कि 2012 से 2024 तक भारत में सबसे अधिक बाघों की मौत मप्र में हुई हैं। इन 12 साल में कुल 355 बाघों की दहाड़ बंद हो चुकी है। यानी हर साल औसत 30 बाघ दम तोड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां पिछले 12 सालों में 261 बाघों की मौत हुई है। 179 बाघों की मौत के साथ कर्नाटक तीसरे जबकि 132 नंबर के साथ उत्तराखंड चौथे नंबर पर है। 2024 का साल पूरा होने में अभी सवा महीने से अधिक का समय बचा हुआ है और इस साल प्रदेश में 38 बाघों की मौत हो चुकी है। जबकि दूसरे नंबर पर रहे महाराष्ट्र में 19 जबकि कर्नाटक में 11 बाघों की मौत हुई है। उत्तराखंड में 9 बाघों की मौत हुई है। बाघों की मौत मप्र में हमेशा सियासत की वजह रही है। टाइगर स्टेट का तमगा रखने वाले मप्र में लगातार बाघों की मौत अब एक चिंतनीय विषय बन गया है। कभी शिकार, हादसा या आपसी लड़ाई में लगातार टाइगर की मौत हुई है। लेकिन फिर भी इस पर लगाम नहीं लग पा रहा है। इस बीच प्रदेश में 11 हाथियों की भी मौत हो गई। वन्यजीवों की लगातार मौत पर सियासत तय मानी जा रही है।

● **विकास दुबे**

जंगली हाथियों की सुरक्षा के लिए सैटेलाइट कॉलरिंग सफल

उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगली हाथियों के संरक्षण के लिए सैटेलाइट कॉलरिंग तकनीक का प्रयोग सफल रहा है। मार्च 2024 में शहडोल के जयसिंहनगर वन क्षेत्र से रेस्क्यू किए गए एक जंगली हाथी को सैटेलाइट कॉलर लगाकर ताला वन परिक्षेत्र की दमना बीट में छोड़ा गया। इसके माध्यम से हाथी के मूवमेंट पर नजर रखी गई, जो संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह तकनीक जंगली हाथियों के मूवमेंट और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करती है। इससे न केवल हाथियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी, बल्कि मानव-हाथी संघर्ष को कम करने में भी सहायता मिलेगी। अब सरकार इस तकनीक को प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व और हाथी संरक्षण क्षेत्रों में भी लागू करने की योजना बना रही है। इस प्रक्रिया के दौरान क्षेत्र संचालक डॉ. नितिन गुप्ता, सहायक संचालक ताला, और वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम मौजूद रहीं। अधिकारियों ने बताया कि यह तकनीक हाथियों के प्राकृतिक वास के अध्ययन और संरक्षण की दिशा में एक अहम पहल है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगली हाथियों की सैटेलाइट कॉलरिंग पहली बार की गई है, जो अन्य टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में इस तकनीक के उपयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इससे न केवल हाथियों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि उनके संरक्षण में नए आयाम जोड़े जाएंगे।

दोढन डैम निर्माण की मिली अनुमति

पार्वती, कालीसिंध और चंबल परियोजना में मप्र में बनेंगे 22 बांध

मप्र सरकार पार्वती, कालीसिंध और चंबल (पीकेसी) परियोजना के तहत प्रदेश में 22 बांध बनाएगी। इससे मप्र के चंबल और मालवा क्षेत्र के 13 जिलों को लाभ मिलेगा। इससे मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड और श्योपुर में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। औद्योगिक क्षेत्र वाले जिलों इंदौर, उज्जैन, धार, आगर-मालवा, शाजापुर, देवास और राजगढ़ के औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा। पहले चरण में 13 बांध और दूसरे चरण में 9 बांध बनाए जाएंगे। दोनों चरणों का काम एकसाथ किया जाएगा। इसको लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समीक्षा बैठक करेंगे। मप्र में इसके तहत गांधीसागर बांध की अपस्ट्रीम में चंबल, शिप्रा और गंभीर नदी पर प्रस्तावित छोटे बांधों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना में 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी और अपनी-अपनी सीमा में बनने वाले प्रोजेक्ट की लागत का सिर्फ 10 प्रतिशत मप्र और राजस्थान देंगे। परियोजना 5 वर्ष के भीतर पूरी होगी। इसकी लागत लगभग 75 हजार करोड़ रुपए है। इसमें मप्र में 35 हजार करोड़ रुपए के निर्माण कार्य करवाए जाएंगे।

भारत के पहले नदी जोड़ो प्रोजेक्ट केन-बेतवा लिंक के लिए केन नदी पर प्रस्तावित दोढन डैम का टेंडर पिछले छह माह से जलशक्ति मंत्रालय में फंसा हुआ था। केन-बेतवा लिंक परियोजना के पहले चरण में दोढन डैम का निर्माण किया जाएगा और इसकी मंजूरी के लिए 4 हजार करोड़ का टेंडर केंद्र सरकार को 6 माह पहले भेजा गया था, जिसकी अब जाकर जलशक्ति मंत्रालय से मंजूरी मिली है। सूत्र बताते है कि जलशक्ति मंत्रालय के अधीन दो कंपनियां कार्यरत हैं। एक टेंडर जारी करेगी, तो दूसरे इस परियोजना का सर्वे कराएगी और डीपीआर को स्वीकृति देगी, लेकिन केंद्र की इन दोनों की कंपनियों में टेंडर जारी करने को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके कारण 4 हजार करोड़ का टेंडर अभी तक जारी नहीं हो सका था। इस परियोजना को 2029 तक निर्मित किया जाना है।

गौरतलब है कि केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर मप्र और उप्र के बीच वर्ष 2005 में अनुबंध हुआ था। उसके बाद प्रक्रिया धीमी पड़ गई थी। तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों राज्यों के बीच वर्ष 2021 में समझौता हुआ। 44 हजार 605 करोड़ रुपए की इस परियोजना को पूरा करने में छह वर्ष का समय लगना अनुमानित है। इस परियोजना में केंद्र सरकार 90 प्रतिशत राशि देगी। दोनों राज्य सरकारों को कुल लागत की पांच-पांच प्रतिशत राशि देनी होगी। परियोजना पूरी होने के बाद मप्र और उप्र में साढ़े आठ लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई क्षमता का विकास होगा तो लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी। केन-बेसिन से उप्र के 2.27 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, केन-बेसिन से मप्र में 4.47 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होगी, जबकि बेतवा बेसिन से मप्र में सिंचाई का क्षेत्रफल 2.06 लाख हेक्टेयर होगा और बिजली मप्र के हिस्से में आएगी।

केंद्र तथा मप्र सरकार की महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना के टेंडर अभी तक नहीं हो सके हैं। जबकि दोढन डैम का निर्माण करने के लिए 4 हजार करोड़ का टेंडर जारी होने की प्रत्याशा में जलशक्ति मंत्रालय में छह महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके कारण बांध सहित अन्य कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं कराए जा सके हैं। केन-बेतवा लिंक परियोजना से मप्र की करीब 2.41 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए सिंचाई प्रस्तावित है। वहीं, उप्र में इससे 1.50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। करीब 8 लाख लोगों को पेयजल के लिए पानी भी मुहैया कराया जाएगा। उप्र के बुंदेलखंड सहित दतिया, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ आदि जिलों में 21 किमी में लिंक चैनल का निर्माण किया जाना है। यानि 241 किमी में नहरें निर्मित कराई जाएगी। करीब 6 हजार एकड़ भूमि का उपयोग डैम सहित नहरों के निर्माण और जलभराव क्षेत्र में होगा। इसके लिए 271 हेक्टेयर निजी भूमि भी अधिग्रहित की जानी है, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू नहीं करा सका। प्रभावित परिवारों की भूमि अधिग्रहण किए जाने के एवज में 1150 करोड़ की मुआवजा राशि बांटी जाना है। साथ ही 41 छोटे-बड़े जलाशयों में पानी भरने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए भी अभी तक टेंडर जारी नहीं किए गए हैं। उधर, 22 गांव इस परियोजना में आ रहे हैं, जिनका विस्थापन किया जाना है।

वहीं केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत केन नदी पर बनने वाले दोढन बांध और बांध से बेतवा नदी तक लिंक नहर का निर्माण केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी (केबीएलपीए) को करना है। बांध निर्माण के लिए तो भू अधिग्रहण की कार्रवाई को पूरा कर लिया गया है, लेकिन 221 किमी लंबी नहर बनाई जा रही है, जो कि 15-20 साल पुराना सर्वे था। वहां पर कॉलोनी, हाईवे आदि बन चुके हैं। मुख्य सचिव अनुराग ने ने इसमें परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया है और इस सर्वे पर पुन: विचार करने के लिए केंद्र सरकार से कहा है।

लिंक नहर का निर्माण केन नदी पर दोढन बांध से बेतवा नदी पर बरुआ सागर के पास किया जाना है। लिंक कैनाल (नहर) छतरपुर टीकमगढ़, निवाड़ी और उप्र के झांसी जिलों की सीमा से होकर गुजरेगी। इसमें सबसे लंबा हिस्सा छतरपुर जिले में बनाया जाना है। छतरपुर जिले में लिंक कैनाल 49 गांवों से होकर गुजरेगी। इसके लिए 165 हेक्टेयर निजी जमीन और 1134 हेक्टेयर शासकीय भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। भू-अधिग्रहण अधिनियम के तहत जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। नहर निर्माण में उपयोग होने वाली जमीन के लिए छतरपुर जिला प्रशासन ने धारा-11 (ए) के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है। धारा-11 (ए) का प्रकाशन मार्च 2024 में कर दिया गया है। अब अगले चरण में धारा-19 के तहत भूस्वामियों के नाम के साथ सूचियों का प्रकाशन किया जाना है। मुख्य नहर के निर्माण के लिए केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी ने झांसी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय की स्थापना की है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

विकास का सत्यानाश...
दिखाया पेरिस बनाने का ख्वाब
बूचड़खाने से भी बदतर भोपाल

मप्र में डबल इंजन की सरकार विकास के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है। लेकिन जिन सड़कों को विकास का वाहक कहा जाता है वे सड़कें विकास का सत्यानाश कर रही हैं। प्रदेशभर की बात तो छोड़िए, राजधानी भोपाल की सड़कें इस कदर जर्जर, बदहाल हैं कि सड़कों पर गड्ढे नहीं, बल्कि गड्ढों में सड़कें समा गई हैं। जिसको देखकर लोग कहने को मजबूर हो रहे हैं कि भोपाल को पेरिस बनाने का सपना दिखाया गया, लेकिन यह तो बूचड़खाने से भी बदतर हो गया है।

● राजेंद्र आगाल

देश की सबसे खूबसूरत राजधानी का तमगा प्राप्त मप्र की राजधानी भोपाल विकास को तरस रही है। एक तरफ शहर में विकास की बड़ी-बड़ी योजनाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ की सड़कें इस कदर बदहाल हैं कि उन पर चलना तो दूर देखकर ही डर लगता है। सड़कों पर चलने वाला हर व्यक्ति पीड़ित है। सड़कों पर गड्ढे नहीं, बल्कि गड्ढों में सड़कें समां गई हैं। पीडब्ल्यूडी की बनाई गई शहर की प्रमुख सड़कों में से 70 फीसदी तो गारंटी पीरियड में ही खराब हो गईं। यही हाल नगर निगम की सड़कों के हैं। भोपाल में नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की 2593 किमी से ज्यादा लंबी सड़कें हैं। 240 से ज्यादा सड़कें टूटी-फूटी हालत में हैं। कोई 30 प्रतिशत तो कोई 80 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त है। 75 किमी सड़कें तो ऐसी हैं, जिनमें गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। 67 किमी से ज्यादा लंबी एप्रोच रोड भी उखड़ चुकी है। इन सड़कों की मरम्मत करने की बजाय इनके गड्ढों को मिट्टी से भरने की कोशिश की गई है, जिससे प्रदूषण फैल रहा है।

देश में अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ख्यात मप्र की राजधानी भोपाल कभी राजाभोज, कभी दोस्त मोहम्मद खान, कभी गोंड महारानी कमलापति, कभी आबिदा सुल्तान, कभी भोपाल गैस त्रासदी के लिए सुर्खियों में रही है। लेकिन इन दिनों यह शहर अनियंत्रित तथा भेदभावपूर्ण विकास और गांवों से भी जर्जर सड़कों के कारण सुर्खियों में है। यह स्थिति तब है जब शहर की करीब 25 लाख आबादी से भरपूर टैक्स लिया जा रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि सर्वाधिक टैक्स देने वाली निजी कॉलोनियों और वहां के लोगों को सुविधाओं के नाम पर छला जा रहा है। आमजन से विभिन्न प्रकार के विकास का टैक्स लेकर वीआईपी कॉलोनियों को सजाया और संवारा जा रहा है। सरकार से लाखों रुपए की पगार लेने वाले साहेबान सरकारी कॉलोनियों में ऐश कर रहे हैं, वहीं टैक्स देने वाले आम लोग धूल, कचरा और गड्ढ़ों से युक्त कॉलोनियों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में विकास के लिए स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सरकार राजधानी को स्मार्ट बनाने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन शहर के अंदरूनी क्षेत्रों की सड़कें इस कदर जर्जर हो गई हैं कि लोग उन्हें देखकर डरने लगे हैं। नगर निगम के पास लगभग 4000 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव है, जबकि कुछ प्रमुख सड़कों में से 573 किलोमीटर की देखरेख पीडब्ल्यूडी द्वारा की जाती है। राजधानी के कुछ इलाके जैसे गोविंदपुरा क्षेत्र का साकेत नगर, शक्ति नगर, पिपलानी के अलावा करोंद, नेहरू नगर, बैरागढ़, गांधीनगर और कोलार की कॉलोनियों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। सबसे ज्यादा हालत खराब तो साकेत नगर, शक्ति नगर, करोंद और कोलार की कॉलोनियों की हैं। सड़के दुरुस्त रहें, इसके लिए निर्माण एजेंसी की सिविल शाखा जिम्मेदार है। शहर की अंदरूनी गलियों, मोहल्ले की सड़कों में कीचड़ अधिक है, इसके लिए संबंधित जोन के कार्यपालन यंत्री, डिप्टी सिटी इंजीनियर, सहायक यंत्री सिविल जिम्मेदार है।

गड्ढ़े और धूल से भरी सड़कें

मप्र में इस साल मानसून की बारिश के बाद राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में सड़कों की बखिया उधड़ चुकी हैं। लोग परेशान हैं। दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं लेकिन अधिकारी और नेता हैं कि अब भी राजनीति में उलझे हुए हैं। सरकारी विभाग एक-दूसरे को आरोप लगाने में व्यस्त हैं। आलम यह है कि मानसून की विदाई के बाद पूरे प्रदेश की सड़कों का हाल खराब है। राजधानी भोपाल की सड़कें भी उखड़ चुकी हैं। जगह-जगह गड्ढ़े हैं। गड्ढ़े और उड़ती धूल लोगों को परेशान कर रही है। राजधानी में ज्यादातर सड़कें बारिश के कारण उखड़ गई हैं। बारिश थमने के बाद कुछ गड्ढ़ों में मिट्टी भर दी गई थी जो अब धूल के गुबार में सामने आ रही है। लेकिन खराब सड़कों को दुरुस्त करने की जगह जिम्मेदार एक-दूसरे को जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कई बार नगर निगम कमिश्नर को गारंटी पीरियड में खराब हुई सड़कों की मेंटेनेंस फार्म कॉन्ट्रेक्टर से कराने के लिए कहा था। इसके बाद भोपाल की महापौर मालती राय ने भी खराब सड़कों पर संज्ञान लिया। निगम की सड़कों की जगह पीडब्ल्यूडी को सड़कों को सुधारने की बात कही। उधर, विभागीय मंत्री के साथ बैठक में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कह चुके हैं कि हम सड़कों को सुधार रहे हैं, नगर निगम की सड़कों की हालत खराब है। यही नहीं पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर बिना अनुमति के सीवेज, पानी और गैस पाइपलाइन डालने के लिए गड्ढ़े करने पर ऐतराज जताया और तुरंत मरम्मत कराने के लिए कहा। मतलब साफ है नगर निगम के अंदर महापौर और अध्यक्ष उलझे हुए हैं और बाहर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा- गारंटी पीरियड में खराब हुई राजधानी की सड़कों को सुधारने की जिम्मेदारी नगर निगम से संबंधित ठेकेदार की है। भोपाल महापौर का कहना है कि यह पीडब्ल्यूडी का विषय है। खराब सड़कों को लेकर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के बीच विवाद बढ़ रहा है।

कॉलोनियों में विकास की राह ताक रहे क्षेत्र के लोग

भोपाल की सड़कों की बदहाली की यह तस्वीर तब है, जब नगर निगम को राजधानी में इस बार 33 प्रतिशत अधिक राजस्व मिला है। लेकिन विडंबना यह है कि शहर की कॉलोनियां विकास की राह ताक रही हैं। शहर में दो बड़े प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी और मेट्रो रेल चल रहे हैं। पूरे काम या तो आधे-अधूरे हैं या फिर गड्ढ़े में हैं। जो प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं वे भी बदहाल हैं। खासकर स्मार्ट सिटी की सड़कों का हाल सबसे अधिक बदहाल है। मुख्यमंत्री निवास से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर बने स्मार्ट रोड का हाल देख लीजिए। पहली बारिश के मौसम में ही यह सड़क उखड़ गईं। बारिश की वजह से सड़कें खराब होती हैं लेकिन यह कोई आम सड़क नहीं है। इसके निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। वहीं मेट्रो प्रोजेक्ट का भी हाल बेहाल है। मेट्रो रूट का सिविल वर्क ही अभी पूरा नहीं हो पाया है। दरअसल मेट्रो रूट की बाधाएं तो एक अलग बात है, लेकिन इसमें बड़ा मुद्दा बजट के इंतजाम का है। बता दें कि 7 साल पहले 2014 में भोपाल मेट्रो की लागत 6,941 करोड़ आंकी गई थी, लेकिन ये बढ़कर अब 9,000 करोड़ होने का अनुमान जताया जा रहा है। क्योंकि इन 7 सालों में काफी बदलाव हुआ है, यहां तक कि इस दौरान कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी महंगा हुआ है। रुपयों के मुकाबले डॉलर भी मजबूत हुआ। अब साल दर साल जिस तेजी से पेट्रोलियम व अन्य चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में प्रोजेक्ट लागत बढ़ने की आशंका साफ नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का बजट और मेट्रो के लोन आदि का गणित बिगड़ना स्वाभाविक है। राजधानी की खूबसूरती पर दाग लगा रही सड़कों की तस्वीरें अभी भी नहीं बदल पाई हैं। अभी भी 60 प्रतिशत सड़कें खराब हालत में हैं, जबकि 6 से 20 अक्टूबर के बीच में सड़कें 100 प्रतिशत सुधर जानी चाहिए थीं।

मंत्री कृष्णा गौर का क्षेत्र बदहाल

राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। हालांकि अभी मंत्री कृष्णा गौर ने मिनाल रेसीडेंसी से जेके रोड तक एक शानदार सड़क बनवाई है। लेकिन बाकी की सड़कों का हाल बेहद ही खराब है। शक्ति नगर, साकेत नगर,

गड्ढ़ों से भरा रास्ता, दिन भर धूल से वास्ता

राजधानी में कई जगह विकास कार्यों के लिए सड़क की खुदाई तो कर दी, लेकिन सड़क नहीं बनाई। अब नीचे से उठने वाली धूल मिट्टी पुल के ऊपर से गुजरने वाले वाहन चालकों की आंखों में किरकिरी बन रही है। साथ ही नाक के रास्ते यही धूल शरीर में भी पहुंच रही है। हालांकि औपचारिकता के लिए पानी का छिड़काव तो कराया जा रहा है, लेकिन इसमें भी कंजूसी बरती गई। इससे अब भी सड़कों से धूल के गुबार उठ रहे हैं। उधर शहर में जलता कचरा भी प्रदूषण का ग्राफ तेजी से बढ़ा रहा है। कई स्थानों पर एक साथ कचरा जलने से हर तरफ धुआं-धुआं दिखता है। कई इलाकों में तो सिर्फ मिट्टी और चूरी डालकर गड्ढे भर दिए गए। इस कारण धूल के गुबार उड़ रहे हैं और एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। गड्ढों और खराब सड़कों के कारण अयोध्या बायपास, कोलार, हमीदिया रोड जैसे भारी ट्रैफिक वाले इलाकों में रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में एक विडंबना यह भी है कि यहां सबसे अधिक विकास वीआईपी क्षेत्रों में होता है। इसकी वजह यह है कि इन क्षेत्रों में मंत्री, विधायक, सांसद, आईएएस, आईपीएस के सरकारी आवास हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकार जिन अफसरों के आवास पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च करती है, उनमें से 70 फीसदी के अपने मकान भोपाल में हैं। लेकिन सरकारी सुविधाओं के आदी हो चुके ये अफसर अपने निजी मकान में जाने की बजाय सरकारी मकान में ही रहते हैं। इसकी वजह यह है कि जिन क्षेत्रों में इनके सरकारी मकान हैं, यानी चार इमली, 74 बंगले और 45 बंगले में सबसे अधिक विकास पर खर्च होता है। यहां की सड़कें सालभर चकाचक रहती हैं। घरों में बराबर पानी आता है और सड़कों की सफाई निरंतर होती है।

बागसेवनिया, अयोध्या नगर में सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी बजट का इंतजार कर रहे हैं। शहर में कांग्रेस की परिषद रही हो या भाजपा की, सड़कों और चौराहे के नाम अपने-अपने हिसाब से बदले जाते रहे हैं। इस परिषद में भी सड़क-चौराहों के नाम बदले जा रहे हैं लेकिन सड़कों की सूरत नहीं बदली। सड़कों की खस्ता हालात को लेकर भोपाल की महापौर मालती राय का कहना है कि बारिश के दौरान खराब हुई सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। सड़क की मरम्मत का काम समय सीमा में किया जाएगा।

यहां की सड़कें बेहाल

नर्मदापुरम रोड पर रहने वाले 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के लिए शहर की तरफ आने के लिए यह एकमात्र रोड है। इन लोगों के लिए ये गड्ढे रोज की मुसीबत हो गए हैं। मिसरोद से रानी कमलापति स्टेशन तक 5000 से ज्यादा गड्ढे हैं। फरवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में नर्मदापुरम रोड से बीआरटीएस हटाने का काम शुरू हुआ। मई-जून में कॉरिडोर तोड़ा। इसके बाद सावरकर सेतु से मिसरोद के आगे तक सड़क की नए सिरे से मरम्मत की गई। अब सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हैं। बारिश में पानी भरा रहता है। वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इस सड़क की मरम्मत गर्मी में की गई थी। जिसमें गिट्टी की एक लेयर डाली। अफसरों व ठेकेदारों ने महज दो दिनों में काम निपटा दिया। अब सड़क पर बारीक गिट्टियां निकल गई हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं का अंदेशा बना हुआ है। निर्माण एजेंसियों के अफसरों और ठेकेदारों ने वल्लभ भवन के आसपास की सड़कों तक को नहीं छोड़ा। पीएफ कार्यालय चौराहे से वल्लभ भवन तक की मुख्य सड़क उखड़ गई।

जानकारी के मुताबिक, शहर में नगर निगम की 2000 किमी से ज्यादा लंबी सड़कें हैं। 225 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। डीआरएम ऑफिस से सांची पार्लर तक की सड़क 80 फीसदी खराब हो चुकी है। संत हिरदाराम नगर से साधु वासवानी स्कूल रोड 75, बीडीए मल्टी से किलोल पार्क 80, टीला जमालपुरा रोड 75, गिनौरी रोड 60, निर्मला देवी रोड कोलार 50, शंकर दयाल चौराहे से लालघाटी होशंगाबाद रोड 20 फीसदी तक खराब हो चुकी है। भोपाल में पीडब्ल्यूडी की कुल 268 सड़कें 573 किलोमीटर की हैं। 400 किमी सड़कें परफॉर्मेंस गारंटी में है। 173 किमी सड़कें साधारण मरम्मत के अंतर्गत आती हैं। बारिश में 14 मार्ग की 22 किमी की लंबाई में 523 वर्गमीटर में गड्ढे पाए गए हैं। 3 प्रतिशत सड़कों में गड्ढे मिले हैं। रॉयल मार्केट से मॉडल स्कूल की सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। इसके अलावा मंदिर से होटल पैलेस मार्ग, भोपाल टॉकीज से रेलवे क्रॉसिंग मार्ग, अग्रसेन चौराहा से शाहजहांनाबाद मार्ग, स्टेट बैंक चौराहा से करबला, मनीषा मार्केट से हबीबगंज थाना सुभाष स्कूल, कलियासोत मुख्य नहर से आकृति इको सिटी, जेके अस्पताल तिराहे से दानिश नगर चौराहा और आरआरएल से साकेत नगर तक सड़कों की हालत बदहाल है।

सड़कों की बदहाली पर मंत्री भी सख्त

सड़कों की बदहाली को देखते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने सुध ली। मंत्री ने मंत्रालय में

आला अफसरों के साथ बैठक की। सड़कों की वस्तुस्थिति को जानने का प्रयास किया। साथ ही प्राप्त शिकायतों का समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए हैं। भोपाल नगर निगम के अफसरों ने बैठक में जानकारी दी कि शहर में कुल 2020 किमी लंबी सड़कें हैं। अभी की स्थिति में कुल 225 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। सबसे ज्यादा 80 प्रतिशत तक डीआरएम ऑफिस और संत हिरदाराम नगर वाली सड़कें खराब हैं। निगम ने सड़कों को सुधारने के लिए 50 करोड़ का प्रस्ताव विभाग को सौंपा। विजयवर्गीय ने कहा कि राजधानी की सड़कों का मरम्मत कार्य प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सड़कों की दुर्दशा पर मोहन सरकार को घेरा है। उमंग ने एक्स पर तस्वीर पोस्ट कर लिखा है कि ये मप्र की राजधानी भोपाल की सड़कों का हाल है। प्रदेश की सड़कों पर अनगिनत गड्ढे भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की खुली गवाही दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, थोड़ी बारिश क्या हुई, राजधानी भोपाल की मुख्य सड़कें नाले और गड्ढे में तब्दील हो गईं। देखा जाए तो भोपाल की सड़कें हर 3 साल में बनती हैं। फिर भी बारिश आते-आते हिचकोले देर हो जाती हैं। उमंग ने आगे लिखा है कि सड़क निधि के लिए 1150 करोड़ और मरम्मत के लिए 730 करोड़ रुपए का बजट तो तैयार हुआ। लेकिन इतने हजार करोड़ रुपए खर्च कहां हुए। सड़कों के नाम पर नाले बनाने में? लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह जी, सड़कों की ऐसी बदहाल स्थिति का जिम्मेदार कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से भी अच्छी बताते नहीं थकते थे। अब 7 महीने में ऐसा क्या हो गया कि सड़कों ने मुंह फाड़ दिए। उमंग ने फिर लिखा है कि राजधानी की सड़कें सुधारने का काम भोपाल नगर निगम का है, पीडब्ल्यूडी

का या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का, जिसका भी हो उसे इस काम की पहल करना चाहिए। क्योंकि, शहर की व्यवस्था कैसी है इसका पता तो सड़कों की हालत से ही लगता है। भाजपा सरकार की लापरवाही और कॉन्ट्रेक्टर के खराब काम का खामियाजा, प्रदेश की बेगुनाह जनता भुगत रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? तत्काल सड़कों की मरम्मत कराई जाए।

विकास में भेदभाव

भोपाल भ्रमण करने पर ये साफ नजर आता है कि वाकई मप्र अजब है, गजब है। इसकी वजह यह है कि एक तरफ भोपाल सुंदर, आकर्षक, हरी-भरी और व्यवस्थित कॉलोनियों वाला शहर नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ विकास के गड्ढ़े नजर आते हैं। हैरानी की बात यह है कि राजधानी में विकास का यह भेदभाव आज से नहीं बल्कि वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन इस पर न तो शासन और न ही प्रशासन ने कोई कदम उठाया है। हैरानी की वजह यह है कि मानसून के कारण जब पूरे शहर की सड़कें खराब होती हैं तो सड़कों की मरम्मत और गड्ढ़ों की भराई में भी भेदभाव इस कदर होता है कि वीआईपी क्षेत्र चकाचक नजर आता है, जबकि आम आदमी गड्ढ़े में। यह स्थिति तब है जब शहर की आम कॉलोनियों के लोग सबसे अधिक टैक्स दे रहे हैं, जबकि वीआईपी कॉलोनियों से नगर निगम को कुछ नहीं मिलता। राजधानी में आम आदमी से तो भरपूर टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन सुविधाएं वीआईपी क्षेत्रों को दी जा रही हैं। इस कारण जहां चार इमली, 74 बंगला, 45 बंगला, अरेरा कॉलोनी क्षेत्र में विकास नजर आ रहा है, वहीं आम आदमी वाली कॉलोनियों की पहचान टूटी सड़क, खुदी सड़क, उड़ती धूल, सड़कों पर अंधेरा बन गया है। जब राजधानी भोपाल में यह हाल है तो अन्य क्षेत्रों का क्या होगा?

शहर की सड़कों की रिपेयरिंग में भी वीआईपी और आम ट्रीटमेंट नजर आ रहा है। जहां से मंत्री, विधायक या अफसर गुजरते हैं, वहां तो सड़क पर डामर की परत बिछाई जा रही है, लेकिन जिन सड़कों से आमजन गुजरते हैं, उनके गड्ढ़े भी सही ढंग से नहीं भरे जा सके हैं। वीआईपी ट्रीटमेंट वाली सड़कों में मंत्रालय और चार इमली का हिस्सा प्रमुख है। दूसरी ओर शाहपुरा, कोलार, अयोध्या बायपास, बावड़ियाकलां, होशंगाबाद रोड, कोहेफिजा, दानिश नगर, इंद्रपुरी, आनंद नगर, करोंद, भोपाल टॉकीज के सामने आदि इलाकों में सड़कें अब तक चकाचक नहीं हो पाई हैं।

जिन सड़कों से मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों की लाखों की कार गुजरती थी, वहां सड़कों के गड्ढ़ों वाले मुहासे डामर के फेशियल से ढंके जाने लगे और जिन सड़कों से आम आदमी की किश्तों पर खरीदी गई गाड़ियां गुजरती हैं, उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। यानी सड़क बनेगी तो पहले वीआईपी, जैसे आम आदमी को तो धक्का खाना किस्मत में लिखा हो। भोपाल से रायसेन जाने वाली सड़क पर आम आदमी को स्लिप डिस्क हो जाए, गाड़ी गड्ढ़े में गिर जाए, हाथ टूट जाए, मुंह फूल जाए। गाड़ी का पुर्जा-पुर्जा हिले चाहे आम आदमी की हड्डी का, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी यहां नजरें इनायत करने अफसर नहीं आते। यदि आपको अपनी कॉलोनी या शहर में अच्छी सड़कें चाहिए तो आपको वीआईपी होना बेहद जरूरी है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि प्रदेश में ऐसा ही हो रहा है। इस कड़वी हकीकत को साबित करने वाली एक चर्चित खबर 11 अक्टूबर को सुर्खियां बनी थी, जिसके अनुसार गुना जिले प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को गड्ढ़ों से भरी सड़कों पर झटके लगे तो उनके एक फोन पर गुना में एबी रोड पर आनन-फानन में पेचवर्क शुरू कर दिया गया। इतना ही नहीं पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अफसरों ने नाराज मंत्रीजी को भरोसा दिलाया कि गुना बायपास के खराब हिस्से को अगले ही दिन दुरुस्त करवा दिया जाएगा। आपको बता दें कि सिस्टम के वीआईपी सिंड्रोम से पीड़ित होने का यह कोई दुर्लभ उदाहरण नहीं है बल्कि यह हर जगह हो रहा है। राजधानी भोपाल भी इससे अछूती नहीं है। यहां भी आम और खास के बीच भेदभाव किया जा रहा है। सरकार को हर सेवा और सुविधा के लिए अपनी जेब से टैक्स अदा करने वाली आम जनता की सड़कों के गड्ढ़े वेस्ट मटेरियल यानी कचरे से भरे जा रहे हैं। जबकि जनता के टैक्स के पैसों से बड़ी सैलरी और मुफ्त सुविधाएं लेने वाले बड़े नेता-अफसरों की सड़कों की सरफेस उखड़ने पर भी उन्हें करोड़ों रुपए खर्च कर नए सिरे से बनाकर चमकाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में 6 अक्टूबर से शुरू हुए सड़क के गड्ढ़ों को भरने के काम में खुलेआम ऐसा ही भेदभाव किया जा रहा है।

हवाई जहाज से जब दूसरे प्रदेश या विदेश का व्यक्ति भोपाल आता है तो ऊपर से यहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मोहित हो जाता है। वाकई भोपाल का प्राकृतिक सौंदर्य मनमोहक है भी। लेकिन जब वही व्यक्ति शहर के रहवासी क्षेत्रों में जाता है तो उसे भोपाल रेशम के कपड़े में लगे पेबंद जैसा नजर आता है। यह भोपालवासियों के लिए ही नहीं बल्कि सरकार

मप्र में बढ़ते वायु प्रदूषण से मुख्य सचिव नाराज

मप्र में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को मुख्य सचिव अनुराग जैन ने गंभीरता से लिया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में उन्होंने नाराजगी जताते हुए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, देवास और सागर कलेक्टर को प्रदूषण घटाने के लिए माइक्रो लेवल एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए। सीएस ने कहा कि हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए रोड डस्ट कंट्रोल करने के कामों की खुद निगरानी करें। बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मप्र के 7 शहरों समेत देशभर में 102 शहरों को नॉन अटेनमेंट सिटी (अति प्रदूषित रहवास क्षेत्र) घोषित किया है। एनकैप के तहत इन शहरों को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय अलग से फंडिंग करता है। नगरीय निकाय एवं आवास आयुक्त भरत यादव ने मप्र में अब तक एनकैप के तहत किए गए कामों की जानकारी मुख्य सचिव को दी। वहीं इस दिशा में सीएस अनुराग जैन ने 7 जिलों के कलेक्टरों को काम करने के निर्देश दिए है।

के लिए भी शर्म की बात है। जिस शहर के विकास के लिए अकेले नगर निगम करीब 2600 करोड़ रुपए का बजट स्वाहा करता है, उस शहर में गड्ढ़े, गंदगी और धूल का गुबार यह दर्शाता है कि यहां का विकास केवल कागजों में हो रहा है। हां, वही व्यक्ति जब चार इमली, 74 बंगला, 45 बंगला, अरेरा कॉलोनी क्षेत्र में जाता है तो उसे अहसास होता है कि वाकई वह स्मार्ट सिटी में आ गया है। शहर के विकास में यह भेदभाव वाकई चिंता का विषय है।

सीवरेज की फजीहत

नगर निगम का दावा है कि शहर के सभी बड़े नालों का चैनेलाइजेशन हो चुका है, लेकिन वास्तविकता यह है कि शहर के 789 छोटे-बड़े नालों का चैनेलाइजेशन पिछले 14 सालों में 130 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं हो पाया है। नगर निगम सालाना 20 करोड़ रुपए स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क डेवलपमेंट और मेंटेनेंस पर खर्च करता है। साथ ही बारिश पूर्व नालों की सफाई में 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्च होते हैं। इसके बावजूद शहर में कई जगहों पर अब भी जलभराव की स्थिति बनती है। इधर, अगर बीते पांच साल की बात करें, तो नगर निगम स्टॉर्म वॉटर नेटवर्क पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च कर चुका है। तीन साल पहले अमृत योजना के तहत 125 करोड़ रुपए की लागत से नाला चैनेलाइजेशन अधूरा काम दोबारा शुरू कराया गया, लेकिन ये भी अब तक पूरा नहीं हो सका है। बता दें कि शहर में छोटे-बड़े 789 नालों सहित मुख्य पांच नालों के चैनेलाइजेशन प्रोजेक्ट को भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने 26 मई 2006 को मंजूरी दी थी। योजना के तहत संजय नगर, शाहपुरा, स्लाटर हाउस, पातरा व साउथ टीटी नगर के सात हजार 250 मीटर लंबे नालों का चैनेलाइजेशन 30 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से कराया जाना था। बड़े नालों का चैनेलाइजेशन करने के बाद इनमें छोटे नालों को कनेक्ट किया जाना था। चैनेलाइजेशन के तहत नालों की कांक्रीट लाइनिंग के जरिए डिजाइन इंबेकमेंट निर्माण शुरू हुआ, लेकिन 14 साल बाद भी काम पूरा नहीं हो सका है। अमृत योजना के तहत कुल 225 करोड़

रुपए की लागत से नालों का निर्माण कर उनका चैनेलाइजेशन किया जाना है। निगम ने पहले चरण में विभिन्न कॉलोनियों के 15 से अधिक नाले-नालियों को अमृत योजना में शामिल किया है। ये वह नाले हैं जिनकी वजह से जलभराव की समस्या होती है।

60 प्रतिशत सड़कें अब भी बदहाल

राजधानी की खूबसूरती पर दाग लगा रही सड़कों की तस्वीरें अभी भी नहीं बदल पाई है। अभी भी 60 प्रतिशत सड़कें खराब हालत में हैं, जबकि 6 से 20 अक्टूबर के बीच में सड़कें 100 प्रतिशत सुधर जानी चाहिए थीं। भोपाल में नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, बीडीए और सीपीए (राजधानी परियोजना प्रशासन) की करीब 4700 किलोमीटर सड़कें हैं। इनमें से लगभग 50 प्रतिशत सड़कें बारिश के कारण जर्जर हो गई हैं। इन्हीं सड़कों को लेकर जहां सियासत गरमा गई है तो वहीं लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। कोलार की कई सड़कों पर पैदल चलना तक मुश्किल है तो पुराने शहर के भोपाल टॉकीज, हमीदिया रोड और करोंद में भी सड़कें गड्ढ़ों में गायब हो गई हैं। सीवरेज और कोलार ग्रेविटी लाइन की खुदाई होने से कोलार गेस्ट हाउस से बैरागढ़ चिचली तक सड़क पूरी तरह से उखड़ी हुई है। कुछ जगह ही पक्का पेचवर्क हुआ है, जबकि बाकी में गिट्टी और मिट्टी डालकर लीपापोती कर दी गई है। बीमाकुंज से बैरागढ़ चिचली तक का हिस्सा सबसे ज्यादा जर्जर है। रायसेन रोड के इंद्रपुरी, आनंद नगर में सड़क पर ढेरों गड्ढ़े हैं। होशंगाबाद रोड पर मिसरोद तक सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढ़े हो चुके हैं। वहीं पुराने शहर में हमीदिया रोड, भोपाल टॉकीज, घोड़ा नक्कास, लोहा बाजार, नवबहार सब्जी मंडी, करोंद में हालत ठीक नहीं है। उधर, कमला पार्क के पास सड़क गड्ढ़ों में गायब हो गई है। शाहपुरा चौराहे से बंसल हॉस्पिटल तक सड़क जर्जर है। बावड़ियाकलां के मुख्य मार्ग पर कीचड़ और गड्ढ़ों के कारण लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया है।

बता दें कि राजधानी की सड़कों के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव समेत कई नेताओं ने सरकार को घेरा था। इसके बाद ताबड़तोड़ नगर निगम, पीडब्ल्यूडी ने अपनी सड़कों की सुध ली। हालांकि, पेचवर्क के नाम पर ईंट के टुकड़े और गिट्टी-मुरम गड्ढ़ों में भरी गई है, जो गाड़ियों के पहियों के साथ सड़कों पर फैलकर राहगीरों के लिए और बड़ी मुसीबत बन गए हैं। नगर निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी का कहना है कि निगम की सड़कों का पेचवर्क कराया जा रहा है। कोलार में सीवेज और पाइप लाइन के काम के बाद सड़क की बेहतर तरीके से मरम्मत करने के निर्देश ठेकेदार को दिए गए हैं। लेकिन आज तक सड़कों की स्थिति जस की तस है। कहीं-कहीं मिट्टी और मुरम से गड्ढ़े भरने की कोशिश भी की गई है, लेकिन अब वही मिट्टी और मुरम परेशानी का सबब बन गई है।

300 से अधिक कॉलोनियां गड्ढ़ायुक्त

मानसून की विदाई के बाद भी शहर की उखड़ी, टूटी, खुदी व खराब सड़कें वैसी की वैसी हैं। इस साल मानसून की बारिश से 300 से अधिक कॉलोनियों के लोग दिक्कत में आ गए हैं। इनमें 60 फीसदी कॉलोनियां कोलार में हैं। बाकी नेहरू नगर, भदभदा क्षेत्र, करोंद, बैरागढ़, पुराने शहर, गोविंदपुरा व कटारा हिल्स से जुड़ी हुई कॉलोनियां हैं। यहां बीते एक साल के दौरान सड़क खुदाई से लेकर नाली निर्माण के काम हुए हैं। यहां काम करने के बाद सड़क दुरूस्त नहीं की गई, जिससे अब रिमझिम बारिश में यहां सड़क से बाहर पड़ी धूल-मिट्टी कीचड़ में बदल गई। कुछ सड़कों पर तो बड़े गड्ढ़े हो गए। कुछ सड़कों पर कीचड़ फिसलन की बड़ी वजह बन गया। लोगों को बेहद संभलकर जाना पड़ रहा है। यहां थोड़ी सी लापरवाही दुर्घटना का कारण बन रही है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां दो साल से सड़कें खोदी हुई हैं। निर्देश के बावजूद ठेका एजेंसी दुरूस्त नहीं कर रही। बारिश के बाद हर बार यहां कीचड़ और इससे लोगों को परेशानी की स्थिति बनती है। कोलार की राजहर्ष कॉलोनी, प्रियंका नगर, ललिता नगर, नम्रता नगर, सनखेड़ी रोड, वंदना नगर से लेकर मिसरोद, बावड़िया, गुलमोहर से जुड़ी कॉलोनियां हैं। शाहपुरा में तो निगमायुक्त बीते दो माह में तीन बार निरीक्षण कर खुदी सड़कों को दुरूस्त करने का कह चुके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है।

अबूझमाड़ में आखिरी लड़ाई!

नक्सलियों की शरणस्थली में ख्यात अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में लगातार सफलता मिल रही है। अभी हाल ही में डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) और सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) ने कोंटा और किस्टाराम क्षेत्र की नक्सल एरिया कमेटी के साथ मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ के बाद मौके से 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए, साथ ही भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी जब्त किए गए। मुठभेड़ स्थल से स्वचालित हथियारों की बरामदगी इस ऑपरेशन की सफलता को और मजबूत करती है। बरामद हथियारों में एके-47, इंसास और एसएलआर राइफल शामिल हैं। यह इशारा करता है कि मारे गए नक्सलियों में कुछ बड़े नेता भी हो सकते हैं। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन को जारी रखते हुए क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों को पूरी तरह खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

अबूझमाड़ क्षेत्र माओवादियों का अब तक एकमात्र सफल आधार इलाका रहा है। नक्सल गतिविधियों के संचालन के दृष्टिगत इस क्षेत्र में पहली सुविधा है सघन वन। बता दें कि इंद्रावती, नल्लामल्ला, कान्हा, नागझीरा, ताडोबा और उदन्ती राष्ट्रीय उद्यान इस परिक्षेत्र के सीधे संपर्क में आते हैं। इतना ही नहीं, यह परिक्षेत्र तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों को आपस में जोड़ता है। अर्थात् वाम-अतिवादियों को एक राज्य में वारदात कर दूसरे में भाग जाने की सुविधा प्रदान करता है। प्रश्न उठता है कि माओवादियों ने अबूझमाड़ को ही अपना आधार इलाका कैसे और क्यों बना लिया? इसका उत्तर बड़ी प्रशासनिक गलतियों में छिपा है। वह साठ का दशक था, जब बस्तर एक वृहद् जिला हुआ करता था, (वर्तमान में बस्तर एक संभाग है जिसके अंतर्गत सात जिले आते हैं)। ब्रह्मदेव शर्मा उन दिनों वहां के जिलाधीश हुआ करते थे, जिन्हें वाम हलकों में जनजाति विशेषज्ञ होने का सम्मान प्राप्त है। 2012 में जब सुकमा जिले के जिलाधीश रहे एलेक्स पॉल मेनन को नक्सलियों ने अगवा कर लिया, तब सरकार ने मध्यस्थता के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकालना चाहा।

आश्चर्य यह कि माओवादियों की ओर से तब बिचौलिया बने थे यही पूर्व नौकरशाह ब्रह्मदेव शर्मा। जब शर्मा जिलाधीश थे, तब अबूझमाड़ की ओर जाने वाली सड़कों की परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अबूझमाड़ को जिंदा मानव संग्रहालय में बदल दिया गया, अर्थात् यदि कोई बाहरी व्यक्ति (वह बस्तर संभाग का निवासी ही क्यों न हो) भीतरी जंगलों में जाना चाहता हो तो उसे जिलाधीश से एक पास बनवाना पड़ता था। यह पास एक घंटे के लिए प्राप्त होता था। ऐसे में नारायणपुर से निकलकर ओरछा पहुंचे नहीं कि समय समाप्त। इस निर्णय से यह हुआ कि मुख्यधारा का जंगल के भीतर से सदियों से स्थापित रहा नैसर्गिक संबंध टूट गया।

अबूझमाड़ को मानव संग्रहालय में बदल देने की इस परिघटना के क्या घातक परिणाम हुए, इसे जानने के लिए नक्सलवाद की एक शाखा पीपुल्स वार ग्रुप के बारे में जानना आवश्यक है। 1975 में हनामकोंडा (वारंगल) के एक विद्यालय में हिंदी अध्यापक रहे कोण्डाल्ली सीतारमैया ने चीन की सांस्कृतिक क्रांति से प्रभावित होकर पीपुल्स वार ग्रुप का गठन किया। सीतारमैया आंध्र प्रदेश में लंबे समय से मुलुगु के जंगल में पैर जमाने की कोशिश कर रहा था।

वह इसी क्षेत्र को आधार इलाका बनाना चाहता था लेकिन सफल नहीं हो पाया। उसे नदी के दूसरी ओर बस्तर के जंगलों में अपने लड़ाकों के लिए सुरक्षित जगह बनाने का ख्याल कौंधा। अस्सी के दौरान उसने अपनी योजना के अनुसार पांच से सात सदस्यों के सात अलग-अलग दल भेजे थे। चार दल तो दक्षिणी तेलंगाना के आदिलाबाद, खम्माम, करीमनगर और वारंगल जिलों की ओर गए, एक दल महाराष्ट्र के गढ़चिरोली को तथा दो अन्य दल को बस्तर की ओर भेजा गया। पीपुल्स वार ग्रुप का बस्तर प्रवेश किसी भी तौर पर इस अंचल की समस्याओं अथवा असंतोष के मद्देनजर नहीं था। यह कदम विशुद्ध रूप से आश्रय तलाश करने और सेना तैयार करने के दृष्टिगत आधार इलाका बनाना था।

साठ के दशक में अबूझमाड़ को मानव संग्रहालय बना देने के निर्णय ने इस क्षेत्र से स्कूल, अस्पताल, डाकघर और अन्यान्य सरकारी भवनों को विलुप्त कर दिया था। माओवादी जब अबूझमाड़ में घुसे तो उनके लिए कोई संघर्ष मौजूद था ही नहीं, जैसे किसी ने थाली में परोसकर आधा इलाका थमा दिया था। यह 2004 से 2006 के बीच की बात है जब देशभर के अलग-अलग स्थानों में सक्रिय एमसीसी, पीडब्ल्यूजी जैसे कई माओवादी धड़े भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नाम से संगठित हुए।

● रायपुर से टीपी सिंह

माओवाद की आखिरी शरणस्थली

अबूझमाड़ माओवाद की आखिरी शरणस्थली है। यदि इस परिक्षेत्र से माओवाद की जड़ें उखाड़कर फेंक दी जाती हैं तो भारत भर में कोई दूसरी ऐसी जगह नहीं है जहां इस प्रकार की भौगोलिक-सामाजिक परिस्थितियां विद्यमान हों। अब अबूझमाड़ में ही लड़ाई होनी है और भीषण संघर्ष होगा। बता दें कि जैसे-जैसे सुरक्षा बल इस क्षेत्र में भीतर प्रवेश करते जाएंगे, शहरी माओवादी सक्रिय होंगे और अपना पूरा अफवाह तंत्र लगाकर अभियान को बदनाम करने में एड़ी-चोटी कर देंगे। बंदूक वाले नक्सली ही कलम वाले नक्सलियों के प्राण हैं इसलिए यह लड़ाई बड़ी और बहुकोणीय होने वाली है। बस्तर संभाग में इसी वर्ष सरकार के बदलने के बाद से नक्सल उन्मूलन अभियान में तेजी देखी गई है। गत् 16 अप्रैल को कांकेर जिला मुख्यालय से करीब 160 किलोमीटर दूर आपाटोला-कलपर जंगल के क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 29 माओवादी मारे गए थे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मार्च, 2026 की तिथि माओवाद से मुक्ति के लिए तय कर दी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत् कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2010 में देश में जहां 107 जिले माओवाद से प्रभावित थे, वर्तमान में उनकी संख्या आधे से भी कम होकर केवल 42 रह गई है। कहने का अर्थ यह है कि योजनाबद्धता और इच्छाशक्ति के साथ प्रयास किया जाए तो निश्चित ही माओवाद मिट जाएगा।

राहुल गांधी की कास्ट पॉलिटिक्स

राहुल गांधी ने जातीय राजनीति की राह तो ठीक पकड़ी है, लेकिन जननायक की मंजिल अभी दूर है। ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के मामले में यूरेका मोमेंट पा लिया हो और कांग्रेस के वोटर से सीधे संवाद करने लगे हों। भाजपा के तीखे हमलों से बिलकुल बेअसर और बेपरवाह राहुल गांधी धुन के पक्के तेज कदमों से अपने रास्ते पर बढ़ते चले जा रहे हैं।

देश की राजनीति में धर्म चलेगा या जाति का दबदबा? समय-समय पर ये सवाल भी उठता रहा है, और घुमा-फिराकर जवाब भी मिलता रहा है। राजनीति में वैसे भी कम ही ऐसे मौके होते हैं जब किसी सवाल का सीधा जवाब मिलता है। मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई में भी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हो चुकी है। बारी-बारी दोनों के पक्ष में जवाब मिल चुके हैं और एक जवाब तो यही है कि न मंडल, न कमंडल ये वक्त ही तय करता है कि हाथी नाव पर होगा, या नाव हाथी को नदी पार कराएगी। बीते एक दशक से भारतीय राजनीति में धर्म का ही बोलबाला महसूस किया गया है, लेकिन अब वही राजनीति जाति की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है।

भाजपा के लिए ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बात है। तभी तो संघ ने अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ाव बनाए रखने के लिए धार्मिक सम्मेलन का प्लान बनाया है। और ये बीड़ा थमाया गया है सबसे विश्वसनीय संगठन विश्व हिंदू परिषद को। वही विश्व हिंदू परिषद जिसने हिंदुत्व की राजनीति को ऐसी धार दी कि भाजपा सहयोगी दलों के साथ केंद्र सत्ता से बाहर होने के बाद फिर से काबिज हो गई, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनते ही, हालत ये हो गई जिसकी उस खेमे में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, लोकसभा चुनाव में भाजपा अयोध्या ही हार गई।

भाजपा को अयोध्या हराने वाले इंडिया ब्लॉक की असली ताकत राहुल गांधी को तभी महसूस हुई जब 4 जून, 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और फिर वो सारी भूल-चूक, लेनी-देनी को दरकिनार कर मिशन को पूरा करने निकल पड़े। ये तो ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी भारतीय राजनीति में अपना ब्रह्मास्त्र मिल गया हो और ऐसे दौर में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भाजपा में भी ये बात महसूस की जा रही है?

बीते एक दशक में भाजपा ने राहुल गांधी का जीना हराम कर रखा है, ये तो पूरा गांधी परिवार मानता है। 2014 में कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसल जाने के बाद राहुल गांधी को वे सारे दिन, और रातें भी देखनी पड़ीं जिनके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मां सोनिया गांधी के साथ कोर्ट में जाकर जमानत कराने से लेकर, प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर जाकर अफसरों के सामने पूछताछ के लिए पेश होने तक। कुछ देर के लिए तो गिरफ्तारी तक का खतरा भी मंडराने लगा था। राहुल गांधी लगे रहे। अपने हिसाब से अपनी लड़ाई लड़ते रहे। एक-एक करके सारे ही हथियार नाकाम होते जा रहे थे, लेकिन बंदा चलता रहा। लंबी भारत जोड़ो यात्रा के बाद, एक और न्याय यात्रा भी पूरी की। तब भी जबकि ज्यादातर गठबंधन साथी नाराज हो गए। नीतीश कुमार ने तो साथ ही छोड़ दिया।

ब्यूटी कॉन्टेस्ट में राहुल गांधी के जातीय ऐंगल खोजने को लेकर भाजपा नेता मजाक उड़ा रहे हैं। पप्पू वाली बातें बालक बुद्धि पर आ चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी को अब ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिलकुल वैसे ही जैसे संसद में अनुराग ठाकुर की बातों से बेअसर रहे थे। अनुराग ठाकुर का कहना था, जिनकी जाति का कुछ पता ही नहीं है वो भी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। मिस इंडिया में जाति का सवाल पूछने वाले राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कहते हैं, राहुल मिस इंडिया में भी आरक्षण चाहते हैं... बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन राहुल अपनी विभाजनकारी बातों से पिछड़े समुदायों का मजाक न उड़ायें... मिस इंडिया, ओलिंपिक के लिए एथलीट या एक्टर सरकार नहीं चुनती है। बिलकुल सही बात

वोटरों को पहुंचा रहे संदेश

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई बार क्षेत्रीय दलों की विचारधारा को लेकर बयान दिए थे, जिस पर काफी कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। हालांकि, पहली बार राहुल गांधी ने ये बात उदयपुर के चिंतन शिविर के दौरान कही थी। राहुल गांधी का मानना है कि विचारधारा की लड़ाई देश में सिर्फ कांग्रेस और भाजपा जैसे राजनीतिक दल ही करते हैं, बाकी क्षेत्रीय दलों के पास विचारधारा जैसी कोई चीज नहीं होती। देखा जाए तो राहुल गांधी अब उस मिशन पर निकल चुके हैं जिसके निशाने पर पहले भाजपा और फिर बारी-बारी वे सभी राजनीतिक दल आने वाले हैं जिनकी राजनीति सिर्फ अपनी बिरादरी के बूते फलती-फूलती आई है। राहुल गांधी का मिस इंडिया के मामले में भी जातीय ऐंगल ढूंढ लेना यूं ही नहीं है। राहुल गांधी अपने वोटर तक अपना संदेश अच्छी तरह पहुंचा रहे हैं और राहुल गांधी का वोटर धीरे-धीरे मानने लगा है कि कोई तो है जो उनकी बात उठा रहा है। बिहार की राजनीति में लालू यादव को सोशल जस्टिस का पुरोधा माना जाता है। जैसे बिहार में आरजेडी का वोटर कहता है कि सड़कें भले न बनवाई हो, विकास भले न किया हो लेकिन लालू यादव ने समाज में वंचित तबके को जो इज्जत दिलाई है, वो सबसे बड़ी बात है और राहुल गांधी भी राजनीति की उसी राह पर फिर से चल पड़े हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर उनका वोटर मानकर चल रहा है कि देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा खत्म होकर रहेगा। ये बात कांग्रेस पर भी लागू होती है।

विवादित बयानों से चर्चा में राहुल गांधी

राहुल गांधी ने अपनी एक विदेश यात्रा के दौरान कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। हाल ही में एक सर्वेक्षण में राहुल गांधी को मोदी के बाद लोगों की पहली पसंद बताया गया है। ऐसे में उन्हें अपनी छवि सुधारने की जरूरत है और इसके लिए उन्हें अपने बयानों पर ध्यान देना होगा। राहुल गांधी को चाहिए कि वह अपनी ऊर्जा बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता करने में लगाएं। देश के बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए काम करें। राहुल गांधी ने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में कहा, मुझे नहीं लगता कि एक निष्पक्ष चुनाव में भाजपा 240 सीटों के आसपास भी कहीं होती। मैं इसे बिल्कुल भी निष्पक्ष चुनाव नहीं मानता। यह एक नियंत्रित चुनाव था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई और मोदी जो चाहते थे, वही किया। राजनीतिक विश्लेषकों ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा के बाद की टिप्पणियों की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने भारत में जातिगत जनगणना का आह्वान किया था। उनका तर्क है कि आरक्षण का विस्तार करने के बजाय, भारत को एक विकसित देश बनने के लिए वास्तविक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वह प्रधानमंत्री मोदी की भी आलोचना करते हैं, उनका कहना है कि वे भारत की खराब स्कूली शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर पाए। वह राहुल गांधी की इस धारणा की आलोचना करते हैं कि जाति ही भारत में असमानता का एकमात्र कारण है। वे कहते हैं कि राहुल गांधी को यह याद रखना चाहिए कि जाति ही एकमात्र कारण नहीं है कि 90 प्रतिशत भारतीय भारत की समृद्धि की यात्रा में भागीदार नहीं हैं। उनका तर्क है कि गरीबी और वंचितता से उठने के लिए निचली जातियों के पास आवश्यक संसाधन नहीं हैं, और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है।

है। किरेन रिजिजू का भले ही ये राजनीतिक बयान हो, लेकिन वो सीधे सपाट शब्दों में ही अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन क्या वो राहुल गांधी की गंभीरता को समझ पा रहे हैं। राहुल गांधी जातीय राजनीति के असर को जो दूर तक देख चुके हैं, क्या किरेन रिजिजू और अनुराग ठाकुर से इतर भी भाजपा नेता उस बात को समझ पा रहे हैं?

प्रयागराज में संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में हिस्सा लेते वक्त राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, मैंने मिस इंडिया की लिस्ट चेक की... इसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं थी... प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश सुपर पावर बन गया... कैसे सुपर पावर बन जाएगा, जब 90 फीसदी लोग सिस्टम से बाहर बैठे हैं। ये बात राहुल गांधी ने कोई पहली बार नहीं कही है। संसद का विशेष सत्र बुलाकर जब महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया था तब भी राहुल गांधी ने ऐसी बातें की थीं। राहुल गांधी ने तब केंद्र सरकार में तैनात ओबीसी सचिवों की संख्या का मुद्दा उठाया था और वैसे ही बजट सत्र में हलवा बनाए जाने को लेकर भी सवाल खड़ा किया था।

राहुल गांधी की मंशा तो भाजपा के रणनीतिकारों और सलाहकारों को तभी समझ लेनी चाहिए थी, जब राहुल गांधी महिला आरक्षण के मामले में अपने ही पुराने स्टैंड से यू-टर्न ले लिया था। जिस मुद्दे पर मुलायम सिंह यादव और लालू यादव की पार्टियों के विरोध के चलते कांग्रेस चाह कर भी महिला बिल नहीं पास करा सकी, उसी मुद्दे पर खुद राजी ही नहीं हुई, बल्कि ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग नए सिरे से शुरू हो गई। अगर अब भी किरेन रिजिजू और अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं को राहुल गांधी कास्ट पॉलिटिक्स के दूरगामी नतीजे नहीं समझ में आ रहे हैं, तो ये भाजपा के लिए चिंता की बात होनी चाहिए।

भाजपा को ये बिलकुल नहीं भूलना चाहिए कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर उसके एनडीए साथी चिराग पासवान भी राहुल गांधी के साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं। भाजपा को 2018 का वो वाकया भी याद कर लेना चाहिए जब एससी-एसटी के मुद्दे पर चिराग के पिता रामविलास पासवान भी ऐसे ही डटकर खड़े हो गए थे। ये तब की बात है जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। 21 मार्च, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट, 1989 के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी सिर्फ सक्षम प्राधिकारी की इजाजत के बाद ही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तब दलित समुदाय की तरफ से भारत बंद भी बुलाया गया था, और बंद के दौरान हुई हिंसा में दर्जनभर लोगों की मौत भी हो गई थी।

राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के बीच ही कांग्रेस नेताओं से ये मुद्दा उठाने को कहा। कांग्रेस तत्काल प्रभाव से दलितों के पक्ष में खड़ी हो गई। रामविलास पासवान सहित एनडीए के दलित सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास चले गए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार ने बदल डाला। ऐसा ही उदाहरण एक बार फिर हाल ही में देखने को मिला जब एससी-एसटी आरक्षण में सब-कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है। भाजपा कैसे भूल जाती है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण को लेकर एक बयान से 2015 के बिहार में हार का मुंह देखना पड़ा था। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी तो भाजपा के खिलाफ संविधान बदलकर आरक्षण खत्म करने की आशंका वाला नैरेटिव चला ही दिया और भाजपा को उप्र में 33 सीटों पर सिमट जाना पड़ा। ध्यान दें, तो राहुल गांधी की जातीय राजनीति के निशाने सिर्फ भाजपा नहीं है, बल्कि वे सारे ही राजनीतिक दल हैं जिनकी कास्ट वोटबैंक से ही डायनेस्टी पॉलिटिक्स चलती है। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के साथ-साथ चिराग पासवान के भी सुर में सुर मिलाने की सबसे बड़ी वजह भी यही है। जब कांग्रेस में संगठन का चुनाव चल रहा था तो शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खरगे को चैलेंज किया था। वो चुनाव तो हार गए, लेकिन शशि थरूर ने तब एक बहुत बड़ी बात कही थी। शशि थरूर का कहना था कि कांग्रेस को अपने कोर वोटबैंक के पास जाना चाहिए और रूठे हुए को मनाकर वापस लाना चाहिए। हो सकता है तब शशि थरूर की बातों को अन्य कांग्रेस नेताओं ने हवा में उड़ा दिया हो, लेकिन राहुल गांधी के मिशन में तो लगता है कि शशि थरूर के सुझाव को गंभीरता से लिया गया है।

● **विपिन कंधारी**

टिकट वितरण में पार्टी कार्यकर्ता की कर्मठता एवं समर्पण सरीखे पहलू अक्सर गौण हो जाते हैं। उसमें केवल जिताऊ कोण पर ही पूरा जोर दिया जाता है। ऐसे में निष्ठावान कार्यकर्ताओं को किनारे करके धनबल, बाहुबल और जातीय-धार्मिक पहलुओं को प्राथमिकता दी जाने लगी है। खासतौर से चुनाव जितने खर्चीले होते जा रहे हैं उसे देखते हुए धनबल की महत्ता बढ़ती जा रही है।

आंतरिक लोकतंत्र का अभाव

समकालीन भारतीय राजनीति में दलबदल एक ऐसी दलदल है जिसमें लगभग हर कोई राजनीतिक दल धंसा हुआ है। ज्यादा दूर न जाएं तो चाहे अप्रैल से जून तक चले लोकसभा के चुनाव हों या बीते दिनों हुए हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव से लेकर महाराष्ट्र-झारखंड का उदाहरण लें तो कुछ नेताओं को लेकर आपको दुविधा हो सकती है कि वे इन दिनों किस पार्टी के साथ जुड़े हैं। सभी दल असंतुष्ट और बागी प्रत्याशियों से जूझ रहे हैं। असल में नेताओं और दलों ने दलबदल को इतना सामान्य बना दिया है कि मानो यह कोई मुद्दा ही नहीं है। हालांकि ऐसा है नहीं। चाहे नैतिकता का तकाजा हो या फिर आदर्श राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो दलबदल की यह परिपाटी राजनीतिक तंत्र में भरोसे और विश्वसनीयता का सवाल निश्चित रूप से उठाती है। इस बहस में पहला प्रश्न तो यही कौंधता है कि आखिर हमारी व्यवस्था में यह सिलसिला क्यों कायम है? इसके उत्तर की पड़ताल करें तो उसमें राजनीतिक एवं चुनाव सुधारों का अभाव दिखेगा। हमारे कुछ नेताओं की निहित स्वार्थ से प्रेरित वह मानसिकता भी इसके मूल में है जो किसी भी स्थिति में सत्ता में भागीदार न सही तो कम से कम उसके करीब जरूर रहना चाहती है।

दलबदल अमूमन दो तरह से होता है। एक तो चुनाव से पहले और दूसरा चुनाव के बाद। स्वाभाविक है कि चुनाव में टिकट से वंचित रह जाने की स्थिति में लोग पाला बदल लेते हैं। हालांकि इसके उतने खतरे नहीं, क्योंकि चुनाव से पहले ही मतदाताओं के समक्ष स्थिति स्पष्ट रहती है कि कौन किसके पाले में है। दोनों स्थितियों में चुनाव बाद होने वाला दलबदल कहीं अधिक गंभीर प्रकृति का है, क्योंकि उसमें मतदाताओं के साथ छल होने का जोखिम अधिक रहता है। शायद यही कारण रहा कि चुनाव बाद होने वाले दलबदल पर अंकुश के लिए वर्ष 1985 में राजीव गांधी सरकार ने दलबदल निरोधक कानून बनाया, जिसे 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने और सशक्त बनाने का काम किया। इससे चुनाव बाद दलबदल की समस्या का कुछ हद तक समाधान अवश्य हुआ, लेकिन उसका पूरी तरह निराकरण नहीं हो पाया। नेताओं ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। चूंकि दलबदल के लिए एक निश्चित संख्या की आवश्यकता होती है तो उसका बंदोबस्त करने के बाद अब यह कहीं अधिक संस्थागत रूप से होने लगा है। यहां तक कि निर्वाचन के बाद जनप्रतिनिधियों द्वारा सदन की अपनी सदस्यता से इस्तीफा देकर बहुमत के आंकड़े को ही विरूपित कर दिया जाता है। उसके बाद उपचुनाव से चुनावी प्रक्रिया और भी बोझिल होने लगी है। वहीं एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले गठबंधन के दल भी जब सत्ता की खातिर अपनी राह अलग कर लेते हैं तो वह भी जनमत और जनादेश के साथ एक प्रकार का छल होता है।

दलबदल की समस्या समय के साथ और विकराल हुई है तो उसके सबसे अधिक दोषी हमारे राजनीतिक दल हैं। छोटी पार्टियां तो निजी जागीरों की तरह चलाई ही जा रही हैं, मगर बड़े दलों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं। बड़ी पार्टियों का नेतृत्व भी हद से अधिक केंद्रीयकृत हो चला है। आंतरिक लोकतंत्र भी आदर्श अवस्था में नहीं है। प्रत्याशी चयन की सुनिश्चित प्रक्रिया नहीं है। टिकट वितरण में पार्टी कार्यकर्ता की कर्मठता एवं समर्पण सरीखे पहलू अक्सर गौण हो जाते हैं। उसमें केवल जिताऊ कोण पर ही पूरा जोर दिया जाता है। ऐसे में निष्ठावान कार्यकर्ताओं को किनारे करके धनबल, बाहुबल और जातीय-धार्मिक पहलुओं को प्राथमिकता दी

सत्ता के लिए सबकुछ दांव पर

महाराष्ट्र में सत्ता के लिए परिवार भी टूटे हैं। चुनाव के समय अजित पवार ने कहा था कि 2019 के नाटक के रचयिता तो शरद पवार ही थे। मान चाचा ने भी लिया है कि हां, वह भाजपा के साथ सरकार बनाने की विचार प्रक्रिया में शामिल थे, पर उस पर भरोसा नहीं कर पाए। महाराष्ट्र के चुनावी परिदृश्य में भाजपा और कांग्रेस ही दो बड़े दल हैं। भाजपा की महायुति और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी, दोनों में ही गिनती के लिए तीन-तीन दल हैं, लेकिन दरअसल शेष दो दल विभाजित गुट हैं, जिनकी राजनीतिक स्वीकार्यता की परीक्षा ये चुनाव थे। शिंदे के नेतृत्ववाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्ववाली राकांपा, महायुति में है तो उद्धव के नेतृत्ववाली शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्ववाली राकांपा, महाविकास आघाड़ी में है। विचित्र स्थिति है कि दोनों बड़े दल इन गुटों पर ज्यादा निर्भर नजर आ रहे हैं, जबकि उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध बनी हुई है। शरद पवार अपने विधायकों की संख्या से भी कई गुणा सीटें अपनी राकांपा के लिए हासिल करने में सफल रहे। अजित पवार महायुति में होते हुए भी भाजपा की चुनावी रणनीति का मुखर विरोध करते दिखे।

जाने लगी है। खासतौर से चुनाव जितने खर्चीले होते जा रहे हैं, उसे देखते हुए धनबल की महत्ता बढ़ती जा रही है। ऐसे में धनाढ्य प्रत्याशियों को तरजीह मिलने लगी है। ऐसे दावेदारों को अगर कुछ कारणों से अपने दल से टिकट नहीं मिलता तो प्रतिद्वंद्वी दल उन्हें हाथोंहाथ अपना लेता है। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि दल की सदस्यता लेने के पांच मिनट में ही उक्त व्यक्ति को पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। आधे घंटे पहले तक किसी के पक्ष में रैली कर रहा नेता एकाएक दूसरे दल के मंच पर पहुंचकर उसकी पैरवी करने लगता है। यह भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की विडंबनाओं को ही उजागर करता है।

दलबदल पर विराम लगाने के लिए कोई कानूनी पहल अनिवार्य रूप से कारगर नहीं हो सकती। दलबदल निरोधक कानून के दुष्परिणामों को ही देख लीजिए। उसके लागू होने के बाद जनप्रतिनिधियों के व्यक्तिगत अधिकार बहुत सीमित हो गए हैं कि कई मुद्दों पर वे अपना पक्ष भी नहीं रख सकते। कई राजनीतिक प्रेक्षक इस स्थिति की व्याख्या ऐसे करते हैं कि दलबदल निरोधक कानून लागू होने के बाद जनप्रतिनिधि एक प्रकार से राजनीतिक दलों के बंधुआ बनकर रह गए हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि जनता स्वयं इस मामले में जागरूक होकर राजनीतिक दलों को जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने के लिए बाध्य करे। सभी दल हमारी राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी ढांचागत कमियों को दुरुस्त करने का काम करें और अर्से से लंबित राजनीतिक एवं चुनाव सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाएं।

अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों से इस मामले में कोई सीख ली जा सकती है। हमारे राजनीतिक दल पश्चिम की सुगठित एवं सुव्यस्थित राजनीतिक व्यवस्था के सकारात्मक बिंदुओं को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसमें प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया से लेकर चुनावी फंडिंग और राजनीतिक समायोजन की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पश्चिम के परिपक्व लोकतांत्रिक देशों में दलबदल जैसी कोई समस्या नहीं, लेकिन वह इतनी विकराल नहीं है। वहां नेताओं से लेकर राजनीतिक दल अपने वैचारिक आग्रह को लेकर खासे मुखर रहते हैं और विचारधारा की राजनीति ऐसी नहीं कि उसे एकाएक केंचुली की तरह बदल दिया जाए। जबकि भारत में विचारधारा की पालकी ढोने का दावा करने वाले नेता भी इस मामले में उसे कपड़ों की तरह बदल लेने से परहेज नहीं करते। ऐसे में यदि विचारधारा, आंतरिक लोकतंत्र और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया जाए तो दलबदल की बेलगाम होती समस्या पर एक बड़ी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है।

महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में जोड़तोड़-गठजोड़ से लेकर लोक लुभावन वायदों तक पर जोर बताता है कि सत्ता के दावेदारों को अपने दम पर भरोसा नहीं। ये दावेदार कभी-न-कभी सत्ता में रह चुके हैं। फिर ऐसा क्यों है कि उन्हें अपने काम पर जनादेश का विश्वास नहीं? इस सवाल का जवाब बिना दिए भी समझा जा सकता है। इसीलिए दोनों ही राज्यों में येन-केन प्रकारेण सत्ता हासिल करने के लिए जोड़तोड़-गठजोड़ से लेकर मुफ्त की रेवड़ियों तक हरसंभव बिसात बिछानी पड़ी। सत्ता के इस खेल में इस बात की परवाह किसी ने नहीं की कि इन राज्यों की पहले से खराब अर्थव्यवस्था के लिए उनकी चुनावी चालें कितनी घातक साबित होंगी।

दरअसल सत्ता की जंग में सबकुछ जायज मान लिया गया है, और इस काम में कोई किसी से पीछे नहीं। पिछले पांच साल महाराष्ट्र लगातार राष्ट्रीय राजनीति के भी केंद्र में बना रहा। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा-शिवसेना को मिले स्पष्ट बहुमत से लेकर मुख्यमंत्री पद पर टकराव और अलगाव तथा फिर बेमेल गठबंधनों के बीच सत्ता के खेल तक महाराष्ट्र ने राजनीतिक पतन के नए आयाम ही स्थापित किए। भाजपा ने शरद पवार की राकांपा से भतीजे अजित पवार की कुछ दिनों की बगावत के जरिये 80 घंटों की सरकार बनाकर अपनी साख दांव पर लगाई तो मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे ने उसी कांग्रेस से हाथ मिला लिया, जिसके विरुद्ध उनके पिता बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी। राजनीति की नाटकीयता यहीं समाप्त नहीं हुई। हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने सबसे पुराने और मुखर साथी रहे बाला साहेब के उत्तराधिकारी उद्धव को मुख्यमंत्री न बनाने वाली भाजपा ने उनकी शिवसेना तोड़ने वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और अपने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उपमुख्यमंत्री बनाकर अपनी साख फिर सवालिया निशान स्वयं लगा लिया। 80 घंटे की फडणवीस सरकार में उपमुख्यमंत्री रहकर राकांपा में लौट गए अजित में फिर बगावत ने अंगड़ाई ली और वह विधायकों के बहुमत के साथ पार्टी तोड़कर भाजपा-शिंदे शिवसेना की महायुति सरकार संग जाकर पांचवीं बार राज्य के उपमुख्यमंत्री बन गए। सत्ता के इस खेल में नीति-सिद्धांत-विचारधारा न इधर थी, न उधर। बस सत्ता की धारा ही सभी के सिर चढ़कर बोल रही थी। जब जैसे जिसको मौका मिल रहा था, वह सत्ता की धारा में डुबकी लगा रहा था।

● **इन्द्र कुमार**

नीति-सिद्धांत-विचारधारा न इधर है, न उधर

झारखंड का चुनावी परिदृश्य भी जोड़तोड़ और वायदों के मायाजाल से मुक्त नहीं है। तमाम आशंकाओं के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस-राजद गठबंधन सरकार कार्यकाल पूरा करने में सफल रही, लेकिन इस बीच एक मनी लांड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री पद छोड़कर हेमंत सोरेन को कुछ महीने जेल में गुजारने पड़े। उस दौरान मुख्यमंत्री बनाए गए चम्पाई सोरेन ही इस चुनाव में भाजपा के लिए आदिवासी क्षेत्रों में ट्रंप कार्ड बनते नजर आए। महाराष्ट्र में अगर पवार परिवार विभाजित हुआ तो झारखंड में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का परिवार टूट चुका है। उनकी भाभी सीता सोरेन भाजपा में हैं। चुनाव पूर्व दलबदल तो अब भारतीय राजनीति का स्थायी चरित्र बन गया है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लंबे समय से सक्रियता तथा बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा सरीखे मुख्यमंत्री रह चुके आदिवासी नेता होते हुए भी भाजपा के लिए चम्पाई सोरेन का इतना महत्वपूर्ण हो जाना बताता है कि बढ़त के संकेतों के बावजूद वह जीत के प्रति आश्वस्त नहीं थी।

योगी का नेतृत्व, संगठन का जमीनी काम

लोकसभा चुनाव के बाद उप्र में 9 सीटों पर उपचुनाव का स्कोर भाजपा के पक्ष में 7-2 रहा। इससे भी अहम पार्टी ने कटेहरी और कुंदरकी में तीन दशकों का सूखा खत्म किया। फ्रंट से लीड कर रहे उप्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे नारे ने कमाल किया। वहीं पार्टी संगठन की जमीनी तैयारियों व लोकसभा चुनाव के बाद मिले सबक के अलावा कई ऐसी बातें रहीं जिसने जमीन पर वोटरों को बूथ तक लाने में अहम भूमिका निभाई।

उप्र में 9 सीटों के उपचुनाव के नतीजे सरकार और संगठन के बेहतर तालमेल का संदेश देने के साथ ही आगे के सियासी सफर के लिए उम्मीद जगा रहे हैं। वजह ये भी है कि कुंदरकी और कटेहरी में भाजपा ने जीत का जो रास्ता तय किया उससे पार्टी को नई संजीवनी मिली। 2027 अभी दूर है पर इस चुनाव से मिली सीख पार्टी के रणनीतिकारों के लिए अहम है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि पार्टी संगठन ने ऐसा क्या किया जिससे जीत की इबारत लिखी जा सकी। सबसे अहम बात यह है कि ये चुनाव उप्र मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ा गया। उनकी रणनीति पर न सिर्फ सरकार के मंत्री सीट पर जिम्मेदारी संभालने पहुंचे, बल्कि संगठन ने भी उनको पूरा सपोर्ट किया।

लोकसभा चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास का जो ओवरडोज था, वो इस चुनाव में जा चुका था। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने ये बता दिया था कि कार्यकर्ताओं की उदासीनता और नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस किस तरह नतीजों को प्रभावित कर सकता है। इस बार उपचुनाव से पहले सदस्यता अभियान चलने की वजह से ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच थे। हर नेता व कार्यकर्ता को बाकायदा सदस्यता का टारगेट मिला था। ऐसे में उपचुनाव वाली सीटों पर भी डोर-टू-डोर पहुंचने से वोटरों से संपर्क और तालमेल बढ़ा। लोकसभा चुनाव के समय ऐसी कोई सक्रियता कार्यकर्ताओं में नहीं थी। यही वजह थी कि कार्यकर्ता घर पर बैठे थे। लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा बैठक में ये बात निकलकर आई थी कि कार्यकर्ता उदासीन हैं। इसको लेकर पार्टी को शिकायत भी मिली थी। इसे देखते हुए लोकसभा चुनाव के बाद तेजी से न सिर्फ कार्यकर्ताओं का समायोजन किया गया, बल्कि उनको कई बार ये संदेश भी प्रदेश नेतृत्व की तरफ से दिया गया कि उनके सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। सरकार ने महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, सेवा आयोग जैसे आयोगों का पुनर्गठन किया और कई कार्यकर्ताओं, नेताओं को समायोजित किया। इससे दूसरे कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी संदेश दिया कि सरकार में कार्यकर्ताओं को भी महत्व दिया जा रहा है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की मायूसी खत्म करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगठन के शीर्ष नेताओं के साथ उपचुनाव की प्लानिंग लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद शुरू कर दी थी। उपचुनाव में योगी सरकार और प्रदेश संगठन का तालमेल भी देखने को मिला। योगी के सुपर-30 फार्मूला ने काम कर दिखाया। यानि मंत्रियों को सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा हर क्षेत्र में जातीय संतुलन साधने के लिए भी 10-10 विधायकों को लगाया गया था। ये वो विधायक रहे जिनको उस क्षेत्र के जातीय गणित को देखते हुए लगाया गया था। ये रणनीति भी कारगर रही। इसके साथ तालमेल बनाकर संगठन के पदाधिकारियों खासतौर पर महामंत्री, उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्रियों को लगाया गया था। इससे इन कार्यकर्ताओं को उस विधानसभा की जमीन समझने और काम करने के लिए काफी समय मिल गया। भले ही ये उपचुनाव हों पर भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तरह ही रणनीति बनाकर काम किया। चुनाव का पूरा मैनेजमेंट देखने को मिला। मुख्यमंत्री आवास पर हर बैठक के बाद मुख्यमंत्री और प्रदेश नेतृत्व की बात को जनता तक पहुंचाने और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने का काम जारी रहा। इसमें संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की भी अहम भूमिका रही।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

उप्र में योगी ने क्या लोकसभा की हार का बदला लिया है?

लोकसभा में बहुमत का ताला उप्र की चाबी से खुलता है। 5 महीने पहले उप्र से भाजपा के 29 सांसद कम हो गए। योगी से सवाल हुए, उनकी लीडरशिप पर सवाल उठे। तभी से योगी ने अपनी वर्किंग और स्ट्रैटजी दोनों में व्यापक बदलाव किए। कार्यकर्ताओं से जुड़ाव बढ़ाया और अफसरशाही को स्पीडी रिजल्ट देने वाला बनाया। योगी की छवि को जो डेंट लोकसभा चुनाव में लगा था, उसे उन्होंने चैलेंज के रूप में लिया। इसीलिए दो सबसे कठिन सीटों की जिम्मेदारी अपने पास रखी। 3 महीने पहले हर सीट की व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों को दी, लगातार रिव्यू करने लगे। राजनीति में समीकरण बदलते देर नहीं लगती, लेकिन यह तय है कि इन नतीजों से माहौल भाजपा का बनेगा। लोकसभा नतीजों के बाद जैसी ऊर्जा सपा में आ गई थी, वही एनर्जी अब भाजपा में दिखाई देगी। लोकसभा से सबक लेकर योगी सरकार ने नौकरी, पर्चा लीक, अफसरशाही जैसे मसलों पर सख्त फैसले लिए हैं। आगे इनमें तेजी आएगी, जिससे माहौल बनेगा। इसका फायदा भाजपा को 2027 में मिल सकता है। उपचुनाव में भाजपा की जबरदस्त जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी और कई मंत्री-नेता लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पहुंचे। जीत की खुशी में आतिशबाजी की। उपचुनाव में भाजपा की जबरदस्त जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी और कई मंत्री-नेता लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पहुंचे। जीत की खुशी में आतिशबाजी की। निश्चित तौर पर संगठित पार्टी होने के बावजूद भाजपा में कई ध्रुव हैं। चुनाव के दौरान योगी ने नई लाइन दी- बंटेंगे तो कटेंगे...। बाकी भाजपा नेताओं ने अलग-अलग शब्दों में इसका इस्तेमाल किया।

मैनेजमेंट से जीत, ओवरकॉन्फिडेंस से हार

6 बड़ी पार्टियां और तकरीबन इतने ही छोटे दल। इनमें से महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित पवार) की तिकड़ी को चुना और विधानसभा चुनाव में महायुति को बहुमत दिया। तीनों पार्टियों ने 230 सीटों पर जीत हासिल की है। इस मैंडेट ने साफ कर दिया है कि कौन असली और कौन नकली शिवसेना है? और चाचा-भतीजे में बड़ा कौन है? 1972 के बाद ये पहला मौका है, जब किसी अलायंस को इतना बड़ा मैंडेट मिला है। चुनाव से 4 महीने पहले शुरू की गई महायुति सरकार की लाड़की बहिन योजना गेम चेंजर बनी। इस चुनाव में भाजपा के माइक्रो-मैनेजमेंट ने कामयाबी दिलाई। इस बार भाजपा को संघ के एक्टिव होने का भी फायदा मिला। आरएसएस ने लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में तकरीबन 2000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं कीं। कार्यकर्ता घर-घर जाकर वोटर्स को बूथ पर लाने में सफल रहे। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी रैलियों में बंटेंगे तो कटेंगे के नारे ने हिंदू वोटर को एकजुट किया। महाराष्ट्र में योगी का स्ट्राइक रेट 100 प्रतिशत रहा। इधर, महाविकास अघाड़ी (एमवीए) ने चुनाव से ठीक पहले पांच गारंटी देने की बात की थी, लेकिन वो ये गारंटियां जनता तक पहुंचाने में नाकाम रही। एमवीए 50 से भी कम सीटों पर सिमटकर रह गई।

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि महायुति की जीत के पीछे एक बड़ी चुनावी रणनीति थी। महाराष्ट्र में 4 महीने पहले शुरू की गई लाड़की बहिन योजना गेमचेंजर बनी। ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों की झुग्गी-बस्तियों में इसका बहुत असर देखने को मिला। इसके अलावा 25 हजार महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती, सीनियर सिटीजन की पेंशन 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने और हर महीने 25 लाख नौकरियां, 10 लाख छात्रों को 10 हजार रुपए महीना ट्यूशन फीस देने का वादा महायुति की छवि को मजबूत करने में कामयाब रहा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा ने संघ के साथ अपने मतभेद सुलझाए। केरल में हुई आरएसएस की समन्वय बैठक में जेपी नड्डा खुद शामिल हुए। उन्होंने संघ प्रमुख से बात कर महाराष्ट्र चुनावों की प्लानिंग की। संघ ने लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं कीं। संघ कार्यकर्ता घर-घर जाकर वोटरों को बूथ तक लाने में सफल रहे। माना जा रहा है कि बूथ लेवल और सीट लेवल पर आरएसएस ने काम कर महार, मतंग और आदिवासी समाज को अपनी ओर खींचने का काम किया। विदर्भ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। आरएसएस ने उसे भी भेदने का काम किया।

लोकसभा चुनाव में महायुति को सबसे ज्यादा नुकसान मराठा आंदोलन की वजह से हुआ था। वो आंदोलन अब ठंडा पड़ता दिख रहा है। मनोज जारंगे पाटिल ने लोकसभा की तरह विधानसभा में भी कैंडिडेट उतारे, लेकिन अचानक उन्हें वापस ले लिया। इस रुख से मराठा वोटर कन्फ्यूज नजर आया। उसने महायुति के साथ जाने का मन बना लिया। महाराष्ट्र में 33 प्रतिशत से ज्यादा मराठा वोटर्स हैं। 2019 में 160 मराठा विधायक बने। मराठा वोटर्स पर शिवसेना (यूबीटी) और शिवसेना (शिंदे गुट), एनसीपी (शरद पवार) और एनसीपी का कब्जा है। महायुति ने बिजली बिलों में 30 प्रतिशत की कमी और सौर ऊर्जा पर जोर देने का वादा किया। किसानों की कर्जमाफी, एमएसपी पर 20 प्रतिशत की सब्सिडी और शेतकरी सम्मान योजना की राशि 12 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपए करने का वादा किया। ऐसा कर 90 विधानसभा क्षेत्रों में किसानों का गुस्सा कम करने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर महाराष्ट्र के किसान प्याज के एक्सपोर्ट और विदर्भ के किसान सोयाबीन का रेट न मिलने से नाराज चल रहे थे। वैसे तो दोनों ही अलायंस में बागी थे, लेकिन महाविकास अघाड़ी को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। उनके 40 बागी उम्मीदवार पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे। उन्होंने महाविकास अघाड़ी के वोटबैंक में ही सेंध लगाई।

लोकसभा चुनाव में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को लेकर जो सहानुभूति की लहर थी, वो इस चुनाव में नहीं दिखी। बारामती की बात करें तो वहां सिर्फ एक ही नारा सुनाई दिया- लोकसभा में ताई और विधानसभा में दादा। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में वहां अजित पवार मजबूत स्थिति में नजर आए। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कम ही रैलियां रहीं। इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की महाराष्ट्र में सिर्फ 10 रैलियां हुईं। जानकारों के मुताबिक, लोकसभा चुनाव में जिन जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार और उद्धव पर निशाना साधा, वहां भाजपा या महायुति उम्मीदवारों को नुकसान हुआ। शरद पवार को भटकती आत्मा वाले बयान का भी निगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। बंटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर भाजपा ने हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने के लिए एकजुट किया।

● **बिन्दु माथुर**

डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट योजना कारगर साबित हुई

मुंबई की सियासी नब्ज को समझने वाले जानकार कहते हैं, कि महायुति को क्लीन विक्ट्री मिली है। मौजूदा सरकार को अपनी जिस स्कीम पर सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने काम किया है। उनकी महिलाओं तक 1500 रुपए पहुंचाने की डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट योजना लाड़की बहिन थी, वो कारगर साबित हुई। दीपावली से पहले जिस तरीके से महिलाओं को 7500 रुपए मिले, उसने पूरा गेम चेंज कर दिया। इसने एकसाथ 6 प्रतिशत महिलाओं के वोट में इजाफा कर दिया। इस चुनाव में 53 सीटों पर शिवसेना बनाम शिवसेना और 36 सीटों पर एनसीपी बनाम एनसीपी के बीच लड़ाई थी। जानकार कहते हैं कि इन नतीजों ने भाजपा को काफी मजबूत स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब शिंदे उनके लिए इतने जरूरी नहीं रह गए हैं। चुनाव से कुछ दिन पहले तक महाराष्ट्र का समीकरण कुछ ऐसा था कि दोनों ही अलायंस (महायुति और महाविकास अघाड़ी) के बीच में कुछ ही सीटों का अंतर था। अभी जो नतीजे आए हैं, उसने सारे समीकरण बदल कर रख दिए हैं।

मोदी नीति से जीता उपचुनाव

तीन माह पहले ही सक्रिय, आखिरी तक हार नहीं मानी

एक तरफ जहां कांग्रेस ने उपचुनावों में हर मामले में देरी की, वहीं भाजपा ने लोकसभा चुनाव में मिले झटके से सबक लेते हुए तीन माह पहले से ही उपचुनावों में जीत की रणनीति पर काम शुरू कर दिया था। पार्टी ने मंत्रियों, संगठन के पदाधिकारियों को उपचुनाव वाले क्षेत्रों में ही रहने को कह रखा था। इसका असर ये हुआ कि पार्टी ने मतदान से पहले ही लोगों की गाहे-बगाहे सामने आने वाली नाराजगी दूर करने में भी कामयाबी हासिल कर ली। झुंझुनूं में बगावत हुई, उसे भी समय रहते नियंत्रण में कर लिया गया। खींवसर सीट पर जातिगत दबाव इतना हावी था कि भाजपा समर्थित अन्य जातियां वोट देने ही नहीं निकलती थीं। ये मतदाता भी इस बार भाजपा के पक्ष में खुलकर सामने आए। पार्टी नेताओं को सलूम्बर में जीतने की उम्मीद कम ही थी, लेकिन पार्टी नेताओं ने हर सीट पर उपचुनाव को आम चुनाव की तरह ही लड़ा।

राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का विश्लेषण करें तो भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे बड़ा कारण जातिवाद को चुनावी रणनीति से दूर रखने का माना जा रहा है। यही वजह है कि अब तक जातिगत समीकरणों के आधार पर हार-जीत तय करने वाली खींवसर और झुंझुनूं जैसी सीटें जीतकर पार्टी ने नया इतिहास भी रच दिया। उपचुनावों को फतह करने की रणनीति शीर्ष स्तर पर उस समय ही बनना शुरू हो गई थी जब भाजपा हरियाणा की चुनावी रणनीति तय करने में जुटी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से चुनावों को जातिगत बंधनों से मुक्त करने की कवायद में जुटे थे। इसके लिए पार्टी ने प्रधानमंत्री के निर्देश पर युवा, किसान और महिलाओं को फोकस करते हुए प्रदेश की सातों सीटों पर चुनाव प्रचार किया और इसके परिणाम भाजपा के पक्ष में आए।

प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और इसके बाद सबसे ज्यादा फोकस प्रदेश की बड़ी समस्याओं पर रहा। इसमें किसानों को दिन में बिजली, समय पर पानी, युवाओं को रोजगार जैसे मुद्दे थे। सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले निर्देश के तहत ही भजनलाल सरकार ने किसानों को दिन में बिजली देने का वादा करते हुए ऊर्जा क्षेत्र में कई काम शुरू किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी चुनावी सभाओं में यह जरूर कहते कि वे किसानों को दो से तीन साल के अंदर-अंदर दिन में बिजली देंगे, जिससे उन्हें रात में परेशान नहीं होना पड़ेगा। युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया। सत्ता में आते ही भाजपा सरकार ने प्रदेश में शेखावाटी क्षेत्र में पानी की परेशानी को दूर करवाने की तरफ कदम बढ़ाए और यमुना जल समझौते को लेकर काम शुरू किया। लोकसभा चुनाव में तो इसका फायदा भले ही नहीं मिल पाया लेकिन हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने से शेखावाटी और मारवाड़ के किसानों को पार्टी यह भरोसा दिलाने में कामयाब रही कि अब उन्हें यमुना का राजस्थान के हक का पूरा पानी मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में सात विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव के परिणाम से प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ आ गया हैं और इस बार जहां भारतीय जनता पार्टी के विकास के नारे को बल मिला और कई वर्षों से अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा जमाए बैठे नेताओं एवं परिवारों का वर्चस्व समाप्त हो गया, वहीं प्रदेश की भजनलाल सरकार को दिए जा रहे पर्ची, सर्कस और यूटर्न सरकार आदि नामों की भी पोल खुल गई और इससे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सियासी कद और बढ़ गया। उपचुनाव की सात सीटों में पांच सीटें भाजपा ने जीतकर यह साबित कर दिया कि भाजपा ने चुनाव में विकास की जो बात कही उसे बल मिला है। वहीं शर्मा के कुशल राजनीतिक नेतृत्व के चलते खींवसर, झुंझुनूं एवं रामगढ़ में कई वर्षों से राजनीतिक प्रतिष्ठा जमाए बैठे दिग्गज नेताओं के सियासी गढ़ इस उपचुनाव में ढह गए। इससे यह भी संदेश गया कि अब पुराने एवं दिग्गज नेता का प्रभाव काम नहीं आता, जनता काम भी चाहती है और वह नए नेताओं को भी काम करने का मौका देना चाहती हैं और वह इस उपचुनाव में नजर भी आया। इस बार खींवसर से भाजपा प्रत्याशी रेवंतराम डांगा, झुंझुनूं से राजेंद्र भांबू, रामगढ़ से सुखवंत सिंह एवं सलूंबर से शांता मीणा, दौसा से कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा तथा चौरासी से भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कुमार कटारा पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता है। केवल देवली-उनियारा में पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर ने 11 साल बाद फिर से चुनाव जीता हैं।

इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने भजनलाल सरकार को पर्ची सरकार नाम दे दिया कि दिल्ली से जो पर्ची आएगी भजनलाल वही काम करते हैं। इसके बाद भजनलाल सरकार को सर्कस एवं यूटर्न सरकार भी कहा गया, लेकिन जब उपचुनाव के परिणाम लोगों के सामने आए और भाजपा को सात में से पांच सीटें मिलीं और वह भी दिग्गज नेताओं के गढ़ में तो इन बातों की हवा निकल गई। क्योंकि इन बातों का जनता पर कोई असर नहीं पड़ा। नागौर जिले में प्रसिद्ध मिर्धा परिवार को पछाड़कर खींवसर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2008 से अपना राजनीतिक दबदबा बनाए रखने वाले सांसद हनुमान बेनीवाल का परिवार इस बार उपचुनाव में हार गया। वर्ष 2008 से पहले खींवसर की जगह मूंडवा विधानसभा क्षेत्र था जहां भी हनुमान बेनीवाल के पिता दो बार विधायक रहे थे। ऐसे में बेनीवाल परिवार को शिकस्त देना काफी कठिन लग रहा था लेकिन भजनलाल की कुशल राजनीति के चलते यह संभव हो पाया और दिग्गज सियासी गढ को ढहा दिया गया। झुंझुनूं में आजादी के बाद से सर्वाधिक बार जीतने वाली कांग्रेस के शीशराम ओला एवं उनके परिवार का सात बार इस सीट पर कब्जा रहा लेकिन इस बार यह सियासी गढ़ भी ढह गया। इसी तरह रामगढ़ में भी पूर्व विधायक जुबैर खान के परिवार का राजनीतिक वर्चस्व भी इस उपचुनाव में समाप्त हो गया और जनता ने परिवारवाद को नकार दिया। देवली-उनियारा में भाजपा के जीतने पर कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो गया।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन
प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

जन सुराज ने सभी को डराया

चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर जिस जन सुराज के सूत्रधार हैं, वह चार सीटों के उपचुनाव से अपने चुनावी डेब्यू में जीरो पर रही। पार्टी के उम्मीदवार तीन सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे। एक सीट पर पार्टी चौथे स्थान पर रही। ऐसे प्रदर्शन के बावजूद पीके की पार्टी एनडीए और महागठबंधन के लिए टेंशन क्यों है?

बिहार की चार विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर (पीके) की जन सुराज पार्टी खाली हाथ रही। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार को कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा जबकि बाकी तीन सीटों पर पीके के कैंडिडेट तीसरे स्थान पर रहे। पहली नजर में ये नतीजे पीके की पार्टी के प्रभावहीन स्टार्ट की कहानी बयान करते लगते हैं लेकिन आंकड़ों का अंकगणित सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी महागठबंधन, दोनों ही गठबंधनों में शामिल दलों की टेंशन बढ़ाने वाला है।

गया जिले की इमामगंज विधानसभा सीट पर जन सुराज के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को 37 हजार 103 वोट मिले। बेलागंज में जन सुराज के मोहम्मद अमजद 17 हजार 285 वोट पाने में सफल रहे। तरारी सीट पर जन सुराज की किरण सिंह को 5622 और रामगढ़ में सुशील कुमार सिंह को 6513 वोट मिले। जन सुराज के चारों उम्मीदवारों को मिले कुल वोट का योग 66 हजार 523 पहुंचता है। औसत की बात करें तो जन सुराज को अपने चुनावी डेब्यू में मिले वोट का औसत हर सीट पर 16 हजार 631 वोट के करीब है।

जन सुराज पार्टी भले ही विधानसभा में अपनी मौजदूगी सुनिश्चित करने में विफल रही हो लेकिन वह ये साबित करने में सफल रही है कि दूसरे दलों का गेम बना और बिगाड़ सकती है। रामगढ़ और इमामगंज के नतीजे तो यही बता रहे हैं। लालू यादव की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का गढ़ माने जाने वाले रामगढ़ विधानसभा सीट से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजित सिंह तीसरे नंबर पर रहे। इस सीट पर भाजपा के अशोक कुमार सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के सतीश कुमार सिंह यादव को 1362 वोट से शिकस्त दी।

रामगढ़ में जन सुराज उम्मीदवार को छह हजार से ज्यादा वोट मिले थे। इसी तरह इमामगंज में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी की जीत का अंतर 5945 रहा और जन सुराज उम्मीदवार को 37 हजार से ज्यादा वोट मिले। इन दो सीटों पर जन सुराज की मौजूदगी ने आरजेडी को नुकसान पहुंचाया और अगर चुनावी रण में पीके की पार्टी नहीं होती तो नतीजे कुछ और भी हो सकते थे।

चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर जिस जन सुराज पार्टी के कर्णधार हैं, सूत्रधार हैं, वह चार सीटों के उपचुनावों में तीसरे नंबर से आगे नहीं बढ़ सकी है। लेकिन इस प्रदर्शन के जरिये भी जन सुराज ने पुरानी पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है तो उसकी भी अपनी वजहें हैं। इसे चार पॉइंट में समझा जा सकता है। जन सुराज के सियासी दल बनने का ऐलान 2 अक्टूबर को ही हुआ था। पार्टी अभी संगठन का गठन करने की प्रक्रिया में ही है। गया, आरा और कैमूर जिले में जन सुराज पार्टी का संगठन भी अभी गठित नहीं हुआ था कि उपचुनाव की तारीखें आ गईं। जन सुराज ने बगैर संगठन के यह उपचुनाव लड़ा। एक तरफ जहां सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन की ओर से स्टार प्रचारकों की टीम प्रचार के मोर्चे पर सक्रिय नजर आई, वहीं दूसरी तरफ जन सुराज की कोई बड़ी रैली नहीं हुई।

बिहार की इन चार सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान हुआ था और जन सुराज को औपचारिक रूप से राजनीतिक दल बने तब डेढ़ महीने भी नहीं हुए थे। नई नवेली पार्टी को बगैर किसी पूर्व तैयारी, बगैर संगठन के सीधे चुनावी टेस्ट में जाना पड़ा। नौबत तो यह भी आई कि जन सुराज को चार में से दो उम्मीदवार बदलने भी पड़े। पीके की पदयात्रा भी इन इलाकों तक नहीं पहुंची है। इन सबके बावजूद जन सुराज ने जीतनराम मांझी के गढ़ इमामगंज और आरजेडी के मजबूत किले बेलागंज में प्रभावी प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी को तैयारी के लिए करीब एक साल का समय मिलेगा।

पीके अपनी जन सुराज पदयात्रा के दौरान परिवारवाद को लेकर लालू यादव और आरजेडी पर हमलावर रहे हैं। उपचुनावों में रामगढ़ और बेलागंज, दोनों ही सीटों पर आरजेडी ने फैमिली कार्ड ही चला था। रामगढ़ में बक्सर सीट से सांसद निर्वाचित होने के पहले विधायक रहे सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह आरजेडी के उम्मीदवार थे। वहीं, बेलागंज में भी पार्टी ने सांसद निर्वाचित होने के बाद सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव पर दांव लगाया था। इन दोनों ही सीटों पर आरजेडी उम्मीदवारों की हार, इमामगंज में जीतनराम मांझी की बहू के कड़े मुकाबले में फंसने को पीके के परिवारवाद विरोधी नैरेटिव से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

● **विनोद बक्सरी**

चिराग-मांझी की पार्टियों से अधिक वोट शेयर

बिहार उपचुनाव में जन सुराज का वोट शेयर करीब 10 फीसदी रहा है। लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे क्षत्रपों की मौजूदगी और भाजपा की चुनौती के बीच डेब्यू में यह स्कोर खराब भी नहीं है। बिहार के वोटगणित की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से तीन सबसे बड़ी पार्टियों का वोट शेयर 15 से 24 फीसदी के बीच ही रहा था। साल 2020 के बिहार चुनाव में आरजेडी को 23.5, भाजपा को 19.5 और जेडीयू को 15.7 फीसदी वोट मिले थे। चिराग पासवान की अगुवाई वाली एलजेपी को तब 5.8 फीसदी वोट मिले थे। जीतनराम मांझी की पार्टी का कोर वोटर माने जाने वाले मुसहर समाज की आबादी में भागीदारी तीन फीसदी के करीब ही है। ऐसे में पीके की पार्टी का 10 फीसदी वोट शेयर ले जाना छोटी पार्टियों के साथ ही बड़े दलों के लिए भी टेंशन देने वाला है।

औकात में आया कनाडा

खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार बैकफुट पर आ गई है। कनाडा सरकार ने कहा कि भारत में वांछित निज्जर की हत्या में भारत के होने का उसके पास कोई सबूत नहीं है। ट्रूडो सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर कभी कोई आरोप नहीं लगाया। प्रिवी काउंसिल के डिप्टी क्लर्क और प्रधानमंत्री ट्रूडो के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खुफिया सलाहकार नथाली जी ड्रौइन ने कहा, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण और जारी खतरे के कारण आरसीएमपी (रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस) और अधिकारियों ने 14 अक्टूबर को कनाडा में भारत सरकार के एजेंटों द्वारा की गई गंभीर आपराधिक गतिविधि के सार्वजनिक आरोप लगाने का असाधारण कदम उठाया।

प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने आगे कहा, कनाडा सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर या एनएसए डोभाल को कनाडा के भीतर गंभीर आपराधिक गतिविधि से जोड़ने के बारे में कभी नहीं कहा है और ना ही इससे जुड़े सबूतों की उसे जानकारी है। इसके विपरीत, कोई भी सुझाव काल्पनिक और गलत दोनों है। ट्रूडो सरकार का ये स्पष्टीकरण कनाडा के एक अखबार द ग्लोब एंड मेल में छपी रिपोर्ट के बाद आया है। उस अखबार में भारत पर आरोप लगाते हुए कहा गया था कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या की साजिश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रची थी। इसमें यह भी कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल को इस योजना की जानकारी थी। यह रिपोर्ट एक अनाम कनाडाई अधिकारी के हवाले से छापी गई थी।

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इसको लेकर कनाडा के पास प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इस मीडिया रिपोर्ट को विदेश मंत्रालय ने 20 नवंबर को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के बेतुके बयानों को खारिज कर देना चाहिए। इससे पहले 14 अक्टूबर 2024 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर अपमानजनक आरोप लगाए थे और कनाडा की धरती पर हत्याओं को अंजाम देने का दावा किया था। आरसीएमपी के हवाले से उन्होंने कनाडा में दक्षिण एशियाई समुदाय, खालिस्तान समर्थक आंदोलन से जुड़े लोगों को निशाना बनाने वाले हिंसक खतरों की एक श्रृंखला खोज निकालने का दावा किया था।

इन खतरों में हत्याएं और जबरन वसूली शामिल हैं, जो कनाडाई कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों के बावजूद जारी हैं। आरसीएमपी ने कहा कि उसने कनाडा की धरती पर भारत सरकार के एजेंटों द्वारा संचालित आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए फरवरी 2024 में एक टीम बनाई थी। जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया था कि कनाडा के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। इस बयान में भारत सरकार का 10 बार जिक्र किया गया है, जबकि भारत का 13 बार। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने पिछले साल कनाडा की संसद में बोलते हुए भी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। भारत ने ट्रूडो और उनकी पार्टी पर खालिस्तानियों को लुभाने के लिए वोटबैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया था।

पिछले साल जून में कनाडा के सर्रे शहर में स्थित एक गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निज्जर अलगाववादी खालिस्तानी आतंकी था। वह आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था। भारत में वांछित निज्जर पिछले कई वर्षों से कनाडा में रह रहा था और लोगों को भारत सरकार के खिलाफ उकसा रहा था। एनआईए ने उस पर 10 लाख रुपए का ईनाम भी घोषित किया था। कनाडा क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से भी धनी है। दुनिया की सात सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के समूह जी-7 में शामिल होने की प्रतिष्ठा रखता है। लेकिन, बात-बात पर भारत से झगड़ा करने वाले इस देश की अंदरूनी हालत खराब है। यहां के आम लोग महंगे घर, महंगे कर्ज और महंगे खाने से त्रस्त हैं। हालात ऐसे हैं कि तमाम संसाधन और दौलत रखने वाले इस देश के लाखों लोगों को दो वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा के टोरंटो में 10 से दो लोग खाने के लिए फूड बैंकों पर निर्भर हैं। कनाडा में फूड बैंक से खाना मांगकर खाने वालों की तादाद में साल-दर-साल आधार पर 36 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है। डेली ब्रेड फूड बैंक के मुताबिक पिछले साल टोरंटो में फूड बैंकों में 34.9 लाख से ज्यादा लोगों ने भोजन की मांग की थी। यह संख्या सालाना आधार पर 10 लाख ज्यादा है। इसके अलावा कोविड महामारी की तुलना में फूड बैंक से खाना मांगने वालों की संख्या में 273 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कनाडा में भुखमरी के हालात को बयां करने वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई और दूसरे कारणों से टोरंटो के 24.9 प्रतिशत से ज्यादा परिवार खाद्य असुरक्षा से प्रभावित हैं। इसके अलावा फूड बैंक आने वाले हर 3 में से 1 व्यक्ति को दिन में एक बार भी खाना नहीं मिलता है, जबकि 50 प्रतिशत ऐसे होते हैं, जिन्हें एक वक्त का खाना मिल पाता है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

कनाडा में बढ़ रही गरीबी

कनाडा में गरीबी को दर्शाने वाले एक आधिकारिक पोर्टल के डैशबोर्ड से पता चलता है कि वहां 2015 से 2020 तक गरीबी के स्तर में गिरावट आई थी, लेकिन 2021 से इसमें वृद्धि हो रही है। 2022 तक यह 9.9 प्रतिशत पहुंच गई। टोरंटो में स्थिति और भी गंभीर है, जहां 2022 तक 8 में से 1 व्यक्ति यानी कुल जनसंख्या का करीब 12.6 प्रतिशत तबका गरीबी में जी रह रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में कनाडा में गरीबी में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस दौरान गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों की संख्या में भी 38.9 प्रतिशत फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जबकि, खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले कनाडाई लोगों की तादाद 31 प्रतिशत बढ़ गई है। रिपोर्ट कहती है कि तमाम संकेत हैं, जिनसे पता चलता है कि बड़ी संख्या में कनाडाई लोग गरीबी में फंस रहे हैं।

स्वस्थ रहें... मस्त रहें

जनहित में जारी

जीवन हमारा है... तो जिम्मेदारी भी हमारी

सावधानी बरतें

- मच्छरों से बचें।
- साफ-सफाई पर ध्यान दें।
- घर के आसपास कचरा न करें।
- ढंके हुए पानी का उपयोग करें।
- बीमारी पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, लापरवाही न करें।
- शौच के लिए शौचालय का ही इस्तेमाल करें।

मेहता एंड एसोसिएट्स, इंदौर (मध्यप्रदेश)

भारत के अनुकूल ट्रंप प्रशासन

राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन को आकार देना भी शुरू कर दिया है। इससे उनके व्यापक दृष्टिकोण एवं भावी नीतियों की भी कुछ झलक दिखाई पड़ती है। चूंकि अमेरिका एक बहुत ही तल्ख एवं तनाव भरे चुनावी दौर से गुजरा है तो नए प्रशासन पर भी उसकी तात्कालिक छाप दिखाई दे रही है। अपने नए प्रशासन के चयन में स्पष्ट है कि ट्रंप ने उन मुद्दों पर मुखर लोगों को चुना है, जिन्हें उन्होंने अपने चुनाव अभियान के केंद्र में रखा। साथ ही अपने वफादारों पर भी उन्होंने भरपूर मेहरबानी दिखाई है।

अगले साल की शुरुआत में जब बतौर राष्ट्रपति वह दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे तो सूजी वाइल्स उनकी चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका में रहेंगी। यह पद संभालने वाली वाइल्स पहली महिला होंगी। वह ट्रंप के चुनाव अभियान संचालन के शीर्ष से जुड़ी रहीं और उनकी सफलता और सुगठित चुनाव अभियान का श्रेय एक बड़ी हद तक वाइल्स को दिया जा रहा है। जहां तक ट्रंप के मूल मुद्दों की बात है तो पूरे चुनाव अभियान में ही उन्होंने अवैध अप्रवासियों का मुद्दा केंद्र में रखा। अवैध अप्रवासियों को ट्रंप अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर अमेरिकी नागरिकों के लिए खतरा मानते हैं। चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने कई बार दोहराया है कि उनका प्रशासन करीब एक करोड़ अवैध अप्रवासियों को खदेड़कर ही दम लेगा। इतने बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की राह में आने वाली संभावित बाधाओं को दरकिनार करते हुए ट्रंप ने कहा कि इस अभियान की जटिलताओं और लागत की उन्हें परवाह नहीं और इसे किसी भी तरह अंजाम दिया जाएगा। इस अभियान की कमान संभालने का जिम्मा उन्होंने टाम होमन को सौंपा है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के मुखिया बने टाम होमन का इस मुद्दे पर आक्रामक रुख किसी से छिपा नहीं है। वहीं, उप नीति प्रमुख के रूप में स्टीवन मिलर के पास भी इसका एक बड़ा दारोमदार होगा।

अमेरिकी राजनीति में विदेश नीति की अपनी महत्ता है और राष्ट्रपति के बाद प्रशासन में अगर सबसे अधिक नजरें किसी नियुक्ति पर लगी होती हैं तो संभवत: वह विदेश मंत्री का पद होता है। इसका एक बड़ा कारण शेष विश्व के साथ अमेरिका की सक्रियता और उसका वैश्विक प्रभाव है। इस पद के लिए ट्रंप ने सीनेटर मार्को रुबियो को चुना है और उनके चयन की वजह भी एकदम स्पष्ट है कि वह चीन से लेकर ईरान तक सख्त विदेश नीति बनाने की वकालत करते आए हैं। ट्रंप चीन को अमेरिकी प्रभुत्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं और उसकी काट तलाशने का जिम्मा रुबियो पर होगा। इसी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए पद पर भी लोगों की नजरें टिकी होती हैं। उसके लिए ट्रंप ने तमाम चर्चित नामों के बीच माइक वाल्ट्ज को चुना है, जो चीन से लेकर पाकिस्तान के प्रति सख्य रवैये के लिए जाने जाते हैं। वाल्ट्ज इंडिया काकस यानी भारत के पक्ष में आवाज बुलंद करने वाले मंच के बेहद सक्रिय सदस्य रहे हैं।

खुफिया विभाग की निदेशक के रूप में हिंदू अमेरिकी तुलसी गबार्ड का चयन भी बहुत कुछ संदेश देता है। गबार्ड यही मानती आई हैं कि अमेरिका को विश्व में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। उनका यह दृष्टिकोण ट्रंप की व्यापक नीतियों से काफी मेल खाता है और वह इस महत्वपूर्ण पद के लिए पहली पसंद बनने में सफल रहीं। स्वास्थ्य मंत्री के लिए राबर्ट कैनेडी जूनियर का चयन भी काफी चर्चा में है। स्वास्थ्य को लेकर पारंपरिक दृष्टिकोण रखने वाले कैनेडी जूनियर वैक्सीन से जुड़ी मुहिम को लेकर भी चर्चा में रह चुके हैं। इन तमाम नियुक्तियों के बीच रक्षा मंत्री के रूप में पीट हेगसेथ का चयन जरूर कुछ चौंकाने वाला रहा। इस अहम जिम्मेदारी के लिए हेगसेथ के पास बहुत ज्यादा प्रशासनिक अनुभव नहीं है और हाल तक वह एक टिप्पणीकार के रूप में ही सक्रिय रहे। उनकी नियुक्ति पर रिपब्लिकन खेमे के बीच से कुछ सवाल भी उठे, लेकिन ट्रंप के व्यक्तित्व को देखते हुए ऐसे प्रश्न सतह पर ही तैरते रहे।

ट्रंप के प्रशासन के इस स्वरूप को देखते हुए कुछ जानकार यह कह रहे हैं कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने विशेषज्ञता या काबिलियत पर वफादारी को वरीयता दी है। उनकी टीम में चीफ ऑफ स्टाफ से लेकर एनएसए तक सभी नाम ऐसे हैं, जो लंबे समय से उनके वफादार रहे। यहां तक कि मुखर होकर उनके चुनाव अभियान का समर्थन कर रहे दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क के लिए तो ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जैसे नए विभाग का गठन कर दिया है, जिसमें भारतीय मूल के अमेरिकी विवेक रामास्वामी उनके जोड़ीदार होंगे। चुनाव के दौरान इंटरनेट मीडिया पर डीओजीई के रूप में सामने आया यह शिगूफा अब साकार रूप ले चुका है। ट्रंप प्रशासन में अगर किसी एक पहल पर सबसे अधिक निगाहें टिकी हुई हैं तो वह यही विभाग है। इस विभाग को जिम्मा दिया गया है कि वह सरकारी फिजूलखर्ची को चिन्हित कर उसे घटाने के उपाय तलाशे। इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को जुलाई 2026 तक का समय दिया है। इसी वर्ष अमेरिका अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाएगा। सरकारी खर्च को घटाना भी ट्रंप के प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक रहा है।

● **ज्योत्सना**

ट्रंप प्रशासन की नई तस्वीर उम्मीदें जगाने वाली

भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ट्रंप प्रशासन की नई तस्वीर उसके लिए उम्मीदें जगाने वाली है। ट्रंप प्रशासन की नीतियों से न केवल भारत के एक बड़े लाभार्थी बनने के आसार हैं, बल्कि भूराजनीतिक मोर्चे पर भी उसका वजन बढ़ेगा। ट्रंप प्रशासन में अधिकांश चेहरे भारत समर्थक हैं। इससे भी बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच आत्मीय रिश्तों के चलते यह द्विपक्षीय साझेदारी आने वाले दिनों में नई ऊंचाई पर पहुंच सकती है। चीनी आक्रामकता और विस्तारवाद सहित कई मुद्दों पर दोनों सरकारों की सोच भी एक समान है। चूंकि ट्रंप प्रशासन चीन के विरुद्ध और आक्रामक रवैया अपनाएगा, तो इसे उपजने वाली स्थिति में उसे भारत की कहीं अधिक आवश्यकता होगी। हिंद-प्रशांत की सुरक्षा से लेकर आर्थिक हितों को लेकर भी सहमति बढ़ने के आसार हैं।

लड़कियों के शादी की उम्र 9 साल!

बाल विवाह की कुरीति को खत्म करने की कोशिश पूरी दुनिया में जारी है। कुछ हद तक इस पर काबू भी पा लिया है। हालांकि, अभी भी कई ऐसे देश हैं, जो लगातार बाल विवाह को कानूनी करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। दरअसल, हम बात कर रहे हैं ईराक की। यहां शादी के उम्र में संशोधन की पूरी तैयारी है। दावा किया जा रहा कि सरकार लड़कियों की शादी की उम्र में कमी करने जा रही है। ऐसे में पुरुष नौ साल की लड़की से विवाह कर सकेंगे।

अगर यहां यह संशोधन पारित हो जाता है तो विवाह की उम्र न केवल कम हो जाएगी बल्कि महिलाओं के लिए तलाक, बच्चों की कस्टडी और प्रॉपर्टी जैसे खास अधिकार भी प्रतिबंधित हो जाएंगे। इसके साथ यह विधेयक ईराक के नागरिकों को पारिवारिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए धार्मिक अधिकारियों या नागरिक न्यायपालिका को चुनने की भी अनुमति देगा। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक, पर्सनल स्टेटस लॉ 1959 के 188 नियम में बदलाव की बात हो रही है। पुराना नियम अब्दुल करीम कासिम सरकार ने बनाया था। कासिम की पहचान प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट के तौर पर थी, जिनके समय में कई बड़े बदलाव लाए गए। इनमें से एक था- 18 साल की उम्र होने पर ही लड़कियों की शादी। पचास के दशक के आखिर में पूरे मिडिल ईस्ट में इसे सबसे बढ़िया कानूनों में माना गया था। निश्चित उम्र में शादी ही नहीं, यह नियम कई और बातें भी करता था, जैसे पुरुष मनमर्जी के दूसरी शादी नहीं कर सकते।

लॉ के अनुसार, मुस्लिम पुरुष और गैर-मुस्लिम महिला अगर शादी करना चाहें तो इस पर कोई शर्त या प्री-कंडीशन नहीं रहेगी। हालांकि, जितना सुनाई दे रहा है, कानून उतना भी सीधा नहीं था। आबादी को खुश करने के लिए इसमें एक नियम यह भी डाल दिया गया कि शादियां 15 वर्ष की आयु में भी हो सकती हैं, अगर परिवार और जज की इजाजत हो। शिया इस्लामिस्ट पार्टियों ने मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार किया, जिसमें इस बदलाव की बात है। बता दें कि फिलहाल ईराक में मोहम्मद शिया अल-सुदानी की सरकार है, जो खुद एक शिया हैं और जिन्हें शिया पार्टियों का समर्थन मिला हुआ है। शिया-बहुल इस देश की सरकार में शिया पार्टियों की बड़ी भूमिका होती है और वे अक्सर बड़े फैसले लेते रहे। ईराक की शिया दलों के गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि यह संशोधन इस्लामिक शरिया कानून के तहत है और इसका उद्देश्य युवा लड़कियों की सुरक्षा करना है। खास बात यह है कि ईराक की सरकार ईराकी महिला समूह की ओर से लगातार किए जा रहे विरोध के बावजूद भी इस कानून को पारित करना चाहती है।

कानून में संशोधन करने के पहले भी प्रयास हो चुके हैं। हालांकि, पहली बार ऐसा लग रहा है कि कानून पारित करने में सांसद सफल हो सकते हैं। इससे पहले कानून में दूसरा संशोधन 16 सितंबर को पारित किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे कानून 188 नाम दिया गया। ये कानून ईराक के मूल रूप से रहने वाले सभी संप्रदाय के परिवारों के लिए समान रूप से लागू किया जाएगा। चैथम हाउस के वरिष्ठ अनुसंधान फेलो डॉ. रेनाड मंसूर के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया, यह अब तक का सबसे करीबी मुकाबला है। इसमें पहले से कहीं अधिक गति है, जिसका मुख्य कारण शिया पार्टियां हैं। हालांकि, यह सभी शिया पार्टियों की बात नहीं हैं, बल्कि केवल कुछ विशेष दल ही सशक्त हैं और वास्तव में इस पर जोर दे रहे हैं। धार्मिक पक्ष पर जोर देना उनके लिए कुछ वैचारिक वैधता हासिल करने का प्रयास करने का एक तरीका है जो पिछले कुछ वर्षों में कम हो रहा है।

यूनीसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईराक में युवतियों को अनैतिक संबंधों से बचाने के लिए कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है। यूनिसेफ के अनुसार, पूरे ईराक में बाल विवाह की उच्च दर पहले से ही प्रचलित है। लगभग 28 फीसदी ईराकी लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है और प्रस्तावित संशोधनों से स्थिति और खराब होने की आशंका है। विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह संशोधन महिलाओं, लड़कियों और ईराक के सामाजिक ताने-बाने पर हमला है, जो महिलाओं के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों को प्रभावी रूप से समाप्त कर देगा। ह्यूमन राइट्स वॉच की ईराक शोधकर्ता सारा सनबार ने कहा, संशोधन न केवल इन अधिकारों को कमजोर करेगा, बल्कि उन्हें मिटा भी देगा। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनी सलाहकार और मॉडल ने बताया कि उन्हें डर है कि ईराक की शासन प्रणाली को एक नई प्रणाली से बदल दिया जाएगा। यह वही प्रणाली है जो अफगानिस्तान और ईरान की शासन व्यवस्था का आधार है, जहां एक संरक्षक न्यायवादी देश के सर्वोच्च नेता के रूप में कार्य करता है।

● **कुमार विनोद**

ईराक में बहुत होते हैं बाल विवाह

ईराक में पहले से ही बाल विवाह की दर बहुत ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के अनुसार, ईराक में 28 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र तक हो जाती है। ऐसा व्यक्तिगत कानून में एक खामी के कारण है, जो अदालतों के बजाय धार्मिक नेताओं को हर साल हजारों विवाह संपन्न कराने की अनुमति देता है। इनमें पिता की अनुमति से 15 वर्ष की आयु तक की लड़कियों की शादियां भी शामिल हैं। ये अपंजीकृत विवाह ईराक के आर्थिक रूप से गरीब, अति-रूढ़िवादी शिया समुदायों में व्यापक रूप से प्रचलित हैं। चूंकि इन विवाहों को कानून द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए लड़कियों और उनके बच्चों को अनेक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, अस्पताल विवाह प्रमाण पत्र के बिना प्रसव के लिए महिलाओं को भर्ती करने से मना कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार, यह संशोधन इन धार्मिक विवाहों को वैध बना देगा, जिससे युवा लड़कियों को यौन और शारीरिक हिंसा का खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही उन्हें शिक्षा और रोजगार से भी वंचित किया जाएगा।

प्रकृति सर्वोपरि...

जनहित में जारी

आओ मिलकर
पर्यावरण बचाएं
हरियाली बढ़ाएं,
प्रदूषण दूर भगाएं

मेहता एंड एसोसिएट्स, इंदौर (मध्यप्रदेश)

खिताब बरकरार रख पाएगा भारत!

अपनी सरजमीं पर न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-3 से मिली शिकस्त के बाद भारत के लिए चर्चित टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया का सामना करने के लिए जिन खिलाड़ियों को चुना गया है उनका टेस्ट मैचों में प्रदर्शन कैसा है? भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का डिफेंडिंग चैम्पियन है तो वो उस खिताब को बरकरार रख पाने में कितना सक्षम है? इसका जवाब भारतीय खिलाड़ियों ने पहले टेस्ट में ही दे दिया है। लेकिन क्या पर्थ वाला प्रदर्शन आगे भी बरकरार रहेगा, यह साल उठ रहा है।

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ टेस्ट में चार दिनों के अंदर ही 295 रन से पटखनी दे दी। भारतीय टीम ने पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 534 रनों का टारगेट दिया था। टेस्ट क्रिकेट में आज तक कभी इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं हुआ। 534 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी दूसरी पारी में 238 रन पर ऑलआउट हो गई। भारत ने इस मैच को 295 रनों से जीत लिया। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 487/6 के स्कोर पर घोषित कर दी। इससे पहले टीम इंडिया पहली पारी में सिर्फ 150 रन ही बना पाई थी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 104 रन पर ढेर कर दिया था। टीम इंडिया को पहली पारी के आधार पर 46 रन की बढ़त मिली थी।

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराकर पर्थ में इतिहास रच दिया है। जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में टीम इंडिया ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024 के पहले टेस्ट मुकाबले में दमदार जीत हासिल की है। इससे पहले टीम इंडिया ने पर्थ में साल 2008 में अनिल कुंबले की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को 72 रनों से हराया था। भारत ने चौथे दिन चायकाल के बाद ऑस्ट्रेलिया को 238 रनों पर समेट दिया। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने 2015 के बाद से भारत को टेस्ट सीरीज में नहीं हराया है और अब एडिलेड, ब्रिसबेन, मेलबर्न और सिडनी में होने वाले बाकी मैचों में उसे ऐसा करने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला टेस्ट मुकाबला साल 1970 वाका क्रिकेट स्टेडियम में खेला था और इस स्टेडियम में ही अपना आखिरी टेस्ट मैच दिसंबर 2017 में खेला था। साल 2017 के बाद से वाका स्टेडियम की जगह ऑप्टस स्टेडियम में सभी मुकाबले खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला टेस्ट मुकाबला ऑप्टस में भारत के खिलाफ ही साल 2018 के दिसंबर में खेला था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 146 रनों से हराया था। अब साल 2024 में ऑप्टस स्टेडियम में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच ये दूसरा मुकाबला था जिसमें टीम इंडिया ने 295 रनों से ऐतिहासिक जीत हासिल की है।

पर्थ की जीत ने यह बता दिया है कि भारतीय टीम अपनी सरजमीं पर न्यूजीलैंड से मिली हार से उबर गई है। गौरतलब है कि हाल ही में अपनी सरजमीं पर न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-3 से मिली शिकस्त के बाद भारत के लिए चर्चित टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत अभी भी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के खिताबी मुकाबले तक पहुंच सकता है? इसके लिए भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के खिताब को बरकरार रख पाएगा?

खेल विश्लेषकों और पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों का कहना है कि दोनों ही टीमों के लिए यह सीरीज बेहद खास होने वाली है। भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया को पांच में से 4 मुकाबले हराने होंगे। जबकि ऑस्ट्रेलिया को भी यह सीरीज जीतनी होगी। ऐसे में दोनों ही टीमों के लिए यह सीरीज बेहद ही महत्वपूर्ण है। खासकर भारतीय टीम के लिए चर्चित टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के लिए सबसे बड़ी चुनौती एक तो ट्रॉफी को डिफेंड करना है और दूसरा विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में जगह बनाना है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल 2023-25 में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 4-0 से जीतनी होगी।

भारत इससे पहले दो बार डब्ल्यूटीसी फाइनल खेल चुका है और तीसरी बार इसमें पहुंचना बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन इस बार टीम को खुद को साबित करने की जरूरत है, क्योंकि दूसरे देशों के नतीजों पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। सीरीज जीतने का दबाव टीम इंडिया पर जरूर होगा, लेकिन उन्हें यह भी समझना होगा कि 4-0 से जीतना न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि इस पर फोकस करने से वे असली लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। खास बात यह है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इस बार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर खेली जानी है। ऐसे में इसका पता लगा लेना जरूरी हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का सामना करने के लिए जिन खिलाड़ियों को चुना गया है उनका वहां टेस्ट मैचों में प्रदर्शन कैसा है? भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का डिफेंडिंग चैम्पियन है। वो उस खिताब को बरकरार रख पाने में कितना सक्षम है। कौन से खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं इसका भी अंदाजा लग सकता है।

गौरतलब है कि इसी महीने भारत को अपने घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था। अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल रही है। भारत इस सीरीज को जीतकर इतिहास रच सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत लगातार दो बार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने में सफल रहा है। लेकिन इस दौरे से पहले भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने एक भविष्यवाणी के साथ ही टीम इंडिया को एक सख्त नसीहत भी दी है। गावस्कर का मानना है कि भारतीय टीम को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के बजाय बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज जीतने पर ध्यान देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि भारत ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हरा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह बड़ी उपलब्धि होगी। मुझे लगता है कि टीम को सिर्फ सीरीज जीतने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह 1-0 ही क्यों न हो। इससे टीम के प्रदर्शन में स्थिरता आएगी और क्रिकेट प्रेमी भी टीम पर गर्व कर सकेंगे।

● आशीष नेमा

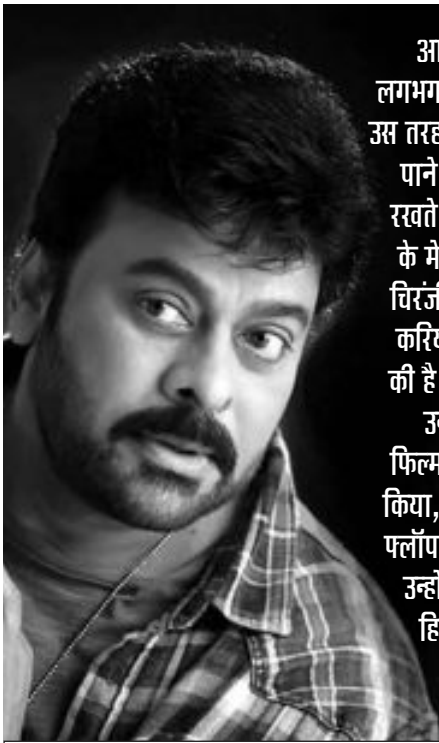

आज के दौर में लगभग सभी सितारे उस तरह की स्टारडम पाने की ख्वाहिश रखते हैं जो साउथ के मेगा सुपरस्टार चिरंजीवी ने अपने करियर में हासिल की है। बॉलीवुड में उन्होंने सिर्फ 3 फिल्मों में ही काम किया, लेकिन यहां फ्लॉप होने के बाद उन्होंने फिर कभी हिंदी फिल्मों में दोबारा काम नहीं किया।

बॉलीवुड का वो फ्लॉप हीरो... जिसने एक साथ दे डाली 14 हिट, फिर मिलने लगी थी अमिताभ बच्चन से ज्यादा फीस

भले ही बॉलीवुड में चिरंजीवी का जादू नहीं चला, लेकिन साउथ फिल्मों के वह मेगा सुपरस्टार कहलाए और 90 के दशक में तो फीस के मामले में उन्होंने अमिताभ बच्चन को जबरदस्त टक्कर भी दी। इसके बाद वह साउथ के सबसे महंगे एक्टर बने। बता दें, वह फिल्मों के साथ-साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं।

चिरंजीवी ने करीब 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। अपने बेहतरीन अभिनय के लिए उन्होंने 10 फिल्मफेयर अवॉर्ड और चार नंदी अवॉर्ड जीते। साल 2022 में हुए 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 90 के दशक में उन्होंने लगातार 14 हिट फिल्म कर साउथ फिल्मों में हलचल मचा दी थी। उस दौर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ वह सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक बन गए थे। खबरों की मानें तो उस समय उनकी फीस बॉलीवुड के दिग्गज स्टार अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा थी।

फीस के मामले में अमिताभ को पछाड़ा... *1992 के एक पुराने मैगजीन कवर ने बताया कि चिरंजीवी की कमाई अमिताभ बच्चन से ज्यादा है। 2019 में दोनों अभिनेता सईरा नरसिम्हा रेड्डी में एक साथ नजर आए, जिसने उनकी शानदार विरासत को और भी बढ़ा दिया। द वीक मैगजीन के 13 सितंबर, 1992 के अंक में स्पेशल रूप से दावा किया गया था कि अमिताभ अपनी फिल्मों के लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज करते थे, वहीं चिरंजीवी अपनी फिल्मों के लिए 1.25 करोड़ रुपए फीस लेते थे। 1990 का दशक चिरंजीवी के लिए खासतौर पर सुनहरा रहा, जिसमें कई कमर्शियल हिट फिल्मों ने टॉलीवुड के शिखर पर उनकी स्थिति को मजबूत किया।*

500 करोड़ी फिल्म देने वाली पहली हीरोइन, हर महीने की कमाई जानकर हो जाएंगे हैरान

आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे, जो आज साउथ सिनेमा की सुपरस्टार्स में से एक हैं। हीरोइन अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाती हैं और भारत की पहली हीरोइन हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए की फिल्म दी है। हम बात कर रहे हैं अनुष्का शेट्टी की। अनुष्का शेट्टी पिछले 19 सालों से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की सबसे भरोसेमंद लीड हीरोइनों में से एक हैं। उन्होंने साल 2005 में सुपर फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनुष्का शेट्टी ने अपने करियर में एक से एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। एक्ट्रेस की एक मूवी की आज भी बहुत ज्यादा चर्चा होती है और उसका नाम है बाहुबली: द कन्क्लूजन। यह साल 2015 में आई बाहुबली का सीक्वल था। कमाई के मामले में बाहुबली: द कन्क्लूजन ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। साथ ही बहुत खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। कई लोगों को नहीं पता होगा कि बाहुबली: द कन्क्लूजन के हिंदी वर्जन ने 500 करोड़ क्लब में एंट्री मारी थी और ऐसा करने वाली यह देश की पहली फिल्म साबित हुई। बाहुबली: द कन्क्लूजन ने दुनियाभर में 1700 करोड़ का टोटल बिजनेस किया था।

आर माधवन ने किया खुलासा... रहना है तेरे दिल में के फ्लॉप होने पर टूट गया था दिल

बॉलीवुड एक्टर आर माधवन की फिल्म हिसाब बराबर का 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में प्रीमियर हुआ। इस दौरान एक्टर ने अपनी आइकॉनिक मूवी रहना है तेरे दिल में को लेकर बात की। 25वीं एनिवर्सरी के मौके पर यह मूवी इस साल अगस्त महीने में दोबारा रिलीज हुई थी। इस फिल्म से आर माधवन और दीया मिर्जा ने बॉलीवुड डेब्यू किया था। हाल ही में आर माधवन ने बताया कि जब रहना है तेरे दिल में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी तो वह बुरी तरह टूट गए थे।

आर माधवन ने बताया कि जब फिल्म फ्लॉप हुई थी तो उनका दिल टूट गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें खुशी है कि यह फिल्म आखिरकार क्लासिक बन गई। अभिनेता ने बताया कि 25 साल बाद फिल्म का फिर से रिलीज होना और पहले से ज्यादा कमाई करना उन्हें बहुत अच्छा लगा। आर माधवन ने कहा, जब यह पहली बार रिलीज हुई तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और यह फ्लॉप हो गई। मुझे याद है कि मैं बहुत दुखी था। मैंने सभी मंदिरों में जाकर प्रार्थना की थी। फिल्म को सही तरीके से बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन यह दिल तोड़ने वाला था।

झोला छाप!

> *इस देश के आम आदमी की नजर में आदमी सबसे सस्ता है। उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की पूरी छूट है। ड्रिप चढ़ाने से लेकर ऑपरेशन, डिलीवरी, इंजेक्शन, एक्स-रे, रक्त आदि की जांच, अल्ट्रासाउंड आदि सब मामूली काम हैं। बस पैसे होने चाहिए। पैसे से मशीनें खरीदो और मुहूर्त कर लो।*

जब बिना वैध डिग्री प्राप्त किए ही गली-गली में डाक्टर साहब पुजने लगें तो कौन भकुआ किसी मैडिकल कालेज में आंखें फोड़ने और मोटी-मोटी रकम छोड़ने जाए! पढ़े-लिखे बड़ी पीएचडी और डीलिट् डिग्रीधारी प्रोफेसर मास्साब कहलाएं और झोलाछाप डाक्टर की पदवी से पूजे जाएं तो समाज की अज्ञानता और मूर्खता पर तरस आता है। किसी नामी गिरामी डाक्टर के यहां हुक्का भरते-भरते जिनकी जवानी चुक गई, वे अपना झोला लटकाए बड़े डाक्टर साहब की पदवी से सम्मानित किए जाएं। धन्य मेरे सांप-सपेरों वाले देश! जहां गुणियों का अपमान हो और निर्गुनिया गुणवंत कहे जाएं, उसका भगवान ही रखवाला है।

इस देश में मास्टरों की बड़ी लंबी कतार है। खास बात यही है कि सब एक ही पैमाने से नापे जाते हैं। एक ही डंडे से हांके जाते हैं। अब वह चाहे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का विद्वान प्रोफेसर हो या प्राइमरी स्कूल के मुंशी जी, उनकी नजर में सब मास्साब हैं। टेलर मास्टर, बैंड मास्टर, ट्यूशन मास्टर, कोचिंग मास्टर या प्रोफेसर सब मास्टर जी ही हैं। पांच वर्ष को चुने गए प्रधानजी आजीवन प्रधानजी हो जाते हैं, किंतु आजीवन इनकी कई-कई पीढ़ियों का गुरु और प्रोफेसर मास्टर के कद से ऊपर प्रोग्रेस नहीं कर पाता।

इस देश में झोलाछाप डाक्टर ही होते हैं। किंतु न डंडाछाप पुलिस थाना होता है न इंस्पेक्टर। न एसपी होते हैं न सीओ (सर्किल आफिसर)। झंडाछाप नेतागण अपवाद हैं। वे तो गल -गली, गांव-गांव और नगर-नगर मिल ही जाते हैं। देश की राजनीति के चांद चमकाते हैं। स्क्रू ड्राइवर छाप इंजीनियर भी नहीं देखे-सुने जाते। उन्हें किसी बड़े इंजीनियर की टांगों तले हुनर हासिल नहीं होते। उन्हें भी परिश्रम से पढ़ना और प्रेक्टिकल करना पड़ता है, तब बड़े इंजीनियर बनते हैं। यदि न्यायपालिका की बात करें तो जज, वकील, बैरिस्टर, दरबार ब्रांड अदालतें सब असली ही मिलेंगे। उन्हें भी कानून की किताब विधिवत पढ़नी, समझनी और गुननी पड़ती है। यहां चपरासी और चौकीदार के लिए भी प्राइमरी या जूनियर हाईस्कूल की सनद चाहिए ही चाहिए। किंतु झोले में इतने गुण हैं कि उसके लिए एमबीबीएस; बीएएमएस बीएचएमएस; एमएस; एमडी; डीएम कुछ भी आवश्यक नहीं हैं। यहां के अनुभवी दीर्घसूत्री बीमार दवाओं का सेवन करते-करते बड़े डाक्टर बन इलाज करने लगते हैं।

इस देश में पुलिस, शिक्षक, वकील, जज, इंजीनियर, अधिकारी, क्लर्क, स्टेनो, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि सबसे सस्ता यदि कोई है तो वह डाक्टर ही है। जिसने बड़े-बड़े डाक्टरों का काम हलका कर दिया है। आदमी की जान को सस्ते से भी सस्ता बना देने वाले ये झोलाछाप गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला, गांव-गांव, बस्ती-बस्ती में खोखा खोले हुए मिल जाएंगे। इस देश के आम आदमी की नजर में आदमी सबसे सस्ता है। उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की पूरी छूट है। ड्रिप चढ़ाने से लेकर ऑपरेशन, डिलीवरी, इंजेक्शन, एक्स-रे, रक्त आदि की जांच, अल्ट्रासाउंड आदि सब मामूली काम हैं। बस पैसे होने चाहिए। पैसे से मशीनें खरीदो और मुहूर्त कर लो। काला कोट पहनकर कोई नकली बस्ताधारी अधिवक्ता नहीं दिखा। डकैतों को छोड़कर पुलिस वेश में वर्दीधारी एसपी या दारोगा नहीं मिला। प्राइमरी पास प्रोफेसर की झलक नहीं मिली। बस डाक्टर ही डाक्टर। आदमी सबसे सस्ता है न! इलाज करते-करते दो चार मर भी गए तो क्या! रिश्वत देकर छूट ही जाना है!

झोलाछाप के झोले में टेबलेट, केप्स्यूल, सिरिंज, ड्रिप के साथ-साथ एक और चीज अनिवार्य है और वह चीज है चांदी का जूता। जब तक चले, चलाते रहो और जब पकड़े जाओ तो कस के मुंह पर मारो चांदी का जूता। इस जूते को सूंघने के बाद तो अच्छे-अच्छों का रॉब हिरन हो जाता है। झोलाओं के फलने-फूलने का यही एकमात्र कारण है। इस देश के किसी खास या आम आदमी से नैतिकता की उम्मीद करना चील के घोंसले में मांस खोजने के समान है। हां, नैतिकता का उपदेश देने वालों से रंगे सियारों की तरह पूरा देश पटा पड़ा है। लोग भागवत कराते हैं, पर करते कुछ भी नहीं। सुनता कोई नहीं, मानता कोई नहीं। सारा उपदेश परोपकार के लिए है, अपने लिए कुछ भी नहीं। लोग हैं ही इतने उपकारी। अपनी मां महतारी और दूसरे की लगे साली। जिस देश की नई और पुरानी पीढ़ी का चरित्र ही मर चुका हो, उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? सस्ते की मस्ती क्या कुछ न करवा दे! झोलाछापों के झोले में जिंदगी हरवा दे! उधर झोलाछापों को हलवा खिलवा दे। महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार-बार। नैतिकता और चरित्र सब बेकार।

● **डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'**

'सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा'

सड़क सुरक्षा से जुड़े कुछ नियम

- सड़क पर वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न करें।
- कार चलाते समय सीटबेल्ट जरूर पहनें।
- दोपहिया वाहन चलाते समय, हेलमेट जरूर पहनें।
- फुटपाथ पर सावधानी से चलें और जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करें।
- गति सीमा का ध्यान रखें।
- कभी भी शराब पीकर वाहन न चलाएं।
- दो-तरफ़ा सड़क पर बाईं ओर रहें।
- बाएं मुड़ते समय, जिस सड़क से आप निकल रहे हैं उसके बाईं ओर रहें और जिस सड़क से आप प्रवेश कर रहे हैं उसके बाईं ओर रहें।
- बस यात्रा करते समय, चलती बस में न तो चढ़ें और न ही उतरें।

मेहता एंड एसोसिएट्स, इंदौर (मध्यप्रदेश)

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_0/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687